हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 मार्च, 1985

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 26 मार्च, 1985

पृष्ठ संख्या

स्थगित तारांकित प्रश्न एंव उत्तर	(13) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(13) 8
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(13) 29
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव––	
फरीदाबाद में पत्थर की खानों में काम कर रहे मजदूरों की दयनीय स्थिति सम्बन्धी	(13) 38
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(13) 39
वर्ष 1985–86 के बजट की डिमांडज फार ग्रांट्स पर चर्चा तथा मतदान	(13)55
बैठक का समय बढ़ाना	(13)88
वर्ष 1985–86 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(13) 89

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 26 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल,

विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डिगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई ।

अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे ।

12–3– 85 को श्रीमती चन्द्रावती के सवाल नं० 807 के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्सटैशन मांगी थी ।

Therefore, we will first take up the list of postponed starred question

Spinning Mills Hansi

***807. Smt. Chandravati :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the expenditure incurred and income accrued to the Spinning Mills, Hansi, during the years 1980-81, 1981-82, 1982-83 and 1983-84;

(b) the details of items, including replacement and repair of machinery, on which the said expenditure has been incurred;

(c) the names and addresses of the firms front which the raw material and synthetic fibre except cotton used in spinning was purchased togetherwith the amount paid for the purchase of said material to each of the said firms during the years as referred to in part(a) above :

(d) the names of the persons who remained as Managers in the said mills during the years, as refined to in part(a) above; and

(e) the names of the Managers, if any, out of those referred to in part (d) above, as have left the service togetherwith the. reasons for their leaving the service ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क)	विवरण सुची सदन को पटल पर रखी जाती है ।	(अनुबंध 'क')
(ख)	विवरण सूची सदन के पटल पर रखी जाती है ।	(अनुबंध 'ख')
(न)	विवरण सूची सदन वो पटल पर रखी जाती है ।	(अनुबंध 'न')
(घ) तथा (ड)	विवरण सूची सदन के पटल पर रखी जानी है ।	(अनुबंध 'घ')

अनुबन्ध ''क' '

क्र० सं०	वर्ष	व्यय	आय
1	2	3	4
1	1980-81	5,45,52,420.41	4,30,57,946.64
2	1981-82	5,50,95,646.67.	4,01,46,142.58
3	1982-83	5,98,59,483.27	5,49,56,320. 72
4	1983-84	6,44,74,498.35	5,20,65,672.23

अनुबंध ''ख' '

वर्ष	खरीद कर–सहित कच्चे माल की खपत	निर्माण व्यय	मशीनरी बदलने तथा उसकी मरम्मत तर व्यय	प्रशासनिक तथा अन्य व्यय	विक्रय तथा वितरण व्यय	ब्याज	जोड
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	3,68,45,097.42	1,03,57,3(59.24	4,25,256.49	14,52,794.96	14,59,240.21	40,12,662.09	5,45,52,420
1981-82	3,51,41,566.91	99,01,580.28	5.45,869:08	15,91,924.11	12,59,702.44	66,55,003.85	5,50,95,646
1982-83	3,65,51,425.32	1,33,03,561.31	1,49,520.10	17,06,951.87	18,29,430.13	63,18,594.54	5,98,59,483

1983-84	4,19,94,937.47	'1,29,08,232.82	2,50,927.65	17,80,639.02	15,51,685.68	59,88,075.71	6,44,74,498

अनुबन्ध 'ग'

क्र ० सं ०	वर्ष	कच्चे माल का नाम	फर्म का नाम	अदा की गई राशि
1	2	3	4	5
1	1980– 81	रेयन	मैसर्ज कानेमासु गोले लि. ओसाका (जापान)	3, 99, 655. 38
2	1981 – 82	रेयेंन	मैसर्ज ईम्परेरा नैशनल दसालरिया, एस. ए, मदरीदे (स्पेन)	7,16,134.45
3	1982– 83	रेयन	–यथोपरि–	11,08,654.58

अनुबन्ध ''घ''

क्र. सं.	उन व्यक्तियों के नाम जो कताई मिल में बतौर मैनेजर रहे	उन मैनेजरों के नाम, यदि कोई है, जो कि कालम नं ० (2) में दर्शाये गए हैं? जिन्होंने सर्विस छोड़ दी है तथा उनके सर्विस छोड़ने के कारण क्या हैं

	उत्पादन मैनेजर		
1	श्री डब्ल्यू ० सी० कक्कड़ श्री एस ० के० चन्दा	6— 6— 78 से 25— 11— 80	त्याग पत्र
2	श्री के० बी० शर्मा	28— 11— 80 से 25— 7— 81	त्याग पत्र
3	श्री एस० के० चन्दा	17—7— 81 से 1 2— 10— 82	त्याग पत्र
4	श्री एस० के ० बंसल	14— 10—82 से 30— 8— 83	त्याग पत्र
5	कार्यवाहक उत्पादन मैनेजर	1— 9—83 से अब तक	
	कारखाना मैनेजर		
1	श्री आर० के० चौधरी	13— 7— 78 से 25—8—80	त्याग पत्र
2	श्री आर० एन० श्रीवास्तवा ए० ओ० कम—कारखाना	24—4—81 से जुनाई 81	त्याग पत्र

	मैनेजर		
3	श्री देश राज चौधरी	21— 5—82 से अब तक	

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि ये जो रेयन खरीदे गये हैं, वह डायरेक्ट खरीदे गये हैं, किसी अदायरे के दारा खरीदे गये हैं या किसी एजेन्ट के द्वारा खरीदे गये हैं और उनके नाम क्या हैं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, टैक्सटाईल कमिश्नर, भारत सरकार के आदेशानुसार ए ० आई० एफ० एफ ०सी ० ओ ० की मारफत सारी खरीद होती है । ये सारे देस की स्पिनिंग मिल्ज के लिये खरीद करते हैं और उसके बाद यार्न अलाट करते हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो घाटा दिखाया गया है, इसकी क्या वजह है? यह घाटा कहीं मैंनेजर्ज के त्याग पतों की वजह से तो नहीं हुआ है? दूसरे कुछ मैनेजर्ज थोड़ा समय ही रहे हैं । मेरी सूचना के अनुसार टोटल सात के करीब मैनेजर्ज बदले हैं । क्या घाटे के ये कारण तो नहीं हैं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि स्पिनिंग मिल, हांसी घाटे में है और उसके घाटे के कई कारण हें । अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन, चार, पांच सात्रों में

जितनी भी धागे की मिलें हैं, वे घाटे में रही हैं । दूसरी बात जहां तक बिजनैस का ताल्लुक है, मैं यह राय रखता हूं कि सरकार के जितने भी अदायरे हैं उनमें से कुछ को छोड़ कर, बाकी प्रोफिट में नहीं हैं । हांसी मिल में इस काम की जानकारी न होने के कारण ऐसा हुआ है । मैं तो इस राय का हूं कि इस किस्म के अदायरे सरकार की तरफ से लगने ही नहीं चाहियें । तजुरबे के बिना बिजनैस का काम नहीं हो सकता है, बड़ा टेढा–मेडा काम है लेकिन फिर भी हमारी चऊरी कोशिश है कि सरकार की तरफ से मिल ठीक तरह से चले और किसी न किसी तरीके से प्रोफिट में आ सके । इसके लिये हमने कई मैनेजर्ड भी बदले जो काम ठीक नही चला सके, उनकी जगह पर हमने काबिल आदमी वहां पर लगाने की कोशिश भी की है और करते भी हैं ताकि वे मल को अच्छे तरीके से चला सकें ।

श्री बीरेन्द्र सिह : स्पीकर साहब, अभी मुथ्य मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि वे इस राय के हैं कि पब्लिक सैक्टर में जो फैक्ट्रियां, और मिलें लगा रखी हैं, वे तकरीबन घाटे में हैं वे इस राय के हैं कि ये प्राईवेट हैक्टर में चली जानी चाहिये । इसको देखने हुए क्या सरकार कनकास्ट स्पिनिंग मिल, टेनरीज और मैच फैक–ट्री रह को प्राईवेट अदायरों के हाथों में देने का विचार रखती है?

चौधरी भजन लाल : ऐसा इरादा तो सरकार नहीं रखती लेकिन हमने भरमक कोशिश की है कि कि किसी तरीके से ये प्रोफिट में चल सकें । प्रोफिट में चलाने के लिये सरकार इन्हें जितना पैसा चाहिये देती भी है ताकि जो–जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके । हमने इसके लिये एक सब–कमेटी भी बनायी हुई है ताकि वह देखे कि इसमें सुधार कैसे आ सकता एं । अगर सूधार हो सकता है तो सुधार करना चाहिए । अगर नहीं, तो फिर यह कमेटी जो अपनी रिपोर्ट दे कि इनका क्या किया जाए, आगे लीज पर दिया जाए या टैन्डर इंवाईट करके इनको बेंच जाए, उसकी रिपोर्ट को हम एग्जामिन करेंगे । इस बारे में सब–कमेटी की रिपोर्ट हमें नहीं आई है । ज्यों ही सच–कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो सरकार उस पर अवश्य कार्यवाही करेगी ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या पिछले कुछ सालों में किसी अफसर के खिलाफ या उसकी इन–एफिशिएंसी के बारे में कोई चार्जिज सरकार के नोटिस में आए हें जिसकी वजह से ये मिल घाटे में चल रही है? अगर सरकार के नोटिस में ऐसी बातें आई हें तो सरकार ने उन पर क्या ऐक्शन लिया है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई ठोस शिकायत किसी अधिकारी के खिलाफ हमारे पास नहीं आई है । एक दो दरखास्तें किसी अधिकारी के खिलाफ किसी ने शिकायत के रूप में दी थीं, उसकी हमने जांच करवायी । लेकिन जब तक

कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तब तक कार्यवाही नहीं कर सकते, शिकायतें तो वकतन फवकतन आती रहती हैं ।

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने यह बताया कि शिकायतें बकतन कबकतन आती रहती हैं । पिछले सैशन के दौरान में भी वहां की बर्कर्ज यूनियन की काफी बातें प्रैस में आयी थीं और विधायकों को भी उसकी कापियां बांटी गई थीं । विधान सभा में इस बारे में सवाल आया था कि इस मिल में 1980– 81 से लेकर आज तक घाटा ही घाटा रहा, उससे पहले प्रोफिट में थी । बहुत सारी अनियमितताएं भी सामने आई । बोगस बिल्टी बनाकर माल को बेचते रहे हैं, इस बारे में लिखित रूप में एक मैमोरेन्डम भी सरकार के पास आया है । बया ये सारी बातें सरकार के नोटिस में हैं, सरकार इसका जवाब दे?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया कि इस तरह की शिकायतें वकतन फवकतनी आती रही हैं और उनकी जांच भी हमने करवायी है लेकिन कोई ठोस प्रमाण यानि सबूत नहीं मिल सके । इस लिये कोई ठोस कार्यवाही भी नही हो सकी लेकिन फिर भी जो अधिकारी ठीक नहीं थे, उनको चेंज किया गया और जिन मैनेजर्ज को तजुरबा था, काबिल थे, उनको लगाया गया क्योंकि इनकी इस काम में काफी जानकारी है, शायद वे जानकारी के आधार पर उस मिल के काम काज को ठीक चला सके ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, मुख्य मन्दी जी ने अभी एक सब–कमेटी का जिक्र किया है । क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह कमेटी कब बनी और उसके कौन–कौन मैम्बर्ज हैं? क्या टर्म्ज आफ रैफरैन्स में यह दिया हुआ है कि यह कमेटी फलां तारीख तक अपनी रिपोर्ट दे देगी? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि पानीपत में छोटी–छोटी प्राईवेट मिलें, दो–दो, चार–चार लाख के सरमाने की हैं और वे दो–दो, तीन–तीन लाख रुपया सारन में कमाती हैं । क्या कारण है कि इतना ज्यादा सरमाया लगाकर के सरकार की मिलें घाटे में जा रही है जबकि प्राईवेट सैक्टर में जो मिलें हैं, वे काफी फायदे में जा रही हैं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने दो सवाल पूछे हैं एक तो यह कि इस सब–कमेटी के कौन–कौन मैम्बर्ज हैं और यह कब की बनी हुई है । स्पीकर साहब, यह कमेटी बने लगभग 6 महीने हो गये हैं । चौधरी शमशेर सिंह बिजली एवं सिंचाई मन्त्री इसके चेयरमैन हैं, वित्त मन्त्री, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, फाइनैन्स सचिव और इंडस्ट्रीज सचिव इस कमेटी के मैम्बर्ज हैं । यह कमेटी एक–एक बात की तह में जाकर देखेगी कि इन मिलों का सुधार कैसे हो सकता एं । दूसरी बात न्होंने कही कि पब्लिक सैक्टर में मिलें काफी घाटे में जा रही हैं जबकि प्राईवेट मिलों वाले पैसे कमा रहे हैं । इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि तकरीबन तीन–चार वालों से पब्लिक सैक्टर में

मिलें घाटे में चल रही हैं और यह नातजुर्बे और नासमझी के कारण ही ऐसा हुआ पैं ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि इसके लिये एक सब–कमेटी बनी हुई है जो इनकी वर्किंग को एग्जामिन करेगी और उसकी रिपोर्ट के ऊपर हम विचार करेंगे । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सब–कमेटी के अन्दर हरियाणा का जो बैस्ट स्पिनिंग किस्त का एक्सपर्ट हो. उसकी असिस्टैन्स लेगी, उसकी राय लेगी ताकि वह सरकार को इस बारे में ठीक रास्ता दिखा सके कि यह मिल प्रोफिट में कैसे आ सकती है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जितनी हमारी दूसरी पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज हैं, क्या उन सब के वर्किंग को भी एक एक्सपर्टस की कमेटी बना करके एग्जामिन करवाने का सरकार विचार रखती हे?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जितने हमारे अदायरे हैं उन सब के लिये हमारी एक सब–कमेटी बनी हुई हए । भाई सुरेन्द्र जी का सुझाव बहुत अच्छा है 'कि जो एक्सपर्ट हैं, उन से इस तरह के सुझाव लेने चाहियें, पूछना चाहिये कि इस मिल में क्या कमी है और किस तरीके से इस कमी को दूर किया जा सकता है । आया यह मिल प्रोफिट में आ सकती है या नहीं? जो सब–कमेटी बनी हुई है, वह खारी बातों की तह में जाएगी और उडके बाद ही हम कुछ निर्णय लेंगे ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

S.Y.L. Canal

***819. Prof. Sampat Singh and Seth Ram Dass Dhamija and Chaudhri Kundan Lal and Shri Hari Chand Hooda** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date-wise amount paid by the Haryana Government to the Punjab Government/Government of India for the construction of S.Y.L. Canal in the Punjab Territory, during the period from 21-10-1982 to-date;

(b) the total length of the said canal so far constructed in the Punjab Territory ;

(c) the break-up of the amount so far spent, out of the amount paid by the Haryana Government to the Punjab Government/ Government of India, on staff, for acquisition of land and for the purchase of machinery separately ; and

(d) the time by which construction of the portion of the said canal, falling in the Punjab Territory, is likely to be completed ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) The date-wise amount paid to the Punjab Government from 21-10-82 to-date for the construction of SYL Canal in Punjab Territory is as under :—

	Rupees in Crores
Paid through Govt. of India in 2/84	5.00
Paid through Govt. of India in 5/84	5.00
Paid through Govt. of India in 9/84	5.00
Paid by Haryana. Govt, in 11/84	5.00
Paid by Haryana Govt. on 6/3/85	5.00
	25.00

(b) Canal excavation has been started in 50 Km, length.

(c) The break-up of the amount so far spent under the following Sub-heads, is as under :—

		Rupees in crores
(i)	Staff	12.50
(ii)	Acquisition of Land	6.00
(iii)	Purchase of Machinery	4.00

(d) The project is scheduled for completion by June, 1987.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, 21— 10—82 के बाद दो सालों में न्होंने यह नहर पूरी करनी थी लेकिन 21— 10— 82

से जनवरी, 1984 तक इन्होंने इस नहर के लिए कोई पैसा नहीं दिया । जब इन्होंने कोई पैसा ही नहीं दिया तो ये नहर बनाने की उम्मीद कैसे करते थे? जो 25 करोड़ रुपया इन्हेंने आज तक दिया है उसमें से साढ़े बाईस करोड़ रुपया उन्होंने मशीनरी, जमीन लेने और स्टाफ पर खर्च कर दिया है लेकिन कह रहे हैं कि नहर पर काम चल रहा है । जितना पैसा दिया था वह तो लगभग सारा खर्च हो चुका है तो फिर काम कैसे चल रहा है? मैंने यह भी पूछा था कि यह नहर कितनी बन गई है उसके जवाब में इन्होंने सिर्फ खुदाई बताई है । इसका मतलब है कि नहर अभी तक बिल्कुल भी नहीं बनी है । अगर बनी है तो मन्त्री महोदय बताएं कि कितनी बनी है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इन्होंने कई सवाल इकटठे कर दिए । जितने सवाल मेरे याद रहेंगे, उनका जवार देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा । पहला सवाल इनका यह था कि हमने 1982 से जनवरी, 1984 तक कोई पैसा नहीं दिया और अब तक कुल 25 करोड़ रुपया दिया है । स्पीकर साहब, असल में अब तक हरियाणा सरकार 48 करोड़ रुपए के करीब दे चुकी है । 23 करोड रुपया 1984 से पहले दे दिया था । इसके लिये 77 लाख रूपए के करीब पंजाब सरकार ने दिया है । बाकी का शेयर उन्होंने नहीं दिया है जिसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं । यह रुपया उन्होंने क्यों नहीं दिया इसके बारे में सारे हाउस को पता है । हमने 1982 के बाद जब 1984 में उनको पैसा

देना शुरू किया, उस वक्त तक पंजाब सरकार ने एस० कई एल ० की बहुत बड़ी आर्गेनाइजेशन बना ली थी लेकिन मौके पर कोई काम शुरू नहीं किया था और लैड एक्वीजीशन की पेमैंट भी नहीं की । इसलिये हमने पेमैंट स्टाप कर दी थी । हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया से प्रोटैस्ट किया कि जब तक हमारा रूपया डिगिंग पर खर्च नहीं होता उतनी देर तक हम इतने हैवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं थे सकते हैं । उसके बाद गवर्नमैंट आफ इंडिया ने डायरैक्ट पैसा देना शुरू किया और उसके बाद से काम. प्रौग्रैस में है ।

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, सदन में एस० वाई० एल० पर बहुत चर्चा हो चुकी है । सबको पता है कि पंजाब सरकार पूरे मन से इसको बनाना नहीं चाहती । इतने पैसे में से अब तक लैड एक्व जिशन पर केवल. 6 करोड रुपया पंजाब वालों ने खर्च किया है । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को सिफारिश करने का विचार किया है कि भारत सरकार इस काम को अपने हाथ में ले ले ताकि एस० वाई० एल० जल्दी. तैयार हो जांए?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, गवर्नमैंट आफ इंडिया के लैवल पर सारो पौसिबिल्टीज एग्जामिन हुई कि आया इस नहर को कंस्ट्रक्ट करने की पंजाब की जिम्मेदारी है या कोई और एजेंसी यह काम कर सकती है या हरियाणा खुद इसे बना सकता है या कोई सैंट्रल एजैंसी बना

सकती है । पूरे पोस एंड कौन्ज देखने के बाद गवर्नमैंट आफ इंडिया इस नतीजे पर पंहुची कि इसे पंजाब ही बनाएगा । इसमें हरियाणा का कोई स्टाफ का आदमी नहीं था लेकिन इसकी मौनिट्रिंग गवर्नमैंट आफ इंडिया के वाटर एंड पावर कमिशन के मैम्बर जो सैक्रेटरी इरीगेशन भी हैं, वे कर रहे हैं । चण्डीगढ में भी इस बारे में फरवरी, 1985 में मीटिंग हुई है । जहां तक काम का सवाल है कि कितना हो चुका है इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हू कि 50 किलोमीटर की लैग्थ में अर्थ वर्क पर काम चालू है । कई जगह काम काफी एडवांस स्टेज पर है । इसके साथ–साथ क्उछ पोरशन में लाइनिंग का काग भी शुरू हो चुका है । कुछ जो जरूरी काम हैं, वे एप्रूव हो चुके हैं । मेजर वर्कस के 9 टेंडर फाडनेलाइज हो चुके हैं । जरूरी कामों में क्रास ड्रेनेज के काम हैं । जैसे सिरसा और गुड़की हैं वे दोनों काम एप्रूव हो चुके हैं और सिरसा एक्वाडेक्ट का काम शुरू हो चुका है । इसके अलावा अलोवाल, खडौता, पारीवार, बिखेडा और माजरी के क्रास ड़ेन वर्कस भी शुरू हो चुके है । इसी प्रकार से जो बाकी स्ट्रकचर है उनका काम भी अलौट हो चुका है । यानी इस वक्त काम तसल्लीबख्श चरन रहा है ।

चौधरी कुन्दन लाल : स्पीकर साहब, उग्रवादियों की वजह से और अकाली पार्टी की वजह से इस नहर की खुदाई में रुकावट आई है और हरियाणा की खेती– बाड़ी को जब्रदस्त घाटा

पड़ा है । क्या हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से इस घाटे की पूर्ति के लिए कोई मांग की है अगर नहीं की तौ कब करेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार चाहती हे कि यह काम जल्दी मुकम्मल हो जाए । लेकिन फाइनैंसिज की बड़ी दिक्कत है और हरियाणा डेढ़ दो साल में इसके लिये प्रे साधन नहीं जुटा सकता है । इसलिये हमने भारत सरकार से दर्खवास्ते की है कि वह हमें 30– 40 करोड़ रुपया एडवांस दे दे । जब नहर पूरी हो जाएगी तो उसके दो साल बाद हम उन्हें यह रकम किश्तों में वापिस कर देंगे । यह हमारी रिक्वैस्ट' अंडर कसिडेरशन, पैंडिंग पड़ी है । मुख्य मन्त्री जी ने प्रधान मन्त्री जी से इस बारे में मुलाकात भी की है और पल भी लिखे हैं । हमें उम्मीद है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया हमारी मदद जरूरी करेगी ।

श्री हरि चन्द हुड्डा : स्पीकर साहब, जभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि रुपए की कमी है । यह इनकी बात ठीक है लेकिन एस ० वाई० एल ० जो हरियाणा में खोदी गई और उस पर इतना रुपया खर्च किया गया, अगर वह रुपया नाथपा– झाकडी प्रोजैक्ट में लगा देते तो बिजली आ जाती और इस नहर को हम बाद में बना लेते । यह काम थोड़ी अकल की कमी की वजह से हुआ है । (शोर) 31 दिसम्बर 1981 को इस प्रोजैक्ट के लिए 2०5 करोड़ रुपए लगाने का आधार माना गया था । लेकिन उसमें एक लाकूना था यानी पंजाब वालों ने यह किया कि रावी और व्यास के

पानी का जब तक फैसला न हो तब तक हम इसे सिरे नहीं चढ़ने देंगे । यह लाकूना गवर्नमैंट के नोटिस में होते हुए भी इन्होंने हरियाणा में इस पर काम शुरू कर दिया । दूसरे जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए और केस को विद्ड्रा किया उसके बाद हमें यह भी उम्मीद है कि इस मामले को दोबारा कोर्ट को रैफर करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए ।

श्री हरि चन्द हुडडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से एस ० वाई० एल० का मामला हौच पोच में है, क्या उसी तरह से यह गवर्नमैंट भी हौच पौच है? (शोर)

Mr Speaker : This is no question. We are becoming unserious every day. We should be serious. This is House after all. This is not a 'panchayat adaira'.

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि एस० वाई० एल० कैनाल की कंस्ट्रक्शन पंजाब सरकार ही करेगी । उनकी यह बात बिल्कुल ठीक है और यह तयशुदा बात है कि उसकी कंस्ट्रक्शन पंजाब सरकार ही करेगी । यह बात भी ठीक है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया पंजाब सरकार की इस बात को सैद्धांतिक तौर पर नहीं मानती कि हरियाणा गवर्नमैंट का कोई आफिसर इसमें इन्वाल्व हो । मैं आपके द्वारा मती महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन बातों के बावजूद भी क्या सरकार ने यह तहकीकात की है कि आया मौके पर मैटीरियल ठीक है, काम तसल्लीबख्श हो रहा है और पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है?

क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि हमारे कुछ आफिसर्ज, जैसे आप कहते हैं कि वे आफ दि रिकार्ड इसकी सुपरविजन करते रहे हैं, भविष्य में भी वे सुपरविजन करते रहेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैंने इस बारे में पहले भी अर्ज किया है कि गवर्नमैंट आफ इडिया के सी० डब्ल्यू० सी० के मैम्बर और इरीगेशन सैक्रेटरी इसकी मोनिटरिंग करते हैं और उनके साथ बाकायदा पंजाब और हरियाणा के सीनियर आफिसर्ज बैठते हैं । एक एक आइटम को क्रिटीकली एग्जामिन करते हैं । जो काम हो चुके हैं उनको भी एग्जामिन करते हैं और जो काम होना है उसको भी एग्जामिन करते हैं । डिजाईन को भी एग्जामिन करते हैं और खर्चे को भी एग्जामिन करते हैं । बाकी इनकी यह बात रह गई कि हम आफ दि रिकार्ड क्या करवाते हैं । क्या मैम्बर साहेबान यह समझते हैं कि आफ दि रिकार्ड जो हम करवाते है, वह बताना ठीक होगा । मैं समझता हूं कि वह बताना ठीक नहीं होगा ।

डा ० भीम सिह दहिया : स्पीकर साहब, मेन सवाल के जवाब में एस० वाई० एल० कैनाल के खर्चे के बारे में ब्रेक–अप दी है । उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने पं जाब सरकार को 25 करोड़ रुपए दिए हैं जिसमें से फिफ्टी परसैंट पैसा यानी 12.50 करोड़ रुपया स्टाफ पर खर्च हो गया और वह स्टाफ भी खाली टैक्नीकल एडवाइस और सुपरविजन के लिए है असल में नहर तो कडैक्टर ने बनानी है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना

चाहूंगा कि क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि वहां पर ओवर स्टाफ है और केवल तनख्वाह देने में ही काफी पैसा जाया हुआ है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, 25 करोड़ रुपए में से 12.50 करोड रुपए नहीं हैं । माननीय सदस्य की समझने में थोड़ी सी कमी रह गई है । यह 48.50 करोड रुपए में से 12.50 करोड़ रुपए का स्टाफ पर खर्च हुआ है । आपने जो सवाल पूछा था वह अक्तूबर 1982 रो गाय तक का खर्चा पूछा था और हमने जो खर्चा बताया है वह टोटल बता दिया है । अगर दोनों चीजों को आप आपस में मिला कर पडेंगे तो आपको गलत महसूस होगा । यह खर्चा 48.50 करोड़ रुपए में से है । यह खर्चा 1977 से आज तक हुआ है । मैं यह मानता हूं कि जो स्टाफ पर 12.50 करोड़ रूपए खर्च हुए है, यह बहुत ज्यादा खर्च हुहु हैं । इसके बारे मैं हमने प्रोटैस्ट भी किया है यह मामला भारत सरकार के पास पेंडिंग है । हमारा कहना हए कि इस आर्गेनाइजेशन पर यह खर्चा उस समय में हुआ है जिस समय इतना काम नहर को बनाने में नहीं छुआ, इसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है । अभी ये सारी एडहाक बातें हैं इस पर फैसला हो सकता है । अल्टीमेटली यह फैसला भी हो सकता है कि इस खर्चे में से कुछ खर्चा जो गैर जरूरी है, वह इसमें न डालें । लेकिन अभी तक जो खर्चा हुआ है, अगर मैम्बर साहेबान दिलचस्पी रखते हैं तो उसकी ब्रेक–अप मैं बता सकता हूं । वह इस प्रकार है । अभी 18 करोड़

रुपए की अदर लायबिलिटी है उसमें से 10 करोड़ रुपए की लायबिलिटी तो आलरेडी अर्थ वर्क की एग्जीक्यूट हो चुकी है, तीन करोड रुपए कम्पनसेशन के लिए रिजर्व रखे हुए हैं और 5 करोड़ रुपए मशीनरी मोबेलाइजेशन के लिए एडवांस किए हुए हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब स्पीकर साहब, अखबारों में भी इस बात का काफी जिक्र आया था कि वहां पर बहुत ज्यादा ओवर स्टाफ है । वहां पर पंजाब वालों ने हरियाणा की कास्ट पर एस. ई. से डायरैक्ट चीफ इंजीनियर बना दिए हैं । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो ओवर स्टाफिंग के कारण ज्यादा खर्च हुआ हए, क्या यह सरकार पंजाब सरकार से वह पैसा वापिस लेगी और उन लोगों को जो हरियाणा की कास्ट पर सर्विस में लगे हुए हैं, हटाने के लिए कोई विचार करेगी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, जैसे पहले एक माननीय सदस्य भै यह कहा था कि दो साल तक कोई पैसा इस नहर के लिए नहीं दिया गया । इस बारे में मैंने बता दिया था । एग्जैक्टली यही कारण था कि जो टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन, व्हीकल्ज, दफ्तर और इतने चीफ इंजीनियर्ज लगा रखे थे इसके लिए हमने मना कर दिया था । हमने कहा कि जब तक आप इस सारे स्टाफ को कम नही करेंगे इनको कट टू दि साइज नहीं करेंगे तब तक हम आपको पेमैंट नहीं देगे । उसके बाद उन्होंने स्टाक रिंडयूस किया और अब वहां पर बहुत कम स्टाफ है । यह बात उस पीरियड की है जिस पीरियड में काम तो

हुआ नहीं और उन्होंने बहुत बड़ी आर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली थी । इस बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यह जो 12. 50 करोड़ रुपए स्टाफ का खर्चा है इसको हम मानते नहीं हैं यह सारा खर्चा हम पर नही पड़ना चाहिए । इस बारे में मामला भारत सरकार के पास पैंडिंग है । '

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने मेन सवाल के जवाब में बताया है कि "Canal excavation has been started in 50 Km. length." लेकिन सवाल में यह पूछा गया था कि आपने काम कम्पलीट कहां तक कर लिया है एक्सकावेशन तो खुदाई बाली बात है । स्पीकर साहब, मैं आपके कैटेगोरीकली मत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इतना पैसा बरबाद करने के बाद कितना काम पूरा हो चुका है? इसके अलावा मती जी ने यह कहा कि मुख्य नन्ही जी बड़े जोर शोर से गवर्नमैंट आफ इंडिया पर दबाव डाल पे हैं कि वह हमें इस काम के लिए 30– 40 करोड़ रूपया एडवांस के रूप में दे । मैं यह जानना चाहूंगा कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने मुख्य मन्त्री जी की बात को कहां तक माना है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, जो काम हुआ एं उसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को बार–बार बता चुका हूं कि 50 किलोमीटर का अर्थ वर्क जारी है बाकी मे जर वर्क का काम डिफरैंट स्टेजिज पर जारी है । मैंने नाम लेकर भी बता दिया है । लाईनिंग का काम भी 10– 11 किलोमीटर में रैडी है इसके अलावा और कुछ पोर्शन में भी शायद लाइनिंग का काग

स्टार्ट हो चुका है । मैं लैंड इक्विजीशन के बारे में भी बता देता हूं कि 2091.41 एकड जमीन एक्वायर हो चुकी है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, क्या मैली जी हमें अपने साथ ले जाकर दिखाएगे कि वहां पर 50 किलोमीटर में काम हुआ है? यदि दिखा देंगे तो हम सैटिस्फाई हो जाएगे ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य अपने आपको बच्चे क्यों समझते हैं । क्या मैं इनकी ऊंगली पकड़ कर दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा । वह जगह यहां से लगभग 20 या 30 किलोमीटर है, ये खुद भी जा सकते हैं । वैसे मुझे इनके साथ जाने में कोई एतराज नहीं है ।

श्री मंगल सैंन : स्पीकर साहब, इनका ऐसा सरकास्टीकली जवाब है कि हम बच्चे नहीं हैं । मैं कहूंगा कि ये भी कोई ऐसे बूढ़े नहीं हैं जो हमको अपने साथ नहीं ले जा सकते । यदि हम इनके साथ जाएंगे तो क्या इनका कुछ बिगड़ जाएगा । स्पीकर साहब इनको ओफर करनी चाहिए और हमें सारी फैसीलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिएं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं । मैं आपके साथ वहां पर चलूंगा ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने ओप्टिमिस्टिक व्यू दिया है कि 1987 तक एस ० वाई० एल ० कैनाल कम्पलीट हो जाएगी । बजट दोनों सरकारों के आ चुके हैं

। यानि भारत सरकार का भी और हरियाणा सरकार का भी बजट आ चुका है और इस काम पर 200 करोड़ रुपए खर्च होने हैं । इसमें से हरियाणा सरकार को 70 करोड रूपया भारत सरकार से मिल जाएगा, 48 करोड़ रुपया अभी तक दिया है । मैं आपके द्वारा मती जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने इस अगले साल में इस नहर की खुदाई के लिए इस बजट में अपने रिसोर्सिज से प्रोविजन रखा' है? अगर भारत सरकार से पैसा नहीं मिला जैसे कि उन्होंने दूसरी स्टेटस को नहीं दिया, ऐसा हुआ है आप सभी जानते हैं, तो क्या आप रुपए का अरेंजमैंट कर पाएंगे? किस आधार पर इनका ओप्टिमिस्टिक व्यू' है? सरकार कौन से यकीन के साथ यह कहती है कि 1987 तक यह नहर बन कर कम्पलीट हो जाएगी? पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार से 39 करोड़ रुपया मांगा है वह इनके पास है नहीं । तीन महीने हो गए हैं इन्होंने उनको एक भी पैसा नहीं दिया । वे रोजाना कहते हैं कि अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम नहर कैसे बनाएंगे । मैंने वह सारा एरिया देखा है । जो वहां पर डिगिंग हुई है वह बरसात में सारी वह जाएगी, वह सारी की सारी हट जाएगी फिर दोबारा नहर खोदनी पड़ेगी । मैं यही पूछना चाहता हूं कि सरकार कौन से अरेंजमैंट करेगी जिनसे 1987 तक यह नहर कम्पलीट हो जाएगी । आपके पास रिसोर्सिज क्या हैं जिनसे उनको फीड करेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कह दिया कि तीन महीने हो गए हैं हमने पंजाब वालों को' कोई पैसा नहों दिया है । स्पीकर साहब, हमने उनको 5 करोड़ रुपया तो तीसरे महीने में दिया है और इससे पहले भी दिया है और लगभग 10 करोड़ रुपए पंजाब सरकार की अपनी लायबिलिटी बनती है । फाइव टू वन रेशो से शेयर उनका भी बनता है । इसी रेशो के हिसाब से खर्चा बनता है । पंजाब सरकार ने अब तक केवल 70 लाख रुपए दिए हैं, एक करोड़ से कम दिए हैं । अगर अपोजीशन के माननीय सदस्य एनक्रेज करेंगे कि वह पैसा न दें और ऐसी पिक्चर ये पेंट करेंगे कि हरियाणा के लोग, हरियाणा के नुमायदे इस बारे में इकट्ठे नहीं हैं, डिवाइडिड हैं तो शायद पंजाब वाले पैसा न दें । अगर इस हाउस से यह राय जाएगी कि हम इस बारे में इकट्ठे नहीं हैं तो वह पैसा क्यों देंगे । वे पैसा नहीं देंगे और न ही नहर बनाएंगे । इसलिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए । अदरवाइज तो कोई वजह नहीं है कि 1987 तक वह नहर पूरी न हो । इसी 1985–8 8 के बजट में गवर्नमैंट आफ इंडिया से 70 करोड़ रूपया हमें मिलेगा और हम भी अपने उपायों से पैसे का प्राबाधान करेंगे । पिछले साल जबकि इसके लिए पैसा नहीं था उसके बावजूद भी हमने इन्टरनल रिसोर्सिज से पंजाब वालों को पैसा दिया । यह सरकार इस काम को प्राथमिकता देती है । दूसरे सारे खर्चो को काट कर सरकार इस काम को पूरा करने में प्राथमिकता देती है । सरकार इस बारे में अपनी तरफ से सीरियस है । आप्टिमिस्टिक की कोई बात नहीं

है । हम वास्तव में यह समझते हैं कि नहर इतने समय में कम्पलीट हो जाएगी और शायद इससे पहले भी पूरी हो जाए । लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि वे हरियाणा के हितों को दिल से लगा कर रखें और सरकार की मुखालफित न करें और जुबान से असैम्बली में या असैम्बली से बाहर ऐसी कोई बात न कहें जिससे हरियाणा के हितों को नुकसान हो । (विध्न)

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, अमी इन्होंने यह कहा है कि अपोजीशन के लोग हित नहीं रखते । मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इस मामले में हम इनसे ज्वादा हित रखते हैं । (विध्न)

श्री निहाल सिंह : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिवाइज्ड एस्टिमेटस के हिसाब से इस कैनाल के पूरा होने पर कितना खर्च आएगा और दूसरे लैण्ड इक्वीजिशन का जो 6 करोड़ रुपया दिया जा चुका है इसके अलावा और कितना रुपया देना बाकी रहता है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इस कैनाल पर टोटल कौस्ट पौने दो सौ करोड़ रुपये होगी । इस पैसे में से 130 करोड़ रुपया हरियाणा को देना होगा और बाकी पैसा पंजाब खुद देगा । लैण्ड इक्वीजिशन के लिए हमने तीन करोड़ रुपए रखे हुए हैं । अमी बीच में पैसे को थोड़ी सी

फाईनेलाईजेशन होनी है, इसके लिए रुपया हमने रिजर्व में रखा हुआ है ।

श्री लछमन सिंह कम्बोज : स्पीकर साहब, आयगर कम्पनी और करतार सिंह जालन्धर के ठेकेदार ने इस नहर पर लैमन गांव से ऊंची बस्ती तक काम शुरू किया हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों ठेकेदारों को कितने रुपए में ठेका दिया गया है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : ठेके पर काम पंजाब सरकार करवा रही है, हम नहीं करवा रहे । इसलिए मुझे मालूम नहीं कि इनको कितने में ठेका दिया हुआ है ।

श्री एस ० सी ० चौधरी : स्पीकर साहब, सरकार द्वारा फिग्गरे दी गई है कि 5 छ किलो मीटर लम्बी नहर की खुदाई का काम जोरों पर है । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अब बारिश आने में सिर्फ तीन महीने रह गए हैं । सरकार को चाहिए कि बारिश होने से पहले–पहले जो भी खुदाई हो उसमें लाइनिंग करके उस्को बारिश में बह जाने से बचाया जाए । यदि खुदे। हुई नहर की लाइनिंग नहीं होगी तो बारिश आने पर सारी खुदाई बेकार चली जाएगी । मैं मती जी से जानना चाहता हूं– कि क्या खुदाई का काम रोक कर पहले लाईनिंग का काम किया जायेगा ताकि खुदी हुई नहर को बचाया जा सके?

Mr. Speaker : Do you think that whatever ycu have

asked is in **the** control of the Irrigation Minister ?

श्री ए ० सी० चौधरी सर, मैं इरीगेशन मिनिस्टर नहीं कह रहा । मैं तो सरकार की बात कर रहा हूं । (विघ्न)

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, सरकार इस मामले में पूरी तरह से जागरूक है । हमने यह मामला पिछली मिटिंग में भी उठाया था कि जिस पोरशन पर अर्थ वर्क कम्पलीट हो चुका है उसमें लाईनिंग बारिश से पहले पहले हो जाये । सरकार अपनी तरफ से पहले ही इस मामले में पूरी तरह से जागरूक है ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, हमारी साथ लगती स्टेट में एक आन्दोलन रीजनल फोर्सिज से और कम्युनल फोर्सिज से जोर पकड़ रहा हे । इस आन्दोलन की वजह से बहुत सारी समस्याएं उठ खडी हैं । सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लिए एस ०वाई०एल० की है । इस आन्दोलन की वजह से ही यह नहर पूरी नहीं हो रही । हमारे साथ लगते प्रान्त में कुछ फिरका परस्त लोगों की वजह से इस काम में रुकावट बनी हुई है । इस समय यह खुशकिस्मती की बात है कि साथ लगते प्रान्त की बागडोर ऐसे हालात में सैडल सरकार के हाथ में है ।. क्या इस स्थिति का फायदा उठाते हुए हरियाणा सरकार इस एस ०वाई०एल ० नहर की खुदाई का केस सैन्ट्रल गवर्नमैंट को रैफर करने के लिए कोई सिफारिश भेजेगी कि यदि इस नहर का निर्माण कार्य सैन्ट्रल

सरकार अपने हाथ में ले लेती है तो यह नहर जल्दी पूरी हो सकती है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं पहले भी बता चुका हूं और अब फिर रिपीट कर देता हूं कि यह काम स्टेट गवर्नमैंट के लैवल का है । स्टेट के कामों में सैन्ट्रल सरकार बीच में नहीं आती । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह स्टेट गवर्नमैंट का ही काम है इसमें सैन्ट्रल गवर्नमैंट कोई फैसला नही कर सकती ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, सैन्ट्रल गवर्नमैंट इस बारे में फैसला अपने लैवल पर कर सकती है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, सैन्ट्रल सरकार केवल उन्हीं प्रौजैक्टस को सी स्टेट में अपने लैवल पर करती है को सैन्ट्रल लैवल के प्रोजैक्टस हैं । (विघ्न)

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह कान्स्टीट्यूशन के अन्दर प्रोविजन है । (विध्न)

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : मैं सभी मैम्बरों से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस मामले में एक अच्छा माहौल तैयार करें । आज हमें दो चीजों की दिक्कत आ रही है । एक तो पैसे की कुछ कमी है । इस काम के लिए हम सैन्ट्रल सरकार से अधिक से अधिक पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं । दूसरे वहां का माहौल भी काफी दिनों से ठीक नहीं है । इसलिए हम सब को

और अपोजीशन को इस के अन्दर एक अच्छा रोल अदा करना चाहिए । हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे इस नहर के पंजाब के अन्दर वनने में किसी तरह की कोई रुकावट आये । (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती : आप नहर की खुदाई करवा दें, हम तो सवाल भी नहीं पछेंगे ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : हम वहां के भाईयों का मन जीत कर ही यह काम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं । अपोजीशन का भी बहुत अहम रोल होता है । इसलिए आप लोगों को भी इस मामले में वहां के वातावरण को अच्छा बनाने में सहयोग देना चाहिए । (विघन्)

श्री लछमन सिंह : हम तो सुझाव ही दे सकते हैं । (विघन) वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपोजीशन का रोल किसी मामले में कम नहीं है । (विध्न)

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : हम भी यही चाहते हैं कि वहां का वातावरण जल्दी से जल्दी ठीक हो ताकि इस नहर की खुदाई भी शीघ्र पूरी हो सके ।

Expenditure incurred on Adult Education

***862. Chaudhri Balvir Singh Grewal :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the amount of expenditure incurred on adult

education in the State during the years 1981-82, 1982-83, 1983-84 and 1984-85 (upto 31 Dec. 1984); and

(b) the district-wise number of adults imparted educaticn in the State during the said period togetherwith the names of the villages of district Bhiwani where the said education has been or is being imparted ?

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra) :

(a) and (b) : Statement is laid on the Table of the House as Annexures A & B.

ANNEXURE—A

	Years	Total expenditure
		(Rs. in lakhs)
1.	1981-82	Rs. 71.77
2.	1982-83	Rs. 81.55
3.	1983-84	Rs. 95.51
4.	1984-85 (up to 31-12-1984)	Rs. 73.04

Annexure—B

(1) The district-wise number of adults imparted education in the State for the years concerned is as under:—

	Name of the	Number of adults imparted education during the year			
	District	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (upto 31st Dec. 1984).
1.	Ambala	6499	7923	8198	9715
2.	Bhiwani	6009	9549	8918	17597
3.	Faridabad	4735	6541	8 546	7910
4.	Gurgaon	8209	10022	9388	9655
5.	Hissar	6237	7451	10017	15896
6.	find	5816	17540	16232	16458
7.	Karnal	6036	9634	9361	9646
8.	Kuruksh etra	776 8	12089	9593	18000
9.	Rohtak	5707	8436	7289	10519
10.	Narnaul	7580	8926	17258	18170
11.	Sirsa	6689	7789	11291	11030
12.	Sonepat	641 5	11264	8669	9253

(2) List of Villages of Distt. Bhiwani where the Adult Education is being imparted' :-

Sr. No.	Name of Village
1.	Dharera
2.	Sanga
3.	Kauat
4.	Puranpura
5.	Rewari Khera
6.	Manhera
7.	Dhana Narsan
8.	Madhu Madhvi
9.	Paluwas
10.	Bamla
11.	Ajitpura
12.	Bapura
13.	Ghuskarni
14.	Gujrani
15.	Chang
16.	Jigrana
17.	Sai

18. Mitathal
19. Dhani Harsukh
20. Biran
21. Preen Nagar
22. Kaluwas
23. Devsar
24. Gobindpura
25. Dhirana Kalan
26. Asalwas Marhatta
27. Golpura
28. Rajgarh
29. Haluwas
30. Haluwas Majra Devsar
31. Neeriwali
32. Kitlana
33. Goripur
34. Haripur
35. Rupgarh
36. Nadgaon
37. Nangla

38. Kheri Daulatpur
39. Dhanana
40. Talu
41. Mandhana
42. Kungar
43. Mundhal Kalan
44. Mundhal Khurd
45. Badesra
46. Jatai
47. Pur
48. Siwara
49. Baliali
50. Sumrakhera
51. Jamalpur
52. Bohai
53. Dangkhurd
54. Bhaini Jattan
55. Paposa
56. Alakhpura
57. Barsi Jattan

58. Barsi Gujran

59. Milakpur

60. Ratera

61. Jitakheri

62. Sippar

63. Kirawar

64. Durjanpur

65. Dang Kalan

66. Sankror

67. Malkosh

68. Neemri

69. Kasni

70. Sanwar

71. Saunf

72. Misri

73. Sanjarwas

74. Ranila

75. Achina

76. Rankoli

77. Baund Khurd

78. Baund Kalan

79. Mirch

80. Kamod

81. Dhani Phogat

82. Mehrana

83. Santor

84. Bhagwi

85. ImIota

86. Gigow a

87. Loharwara

88. Jhinjar

89. Samaspur

90. Khatiwas

91. Rawaldhi

92. Mauri

93. Makrana

94. Ghasola

95. Makrani

96. Santoshpura

97. Balkara

98. Chiriya

99. Datoli

100. Dudhwa

101. Mandholi

102. Mandola

103. Chhillar

104. Jhojhu Kalan

105. Badhwana

106. Baloli 107: Sirhi 108. Mehra

109. Jhojhu Khurd

110. Chandeni

111. Badal

112. Naurangabas Thakran

113. Naurangabas Jattan

114. Dadhi Bana

115. Kalali

116. Beejna

117. Kheri Bura

118. Kheri Buttar

119. Sahuwas

120. Fatehgarh
121. Narsingwas
122. Painawas Kalan
123. Charkhi
124. Mankawas
125. Ghikara
126. Rasiwas
127. Chhappar
128. Barsana
129. Pandwan
130. Dohki.
131. Sarangpur
132. Tiwala
133. Siswala
134. Arya Nagar
135. Gobindpura
136. Gopi
137. Khorda
138. Dhandwa
139. Mandi Haria

140. Mandi Kehar

141. Jagran Bass

142. Panch Gaon

143. Jewali

144. Chand was

145. Kari Dharni

146. Kari Moth

147. Badhra

148. Nandha

149. Hansawas Khurd

150. Hansawas Kalan

151. Hui

152. Badesara

153. Atela Kalan

154. Atela Khurd

155. Atela Naya

156. Dohka Moji

157. Dohka Dina

158. Rampura

159. Dudi Wala (K)

160. Kbationki Dhani

161. Sainionki Dhani

162. Umarwas

163. Jeet Pura

164. Kakroli Khatika

165. Kakroli Sardama

166. Kakroli Hatti

167. Kakroli Hukmi

168. Ladawas

169. Dwarka

170. Shyam Kalan

171. Dandma

172. Harodi

173. Bindraban

174. Pichopa Kalan

175. Pichopa Khurd

176. Berla

177. Mandhi Priano

178. Nihal Garb

179. Rambass ,

180. Unn

181. Kadma

182. Dagroli

183. Kandhra

184. Sangwan

185. Kharkri Sohan

186. Duleheri

187. Nigana Khurd

188. Sugarpur

189. Kharkari Madhwan

190. Lakshaman Pura

191. Jhamri

192. Thilor

193. Alampur

194. Haroda

195. Patodhi Khurd

196. Patodhi Kalan

197. Sandhwa

198. Saral

199. Dadam

200. Khanak

201. Pinjokhera

202. Garanpura Khurd

203. Garanpura Kalan

204. Tosham

205. Dhani Bhakran

206. Bidhwan

207. Kakali

208. Gudha

209. Kalod

210. Dewawas Khurd

211. Dewawas Kalan

212. Madhan

213. Jhulli

214. Bhariwas

215. Indriwali

216. Dhani Ketwar

217. Ketwar

218. Bushan

219. Sahlawala

220. Hassan

221. Rodhan

222. Isharwal

223. Siwani

224. Barwa

225. Dhani Mithi

226. Naloi

227. Kikral

228. Sainiwas

229. Budhsoili

230. Gaindawas

231. Bakhwatwar Pura

232. Ghadwa

233. Bhera

234. Sidhan

235. Miran

236, Chhapra Jogiyan

237. Dhani Miran

238. Dhani Bhalara

239. Khera

240. Dariapur

241. Loharu

242. Kundal

243. Sahansara

244. Jhajara Toda

245. Kushalpura

246. Barlu

247. Bisalwas

248. Ahamdawas

249. Damkora

250. Gagarwas

251. Bhudera

252. Dhani Lakshaman

253. Sighani

254. Dhani Toda

255. Barwas

256. Dhani Manshukh

257. Jhuppa Kalan

258. Jhuppa Khurd

259. Basirwas

260. Obera

261. Seharyarpur

262. Sindhnawa

263. Hariawas

264. Gopalwas

265. Mandholi Kalan

266. Kasani Khurd

267. Kasani Kalan

268. Serla

269. Bidhnoi

270. Bidhan

271. Nunsar

272. Saher

273. Paju

274. Kharkari

275. Baran

276. Choharkalan

277. Nangal

278. Pahari

279. Dhana Jogi

280. Bardu Chaina

281. Bahal

282. Surpura Kalan

283. Surpura Khurd

284. Morta

285. Sorda Jadid

286. Sudhiwas

287. Matani

288. Jhuppa Kalan

289. Jhuppa Khurd

290. Gokalpura

291. Patwan

292. Midhi

293. Garwa'

294. Devrala

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे सवाल के ए भाग के जवाब में बताया है कि चार सालों में इतना–इतना रुपया एडल्ट एजुकेशन पर खर्च हुआ है । जो फिगर्ज इन्होंने सदन की टेबल पर रखी हैं उसके मुताबिक एक जिले के हिस्से में एक साल के लिए 8. 50 लाख या 6. 75 लाख

रुपये आते हैं । मैंने भिवानी जिले के बारे में पूछा था कि कितने गांवों में एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम चलाया गया है । इसके उत्तर में इन्होंने 294 गांवों के नाम दिए हैं । मैं इनसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि ये मुझे किन्हीं 10 गांवों के आदमियों के नाम बता दें जिनको इन्होंने पिछले चार सालों में एडल्ट एजुकेशन दी हो । दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो टीचर इस काम के लिए लगाए हुए हैं, उनको कितनी पे दी जाती है और आया वे परमानैंट हैं या टैम्परेरी बेसिज पर काम कर रहे हैं?

श्री जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, जो पैसे का हिसाब इन्होंने बताया है वह दुरुस्त है । लेकिन अनैक्श्चर 'बी' के अन्दर हर जिले की फिगर साल वाईज दी गई है कि किस साल में कितने लोगों को एडल्ट एजुकेशन दी गई । ये अब 10 गांवों के आदमियों के नाम पूछ रहे छउ । मेरे पास नाम नहीं हैं । टोटल फिगर है जो मैंने सदन की पटल पर रख दी है । इसमें से आप 10 गांव छांट लें ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ 10 गांव के आदमियों के नाम ही बता दे जिनको आपने एडल्ट एजुकेशन पिछले चार सालों में दी है?

श्री जगदीश नेहरा : मैंने बताया है कि मेरे पास नाम नहीं हैं टोटल फिगर है जिनको शिक्षित किया गया है । पिछले चार सालों में कितने–कितने लोगों को एडल्ट एजुकेशन दी गई

यह अनैक्श्चर बी पर है । आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं । इस अनैक्श्चर के अन्दर भिवानी जिला नम्बर 2 पर आता है । आप इसको पढ़ ले । इससे पता लग जाएगा कि पिछले चार सालों के अन्दर भिवानी जिले में कितने लोगों को एडल्ट एजुकेशन दी गई है । स्पीकर साहब, दूसरा सवाल इनका यह था कि जो टीचर पढ़ाते हैं आया वे रैगुलर हैं या नहीं और उनको पे क्या मिलती है । इनको 100 रुपया महीना पे मिलती है । जब तक कोई पढ़ाना चाहे उस समय तक वह टीचर परमानैट रहता है । इनको कोई नहीं हटाता । जब तक कोई शिकायत न आ जाए, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता । अगर कोई टीचर समय पर नहीं आता या क्लास नहीं लेता तो आनरेबल मैम्बर बता दें, मैं देखे लूंगा ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : स्पीकर साहब, मेरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट था । ये बता दें कि पिछले चार सालों में, किसी एक गांव में कितने लोगों को एजुकेट किया हैं?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कंसोलिडेटिड फिगर है, किसी पर्टिकुलर गांव की फिगर नहीं है ।

चौधरी बलबीर सिह ग्रेवाल : आप सिर्फ किसी एक गांव की फिगर बता दें ।

श्री अध्यक्ष : ये कहते हैं कि इनके पास विलेजवाईज फिगर नहीं है, टोटल फिगर है ।

चौधरी ओम प्रकाश : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने सवाल के जवाब में फिगर दी है कि. फलां–फलां जिले में 1981 से 31 दिसम्बर, 1984 तक इतने आदमियों को एडल्ट एजुकेशन दी है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सारी स्टेट में एडल्ट एजुकेशन के कितने सैन्टर खोले गए हैं और एक सैन्टर कितनी पापुलेशन के पीछे खोला जाता है? स्पीकर साहब, जहां तक मैं समझता हूं, दो किस्म के टीचर्ज एडल्ट एजुकेशन देने के लिए रखे जाते हैं । एक किस्म के टीचर को 100 रुपये और दूसरी किस्म के टीचर को 150 रुपये तन्खाह मिलती है । क्या सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम अंडर कंसीड्रेक्षन है जिसके तहत इनकी तन्खाह बढ़ाई जाए? इसके अलावा क्या मन्वी महोदय बतायेंगे कि लोगों को पढ़ाने के टाईमिग्ज क्या हैं? क्या इनकी नालेज में यह बात है कि प्रौढ शिक्षा को स्टेट में कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है और हरियाणा निवासी प्रौढ शिखा को फौड शिक्षा की संज्ञा देते हैं ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इन्होंने पहला सवाल यह किया कि स्टेट में कुल कितने सैन्टर हैं । स्टेट में कुल 4900 सैन्टर हैं, जिन में से 2700 सैन्टर सैन्ट्रल गवर्नमैंट के हैं और 2200 स्टेट गवर्नमैंट के हैं । दूसरा सवाल यह किया कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सैन्टर खोले जाते हैं, इस का जवाब यह है कि एक ब्लौक में 100 सैन्टर खोले जाते हैं, ब्लौक एक यूनिट है, इसमें जो पंचायतें होती हैं उनकी सलाह से स्कूल खोले जाते

हैं । तीसरी बात इन्होंने कही कि सैन्टरों में पढाई नहीं होती, ऐसे ही तन्खाह दे दी जाती है । अध्यक्ष महोदय, यहां पर एडल्ट सैन्टर दो तरह के हैं । एक एडल्ट सैन्टर पुरुषों के लिए और दूसरा स्त्रियों के लिए है । स्त्रियों के सैन्टर ठीक तरह से चल रहे हैं, इसका कारण यह है इसमें फंक्शनल नालेज यानि सिलाई, कढाई, बुनाई वगैरा का ज्ञान दिया जाता है । इस ज्ञान को हासिल करने के लिए औरतें ज्यादा आती हैं । पुरुषों के सैन्टर बहुत कम हैं । चौथी बात इन्होंने कही कि कुछ टीचर्ज को 150 रुपये और कुछ को 100 रुपया तन्खाह दी जाती है । यह तन्खाह बढाई जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, 100 रुपया महीना हम एडल्टस को पढाने का देते हैं । दूसरे नान–फार्मल एजुकेशन देतें हैं । जो बच्चे 9–10 साल की उम्र में वहां सैन्टर में आ जाते हैं, उनको जो शिक्षा देते हैं उसको नान–फार्मल एजुकेशन कहते हैं और जौ पढ़ाते हैं उनको 150 रुपये महीना देते हैं । जहां तक इस शिक्षा को आगे बढ़ाने का सवाल है, आप जानते हैं कि यह सैड़ल गवर्नमैंट की स्कीम है । सैन्ट्रल गवर्नमैंट पहले टीचर को 50 रुपया देती थी, अब बढ़ाकर 100 रुपया किया है । इससे ज्यादा बढ़ाने का मामला अंडर कंसीड्रेशन नहीं है ।

श्री देवी दास : क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जो बोले जाते हैं, ये सरकारी स्कूलों में खोले जाते हैं या प्राईवेट जगहों पर खोले जाते हैं अगर प्राईवेट जगहों में खोले जाते हैं तो इस जगह का माहवार किराया क्या दिया जाता है?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, गांवों में पंचायत की जगह होती है, वहां सैन्टर खोला जाता है । जो जगह गांव की सांझी हो, पंचायत घर हो, हरिजन चौपाल हो यानी जहां सुविधा हो, वहां खोला जाता है और इस जगह का कोई किराया नहीं दिया जाता ।

श्री मंगल सैन : मैं शिक्षा राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो शिक्षा ये इन सैन्टर्ज में देते हैं, क्या उसके बाद कोई टैस्ट भी लिया जाता है? अगर टैस्ट लिया जाता है तो क्या कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और सर्टिफिकेट इशू करने का मापदण्ड क्या है?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, एडल्टस की पढ़ाई 10 महीने हौती है, इसके बाद टैस्ट होता है । टैस्ट में लिखाई–पढ़ाई का ज्ञान देखा जाता है और फंक्शनल ज्ञान के बारे में सवाल पूछे जाते है ।

श्री मंगल सैन : फंक्शनल ज्ञान क्या होता है?

श्री जगदीश नेहरा : इस में प्रैक्टिकल नालेज देखा जाती है ।

श्री मंगल सैन : किस चीज की प्रैक्टिकल नालेज दी जाती है?

श्री जगदीश नेहरा : जो महिलाएं खिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम मशीन पर करती हैं वही इनका प्रैक्टिकल नालेज होता है और टैस्ट में इनका प्रैक्टिकल नालेज देखा जाता है । आप जैसे मर्दो को इस नालेज की जरूरत नहीं है ।

श्री कंवल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएगे कि जो टीचर्ज प्रौढ शि ना के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, उनके रिक्रूट करने का क्या क्राइटेरिया हे? इसके अलावा जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं, उनका रेट आफ अटेंडैसं क्या है यानी उनकी रैगु–लैरिटी किस प्रकार की है?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जो लड़का 10 वी क्लास पढ़ा हो और कहता है कि मुझे पढ़ाने के लिए लगना है तो उसको लगा लिया जाता है । जहां तक अटैडैसं का सवाल है, पुरुषों की अटैंडैंस राउण्ड अबाउट 40 से 50 परसैटं है और स्त्रियों की अटेंडैंस 70 से 75 परसैटं है ।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, फर्ज करो किसी गांव में पढ़ाने के लिए 20 लड़के एप्लाई करते हैं इनको किस आधार पर सिलैक्ट करते हैं?

श्री जगदीश नेहरा : जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, उनको रख लेते है?

श्री भागी राम : क्या मन्त्री महोदय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन टोचर्ज की तन्खाह 100 रुपए से बड़ा दी जाए?

स्पीकर साहब, आप इस बात को फील करते होंगे कि 100 रुपया लेकर कोई आदमी क्या पढाएगा । सही बात तो यह है कि इनके पास जो आदमी आते ऊद वे कहते हैं कि मेरे लडके को नौकरी लगवा दो । (व्यवधान) वे दस–बीस आदमियों के नाम लिख देते हैं और जो जिस गांव का होता है उसे उसी गांव में लगा देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

श्री भागी राम : मैं सवाल पूछ लेता हूं जी । मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी तन्खाह बडाने के लिए क्या सरकार किसी प्रपोजल पर विचार कर रही है जिसके तहत इनकी तन्खाह 200 या 400 रुपए हो जाए? क्या मन्त्री महोदय अपनी कांस्टीज्यूएसी के गांव पनियाल मोटा में किमी आदमी का नाम बता सकते हैं जिसने प्रौढ शिक्षा ली हो?

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी, आप हमेशा पर्सनल बात करते हैं, इसी लिए मैं आपको कई बार एवायड करता हूं । आप बैठ जाईए । (व्यवधान)

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मेरे कहो का मतलब यह कुए कि यह प्रौढ शिक्षा एक फौड है, इसका लोगों को कोई लाभ नहीं है, यह बिल्कुल बन्द होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप मेहरवानी करके बैठ जाइ ए ।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह कोड इसलिए नंजर आता है कि यह फौड इनकी सरकार ने शुरू किया था । 2 अक्तूबर, 1978 को यह स्कीम लागू हुई थी और केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार ने इसको लागू किया था । यदि यह फौड है तो यह फौड इन्होंने किया था (व्यवधान)

श्री भागी राम : आप मेरे सवाल का ठीक ढंग से जवाब दीजिए । (व्यवधान)

श्री जगदीश नेहरा : अगर आप ठीक ढंग से सवाल करेंगे तो जवाब भी ठीक ढंग से देंगे । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दूसरा सवाल किया है कि मेंरे गांव में कितने पढ़े लिखे हैं? अपने गांव के बारे में तो शायद मैं ऐग्जैक्टली नहीं बता सकता लेकिन इनके गांव के बारे में बता सकता हूं कि फना–फना आदमी पढ़ा है । अध्यक्ष महोदय, तीसरा सवाल इन्होंने यह किया कि क्या तन्खाह के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं या नहीं? अध्यक्ष महोदय, जैसा मैने पहले अर्ज किया कि उनकी तन्खाह पहले 50 रुपए हुआ करती थी लेकिन इसे बढ़ाकर 1 – 3– 84 को 100 रुपए कर दिया गया । इसको और ज्यादा करने के लिए नौन फोर्मल ऐजुकेशन इसके साथ जोड़ी गई । जो बच्चे काम धन्धे में लग जाते हैं उनको इन सैन्टर्ज में शिक्षा दी जाती है । यहां पढ़ाने वाले टीचर्ज को 150 रुपए तन्खाह दी जाती है । अध्यक्ष महोदय, कई बार हम दो सैन्टर्ज को इकटठा भी कर देते हैं ताकि पढाने वाले को दो सौ तीन सौ रुपए तक तन्खाह मिल जाए ।

Conversion of Saraswati River into drain in District Kurukshetra

***856. Shri Kitab Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to convert the Saraswati river in the North of the Kurukshetra City into a drain from Sher Shah. Suri Marg to the Syphon situated on Bhakra Canal ; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to materialise ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) :

(a) No.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, इस नदी में कई बार इतना पानी आता है कि कुरुक्षेत्र बस्ती तबाह हो जाती है और लोगों की फसलें भी तबाह हो जाती हैं । क्या सरकार के जेरे गौर कोई ऐसी स्कीम है जिसको लाग करके इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मकान और जमीनों को बचाया जा सके?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, सरस्वती ऐसा रिवर नहीं है जिस सैन्स में एक रिवर होता है । यह कोई लीजैन्डरी दरिया होगा जो जमीन के नीचे चला गया ।

जहां से सरस्वती नदी गुजरती है वहां से उस रिवर का पुराना कोर्स था । उसमें पानी तब आता है जब मारकंडा और चुटाग नदियों में पानी स्पिल ओवर हो जाता है । वह पानी कुछ एरियाज को फ्लड करता था । सन 1978 में काफी फ्लड आया था । अब मारकंडा और चुटांग नदियों की ऐग्बैंकमैंटस बना दी गई है और ऊंची कर दी गई है । उससे फ्लड का पानी इस एरिया में आने का कम चांस है । दूसरी बात स्पीकर साहब यह है कि सरस्वती नदी का पानी कुरुक्षेत्र से आगे जाकर डाऊन स्ट्रीम बीबीपुर लेक में चला जाता है । (विध्न) अगर बरसात ज्यादा हो तो पानी शीट क्लो में बीबीपुर लेक में चला जाता है । कुरुक्षेत्र शहर को बचाने के लिए डेरनेज डिपार्टमैंट ने टाऊन एंड कटरी प्लानिंग डिपार्टमैंट को राय दी है कि जी० टी० रोड से लेकर रिंग रोड तक, नौर्थ में जो पैरीफरी है, उसकी सड़कों को रेज कर दिया जाए । ऐसा करने से, अगर कभी सरस्वती में ज्यादा पानी आने का चांस हो तो कुरुक्षेत्र टाऊन उससे बच जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि सरस्वती नदी में जो फलड आता है वह इसलिए आता है कि आगे नरवाना बीच के अन्दर जो एस्केप है उसकी कैपेसिटी थोडी है और पानी ज्यादा आ जाता है । दो तीन दफा तो नहर भी काटनी पड़ी है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, यह ठीक है कि यह जो ऐस्केप हए इसकी कैपेसिटी इतनी तो नहीं है कि 1978 से पहले जितना पानी आता था उसको बीयर कर ले

लेकिन प्रोटैक्शन वर्कस जो किए गए हैं उनसे अब ऐसा होने का चौस कम है । अब कुरुक्षेत्र टाऊन को कोई खतरा नहीं है ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, सरस्वती नदी के साथ साथ राक्षी नदी चलती है । इसकी कैपेसिटी थोड़ी है जबकि बरसात में पानी ज्यादा आ जाता है । इससे रादौर की सारी फसलें खराब हो जाती हैं । लाडवा बस स्टैंड तक पानी आ जाना है । क्या सरकार इसका कुछ इन्तजाम करेगी?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल राक्षी नदी के बारे में नही है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, पर्टिकुलरली इस बारे में तो मैं नहीं बता सकूंगा' लेकिन एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि चाहे राक्षी नदी हो या कोई दूसरी छोटी नदी हौ, इन नदियों मैं फ्लैश फ्लड आता है । इनमें 1 2– 14 घंटे से ज्यादा पानी नहीं चलता । इनमें पानी आता है और आगे निकल जाता है । इनमें फ्लड उस सैन्स में नहीं आता कि पानी लम्बे समय तक खड़ा रहता हो ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, आपने भी अभी कहा कि सरस्वती नदी में काफी पानी आता है और उससे लोगों को भी नुक्सान होता है और कुरुक्षेत्र शहर को भी नुक्सान होता है । क्या सरकार कोई ऐसी स्कीम बनवाएगी कि यह पानी बीबीपुर लेक में चला जाए और लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल हो सके?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, स्कीम आलरेडी है । बहुत सा काम हो चुका है । जो बड़े–बडे नाले थे, मारकंडा और घग्गर आदि उनको कैनेलाइज करने के लिए सरकार ने काफी कुछ किया है । इसी तरह से जो नाले जमुना के साथ लगते हैं उनको कैनेलाइज करने के लिए प्रोटेक्शन बंध बनाए हैं । स्पीकर साहब, ये नाले बेशुमार हैं । इनके लिए फूल–प्रूफ स्कीम तो तभी बन सकती है यदि एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट, फोररैस्ट डिपार्टमैंट और दूसरे सारे डिपार्टमैंटस मिल कर कुछ करें लेकिन फिर भी सरकार हर साल कोई न कोई स्कीम फाईनैन्सिज को देखते हुए टेक अप करती है । इसके बावजूद भी यदि माननीय सदस्य कोई पर्टिकुलर बात कहेंगे तो उसे डिपार्टमैंट से जरूर ऐग्जामिन करवाया जाएगा ।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, मंत्रो जी ने अभी कहा कि 1978 के बाद वहां बाढ़ नहीं आई लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि बहूत बाढ आई है और बहुत फसलें भी तबाह हुई हैं । ये इस बात को अपने अधिकारियों से पूछ लें । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सरस्वती रिवर को ड्रेन में तबदील कर दिया जाएगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर– साहब, इस बात को डिपार्टमैंट ने ऐग्जामिन किया है । अगर हमने इस नदी को ड़ेन के रूप में बना दिया तो शीट क्लो को बदलने से नुक्सान ज्यादा सिवीयर होगा । आपने खुद भी फरमाया है कि नरवाना

ब्रांच कें नीचे आउट–लैट ज्यादा बड़ा नहीं है । इससे पूरी कैनाल टूट सकती है । इसलिए यही ऐडवाइजेबल समझा गया कि इसे कंवर्ट न किया जाए । अभी इसका पलों ज्यादा सिवीयर नहीं है । पानी बीबीपुर लेक में चला जाता है । यहां बहुत देर पानी खड़ा नहीं होता ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, चुतंग नाले को कैनेलाइज करने के लिए एक स्कीम बनी थी । क्या वह स्कीम अब भी सरकार के विचाराधीन है? स्पीकर साहब, यह नाला अपने रास्ते से हट चुका है । बरसात के मौसम में यह आसपास के लगते हुए गांव को तबाह कर जाता है । (विघ्न) वहां कुछ काम तो हुआ था लेकिन कुछ काम रुका पड़ा है । क्या उस काम को मुकम्मल करवाने के लिए सरकार कुछ करेगी?

चौधरी शमशेर सिह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मुझे पता नही कि ये कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं लेकिन मैं सदन को एक बात बताना चाहूंगा । अम्बाला और कुरुक्षेत्र किले में यह देखने में आया है कि मुरब्बाबन्दी के बाद लोगों ने वेस्ट लैंड को लेवल करके कल्टीवेशन शुरु कर ली है । बहुत से नदी नाले ऐसे हैं जिनका कोर्स तक मोजूद नहीं है । अब नैचुरली पानी इधर उधर जाने की कोशिस करता हे । पूरी जमीन को हम ऐक्वाकर नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा दे नहीं सकते । डा० साहब कौन सी योजना की बात कर रहे हैं यह मुझे पता नहीं । ये अगर

इस बारे में अलग से पूछेंगे या बाहर मेरे से बात करेंगे तो मैं इनको प्री तरह से अवगत करवाऊंगा ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, वह स्कीम डेरन्ज डिपार्टमेंट के पास पैंडिंग है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : डा ० साहब, उसे देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब सवालों का समय समाप्त होता है ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Natnpa Jnakri Project

***840. Shri Hari Chand Hoola :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the present stage of the construction work of Nathpa Jhakri Project togetherwith the steps, if any, being taken or proposed to be taken to co nplete tne said project ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : प्रारम्भिक निर्माण कार्य जैसे आवासों का, पहुंच सड्कों एवं स्रोत आदि के निर्माण को हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जा चुका है । फिर भी इस परियोजना का निर्माण अब केन्द्रीय सैक्टर में राष्ट्रीय जलीय विद्युत निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किया जाना है ।

Passengers travelling from Jhajjar to Rohtak

***892. Shrimati Basanti Devi :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the buses coming from Jhajjar to Rohtak drop the passengers 4 k.m. away from the Rohtak bus stand; and

(b) if so, tne arrangement, if any, made or proposed to be made for providing bus service to the passengers from there to the said bus stand ?

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Construction of pump houses and drains along JLN Canal and JSB.

***926. Chaudhri Om Parkash :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under cosideration of the Government to construct pump houses and parallel drains along JLN Canal and JSB in District Rohtak for checking water logging and seepage; if so, the time by which the said proposal is likely to materialise ?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : जी हां । इस समय जे. एल. एन. नहर के साथ–साथ डिच ड्रैन तथा पम्प हाउस बनाने का प्रस्ताव है । जहां

तक अच्छर सब ब्राँच का सम्बन्ध है, इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । उपरोक्त वर्णित स्कीम पर कार्य वर्ष 1985–86 में शुरू करने का प्रस्ताव है और योजना के अनुसार किया जायेगा ।

Loan under the R.I. Scheme

***962. Shri Devi Dass :** Will the Minister for industries be pleased to state-

(a) the names and addresses of factories 'units' set up under R.I. Scheme in district Sonepat during the period from January, 1978 to February, 1985 togetner with the amount of loans, if any, given to the said factories;

(b) whether any raw material has been supplied by the Govt. to any of the factories, as referred to in part (a) above during the same period; if so, details thereof together with the names of the factories ; and

(c) whether any goods, manufactured at any of the above said factories, have been purchased by the Govt. during the above said period; if so, the names of all such factories together with the details of the goods purchased ?

उद्योग मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया) : वांछित सूचना एकत्रित करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा उससे उतना लाभ न होगा ।

Gobar Gas Plant

***968. Chandhri Kundan Lal :** Will the Chief

Minister be pleased to state—

(a) the number of Gobar Gas plants installed in the State during the years 1982, 1983 and 1984 togetherwith the amount given by the Government for the installation thereof separately; and

(b) the number of plants, out of those referred to in part (a) above, as were in working order on 1.1.1985 ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(ए) तथा (बी) तालिका अनुबन्ध ए, बी तथा सी सदन के पटल पर रखी जाती हैं ।

अनुबन्ध 'ए'

वर्ष 1982– 83, 83– 84 एवं 84– 85 में स्थापित किये गये' संयत्रों की सूचि

क्र०	जिले का नाम	कुल बायो गैस मंगल जो स्थापित किये गये		
		वर्ष	वर्ष	वर्ष
		1982–83	1983–84	1984– 85 (28– 2– 85 तक)

1	अम्बाला	218	213	249
2	करनाल	345	377	489
3	सोनीपत	70	59	165
4	गुडगांव	142	123	84
5	फरीदाबाद	160	228	118
6	नारनौल	81	156	161
7	भिवानी	84	169	138
8	रोहतक	54	228	211
9	जीन्द	150	144	82
10	हिसार	320	368	288
11	सिरसा	292	289	228
12	कुरुक्षेत्र	343	176	193
	कुल जोड़	2259	2530	2406

अनबन्ध 'बी'

वर्ष 1982–83, 83–84 एवं 84–85 में स्थापित किए गए संयत्रों पर दी गई अनुदान की राशि की सूचि ।

क्र०	जिले का नाम	जिले का नाम बायोगैस संयतों पर दी गई अनुदान राशि		
		वर्ष	वर्ष	वर्ष
		1982– 83	1983–84	1984– 85 (2/85 तक)
1	अम्बाला	4,00,000	3,90,000	3,50,000
2	करनाल	8,00,000	8,58,000	15,02,000
3	सोनीपत	2,50,000	2,12,000	2,35,000
4	गुडगांव	2,50,000	2,35,000	1,72,000
5	फरीदाबाद	5,00,000	7,12,000	2,84,000
6	नारनौल	1,25,000	2,22,000	3,69,000
7	भिवानी	1,40,000	3,75,000	1,50,000
8	रोहतक	1,20,000	4,18,000	3,04,000
9	जीन्द	2.50,000	2,16,000	2,45,000
10	हिसार	7,00,000	7,56,000	7,70,000
11	सिरसा	8,50,000	8,51,0 00	6,00,000

12	कुरुक्षेत्र	6,94,000	3,29,000	6,78,000
	टोटल	50,79,000	55,74,000	56,59,000

अनबन्ध 'सी '

1– 1– 85 तक स्थापित हुए बायोगैस संयतों की सूचित (चालू हालत में)

क्र सं ०	जिले का नाम	कुल स्थापित किए गए संवत्र	कार्य कर रहे संयत्रो की संख्या
1	अम्बाला	680	634
2	करनाल	1211	1135
3	सोनीपत	294	197
4	गुडगांव	349	182
5	फरीदाबाद	506	264
6	नारनौल	39.8	215
7	भिवानी	391	189
8	रोहतक	493	248

9	जीन्द	376	219
10	हिसार	976	495
11	सिरसा	809	610
12	कुरुक्षेत्र	712	712
	कुल जोड़	7195	5100

Complaints received under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

***939. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether any complaints alleging violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 were received during the years 1982, 1983, 1984 and 1985 (to-date); if so, the number thereof together with the action, if any, taken thereon ?

Finance Minister (Shri Sagar Ram Gupta) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

31 complaints alleging violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 due to the discharge of polluted effluents into banal on land and in sewer were received during the years 1982, 1983, 1984, 1985 (to-date). The number of complaints received with the Board yearwise is as under

(i) 1982 = 2

(ii) 1983 = 14

(iii) 1984 = 14

(iv) 1985 = 1

Total = 31

These involve total number of 35 industries.

The Haryana State B)ard for the Prevention & Control of Water Pollution enquired into all these complaints. As a result of these enquiries, tne following action has been taken.

(i) Complaint against one industry was not correct.

(ii) Seven industries were found to be discharging effluents into canal system out of which one has already provided the treatment plant. The Board filed cases against the remaining industries. As a result of the prosecution, five industries have started construction of treatment plant and the remaining one industry has initiated experimental study for this purpose.

(iii) Three industries were found to be discharging effluent in sewer. The Board has filed prosecution case against one industry. Case against another industry nas also been approved for prosecution. One industry is housed in a residence and the discharge is negligible. However, the industry is being persuaded to take anti-pollution measures.

(iv) 24 industries were found to be discharging effluent on land, out of which 3 industries have provided

treatment plants. and 2 have started construction of treatment plants. Prosecution proceedings were filed against 11 industries, as a result of which, 7 industries have since been closed, one industry has started the construction of treatment plant. 2 industries have been approved for prosecution. The remaining six industries are small scale industries discharging very little quantity of effluent and are being persuaded to provided treatment plants and to take anti-pollution measures.

Sanction for the construction of Roads

***981. Shri Bhagi Ram : Will the** Minister for Public Works (B&R) be pleased to state whether construction of the following roads has been sanctioned :-

(1) Otu to Dhani Pratap Singh;

(2) Rania Jivannagar road to Rampur Therhi;

(3) Ellenabad Mamera road to Moju Khera;

(4) Abholi to Dhamora Therh and 8 Burji; and

(5) Ellenabad to Dhani Jatan ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री अमर सिंह) :

1.

2.

3. जी हां ।

4.

5 ऐलनाबाद और ढाणी जाटान पहले से ही पक्की सड़क से जुड़े हुए है ।

Repair of Approach Roads

***978. Master Ram Singh :** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the approach roads in district Kurukshetra; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री अमर सिंह) :

(ए) मुरम्मत नियमित रूप से की जा रही है ।

(बी) उपरोक्त (ए) अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता ।

Feederwise supply of Electricity and Burnt Transformers

***857. Shri Kitab Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the feederwise hours for which the electricity was supplied daily to agricultural and industrial sectors in the State separately during the period from 1-1-85 to 15-1-85 ; and

(b) the number of transformers that got burnt during the period from 1-8-1984 to 15-1-1985 and the dates of their installation/ burning ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATMENT

(a) There are, at present 1100, 11 KV feeder emanating from about 260 grid sub-stations, supplying power to the agricultural as well as industrial consumers in the Stale. The running of feeders is recorded every hour in these sub-stations. Compilation of data in respect of 1 100 feeders for 15 days is an enormous and voluminuous exercise and involves considerable time and effort. However, the number of hours power was supplied to the 11 KV feeders circle-wise, on an average, during the period from 1-1-85 to 15-1-85 is placed as Annexure.

(b) 2208 transformers were burnt/damaged daring the period 1-8-84 to 31-1-85. These transformers were installed all over the State at different locations. In addition, the distribution transformers are also shifted from one place of installation to another, while carrying out the augmentations. Thus, the collection of desired information regarding 2208 burnt transformers is also a voluminuous work. However, the circle-wise break-up of damaged transformers month-wise from 8/84 to 1/85 is as below :—

Sr.	Name of	8/84	9/84	10/84	11/84	12/84	1/85

No.	Circle						
1.	Ambala	33	42	35	28	27	33
2.	Karnal	114	83	55	35	39	32
3.	Kurukshetra	98	85	32	40	27	44
4.	Faridabad	68	61	40	35	32	42
5.	Gurgaon	60	41	62	35	25	25
6.	Hissar	52	51	37	41	36	40
7.	Bhiwani	63	62	30	27	19	39
8.	Rohtak	29	33	23	22	13	17
9.	Delhi	44	42	44	26	23	30
	Total :	509	500	367	289	241	302

Annexure

January 1985 (from 1st to 15th)

Circle	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th
Ambala	5	3	3	3	5	5	5¼	8	6	34	2	2	4	4	4
Bhiwani	6	6½	4	4½	6	4	4¼	7	6	5	3	3	3	5	5

Delhi	4	4	3	4	5	5	4½	7	4	3½	4	14	5	3½	4
Faridabad	5	4	14	3	3½	3	3	7	3	2	2	1	1	2	1
Gurgaon	5	5	4	3½	5	4	4½	4	5	3½	3	2	4	5	3
Hissar	4	4½	2	2	4	6	3½	4½	2	1½	1	1	4	3	4
Karnal	2	2	3	3¼	5	4	3¼	64	1	1	2	2	1½	3	1
Kurukshetra	4	3	3	3¼	4	5	5	4	1	1½	1	2	3	3	3
Rohtak	8	3½	24	4	3½	4	4½	6	3	3	3	3	3	4	2

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

फरीदाबाद में पत्थर की खानों में काम कर रहे मजदूरों की दयनीय स्थिति सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, डा ० मंगल सैन और श्री हीरा नन्द आर्य की ओर से pitiable conditicns of the labourers working in Faridabad quarries के बारे में काल अटैन्शन मोशन के दो नोटिसिज मिले है । I admit both the notices. डा ० मंगल सैन अपना नोटिस पढ़ दें ।

Shri Mangal Sein : I want to draw the attention of the August House towards a matter of urgent public importance that the persons working in quarries or on crusners are forcibly detained in the name of liberation of the bonded labour by those persons who are indluging in mafia or illegal business in the Police Station Suram Khawaja, district

Faridabad. The police is not taking any action in the matter and stands as a spectator only. When any political worker or press reporter i.e. Shri Kirmani, Special Representative of Nay Bharat Times & Sh. Randhir Singh Cnandela, President of Bhartiya Janta Party visited the place where the policemen had burnt the huts of poor labourers, they were arrested. On account of the silence of the police in mafia activities and failure of district administration in regard to the security of life of the labourers working on crushers, the huts of poor people were burnt. When the Sarpanch of the village objected the drunkard police personnels not to tease the women, he was put behind the bars. The resentment is prevailing in whole of the area, district and State due to this incident. Through this motion I want to draw the attention of the Government towards this matter of public importance and of recent occurrence and request it to explain its stand in the matter.

Shri Hira Nand Arya : I want to draw the attention of the August House towards a matter of urgent public importance that inspite of the decision of the Supreme Court of 1983 and the award of the Haryana Government of 1985 in respect of the pitiable condition of the labourers working in Faridabad quarries the decision is not being implemented in favour of the bonded labourers due to the influence of the influencial persons, contractors and owners. On account of it the situation has worsened to such an extent that the labourers are not in a position to lead a human life. A number of persons have been killed in the dispute and **a** great panic and dissatisfaction is prevailing amongst the labourers. Therefore, the Government should inform this August House

after taking immediate action in this respect.

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय इस मामले पर आज व्यान देगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) : सर, मैं इसका कल जवाब दूंगी ।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मेरी भी काल–अटैन्शन मोशन एलेनावाद कस्वे के बारे में है । वहां पर तीस–पैतीस हजार की आबादी है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपकी काल अटैन्शन मोशन मुझे मिल गई है । मैं उसे कंसिडर करूंगा ।

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, मेरी भी एक काल अटैन्शन मोशन है । प्रधान मती ने पंजाब के किसानों को बोनस देने के बारे में ऐलान किया है । इस वारे में मैंने भी काल अटैन्शन मोशन भेजी है कि हरियाणा में भी किसानों को बोनस मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : वह मेरे पास पहुंची नहीं है । यह आपकी आदत ठीक नहीं है कि आप मोशन एडमिट होने से पहले ही लैक्चर देना शुरू कर दें । आप की काल अटैन्शन मोशन आ गई है । वह सैक्रेटरी साहब के पास पहुंच गई है । मेरे पासनहीं

पहुंची है । मैं कंसिडर करूंगा और कोशिश करूंगा कि गवर्नमैंट उस पर स्टेटमैंट दे ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : स्पीकर साहब, मेरी भी एक काल अटैन्शन मोशन भिवानी जिले के बारे में है । भिवानी जिले में फौरैस्ट डिपार्टमेंट पैसे का दुरुपयोग कर रहा है । मैंने यह आज ही दी है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वह अभी मेरे पास पहुंची नहीं है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, नेत्रहीन लोग मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिए गये थे । वे अपनी मांगों के सम्बन्ध में मिलने के लिए गये थे लेकिन उन लोगों को गिरक्तार करके बेरहमी से जेल में भेज दिया गया । इस विषय में मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण दें कि क्या यह बात सही है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : किसी भी नेत्रहीन को नहीं पकड़ा गया । वे लोग मेरे से मिले थे । मैंने उनकी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुना । नेत्रहीन जब भी कोई मांग रखते हैं तो सरकार पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है । सरकार ने हमेशा उनकी जायज मांग को माना है और आगे भी मानेगी । (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, उन में दो लड़के ऐसे हैं जिनका प्रैक्टीकल का इम्तहान है । एक का कल होना है । इसलिए उन्हें रिहा किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : जब गवर्नमैंट यह कहती है कि हमने किसी को गिरफ्तार नही किया तो फिर इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है ।

चौधरी धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन नियम 73 के अधीन के० सी० बी ० ड्रेन के बारे में दी है । इस ड्रेन का पानी जिला रोहतक के कुछ गांवों के खेतों में भर जाता है और सारे साल भरा रहता है । मैंने यह आज ही दी है । इसकी क्या पोजीशन है?

श्री अध्यक्ष : मैं इसे कन्सिडर करूंगा ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार से कहना चाहती हूं और मेरी शिकायत भी है कि मेरे घर में मेरी गैर हाजरी में मेरे कुक से एक आदमी खड़ा हो कर बातें कर रहा था । जब मैं वहां पहुंची और पूछा कि यह कौन है तो वह आदमी वहां से चला गया । मुझे पता नहीं कि यह बात आपके नोटिस में है या नहीं लेकिन मेरे घर पर सी० आई ० डी ० के लोग आते हैं । मैंने अपने आप देखा है । इस तरह से गुस्ताखी का व्यवहार करते हैं । यह बड़ी गलत चीज है । यह बात बरदाश्त करते हुए बहुत दिन हो गये । मजबूर हो कर हाउस में खड़े हो कर मुझे यह बात कहनी पड़ी । इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए । यह अच्छी बात नहीं है । (विघ्न एवं शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम सियासी आदमी हैं । सियासी आदमियों के पास सुबह से शाम तक घरों में सैकड़ों आदमी आते हैं । अगर इनके वर में एक आदमी चला गया और इनके कुक से बात करने लगा तो इस में क्या बुरी बात है । इनका यह इल्जाम कि सी ०आई ० डी ० वाले सफेद कपड़ों में आते हैं, यह बेआधारित बात है । वह कोई और भी हो सकता है । बहिन जी सियासत में हैं । इनके पास एक आदमी आ गया तो कहने लगीं कि सी ० आई० डी० वाला बात करने के लिए आया है । मेरे घर में भी सुबह से शाम तक एक हजार आदमी आते हैं । मेरे घर आते हैं तो आपके घर भी आ सकते हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती : मिलने वाले आपके घर में आते होंगे, मेरे घर में भी आते हैं लेकिन सी ० आई ० डी० वाले नहीं आने चाहिएं । यह अच्छी बात नहीं है । दूसरे जनाब मेरे दो तीन काल अटैन्शन मोशन थे । उनके बारे में भी जानकारी चाहती हूं । एक तो अम्बाला जिला के बारे में था । अम्बाला जिला की लेडी टीचर्ज के बारे में है । चण्डीगढ से हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के कर्मचारियों की लेडीज इस जिले में पढ़ाने के लिए जाती हैं । उन्हें हैरान किया जाता है और वे बच्चों को पढ़ा नहीं पातीं । (विघन)

श्री अध्यक्ष : वह मैंने डिस–अलाऊ कर दी हे । यह कोई नई बात नहीं है और न ही कोई अरजैन्ट मैटर है ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, एक दो काल अटैन्शन मोशन्ज और भी दी हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष : वे कौन सी हैं

श्रीमती चन्द्रावती : मुझे अश्व ध्यान नही है कि कौन कौन सी थी?

श्री अध्यक्ष : अगर आपको अपनी काल अटैन्शन मोशन्ज का धन नहीं है तो मेरे पास तो बहुत सारी आती हैं, फिर है कैसे ध्यान रख सकता हूं । आपकी किलर ड्रगज की काल अटैन्शन मोशन के बारे में मैंने गवर्नमैंट के कमैन्टस मंगवा– रखे हैं ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, क्वैश्चन–आवर में तो हम प्वायंट आफ आर्डर रेज नही कर सकते लेकिन अब मैं प्वायंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । स्पीकर साहब, आपने सुना होगा कि आनरेबल पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नमैंट आफ इंडिया एस9 वाई० एल० के मामले में और क्या कर सकती है? Article 249 of the Constitution of India empowers the Parliament to legislate with regard to a matter in the State List in the national interest. इस सारी धारा को मैं पढ़ना नहीं चाहता । इससे ही आप मेरा मतलब समझ गये होंगे कि अगर कोई विषय देश या राष्ट्र हित में हो तो भारत की संसद को अधिकार है कि वह स्टेट लिस्ट के सब्जैक्ट को भी लैजिसलेट कर सकती है और इसके लिए इस आर्टिकल में प्रोसीजर लेड–डाउन

है । मंत्री महोदय ने जो बात कही वह सदन को मिस– लीड करने वाली है कि भारत सरकार क्या कर सकती है (ई मैं कहना चाहता हूं कि इरीगेशन सब्जैक्ट के गवर्नमैंट आफ इंडिया अपने हाथ में ले सकती हए । इसलिए we absolutely doubt their intention, Sir. मेरी हम्बल सबमिशन है कि भारत सरकार खुद एस ० वाई ० एल० नहर को बना सकती है । मैं आपकी गाईडैन्स चाहता हूं कि यह बात गलत है या दुरूस्त है?

दूसरी बात का मुख्य मंत्री जी ने खोवे मटकाते हुए जवाब दे दिया । इन्होने कहा कि हम, सियासी लोगों के घरों में हजारों लोग आते रहते हैं । लेकिन चन्द्रावती जी के घर में आदमी गया है और इनको यह भी पता था कि एक ही आदमी को भेजा है । स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री के नाते अगर हजारों आदमी इनके पास आते हैं तो सैकड़ों हम से भी मिलते हैं लेकिन यह हमें पता है कि कौन आदमी भेजा हुआ है और कौन आदमी फरियाद या मुसीबत का मारा हुआ आया है ।

Mr. Speaker : I will talk to C.I.D. people.

श्री मंगल सैंन : स्पीकर सर, मैं आपकी सेवा में एक और सबमिशन करना चाहता हूं । आज जब मैं रजिस्टर पर साईन करने लगा तो वहीं पर एक सज्जन ने मेरे हाथ में एक कार्ड थमा दिया । कहने लगा कि आपको राति भोज पर बुलाया है । माननीय श्री अर्जुन सिंह, राज्यपाल, पंजाब, जो मध्य प्रदेश से यहां पर भेजे गये है, उनके सम्मान में और श्रीमती अर्जुन सिंह के

सम्मान में श्री भजन लाल मुख्य मंत्री और श्रीमती भजन लाल की ओर से उनके निवास स्थान कोठी नं ० 1 सैक्टर–3 चण्डीगढ में मंगलवार दिनांक 28 मार्च 1985 को सादर आमंत्रित हैं । स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय क्यों, राज्यपाल महोदय क्यों नहीं? बर्नी साहब का ईक्वल स्टेट्स है । यह तो पोलीटीकल आदमी हैं । राज्यपाल नान–पोलीटीकल आदमी होता है जो कांस्टीच्यशन के तहत अपॉयंट किया जाता है । यह बात दूसरी है, वे बीहेव कैसे भी करें, यह उनकी अपनी इच्छा पर है । स्पीकर साहब, चूकि यह बात आप के अधिकार क्षेल में आती है, इसलिये मैं यह बात आप के नोटिस में ला रहा हूं कि आप हमारे सैटीमैंट्स बर्नी साहब तक पहुंचा दें । इसकी कास्ट तो एक ही जगह से मीट होनी है, रोटी तो हौस्पिटैलिटी वालों ने ही खिलानी है चाहे राज भवन में खिला दें या वहां पर खिला दें लेकिन अच्छा होता अगर ऐसा इन्वीटेशन हरियाणा के राज्यपाल महोदय की तरफ से होता । उसमें एक अच्छा प्रैसीडैंट भी बना रह जाता और प्रोटोकोल भी यही है कि गवर्नर टू गवर्नर होना चाहिये, चीफ मिनिस्टर का नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, पहले तो आप सब यह कहते थे कि कोई खाना नह्यई हो रकु है । दूखरी बात यह है कि पंजाब में गवर्नर होने के अलावा उनके मुख्य मंजी जी के साथ पर्सनन ताल्लुकात भी हें ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर सर, पर्सनल ताल्लुकात का तो हमें पता नहीं है । स्पीकर साहब, मैं तो इसलिये कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर का स्टेट्स दूसरा होता और गबर्नर का दूसरा होता पे । स्पीकर साहब, मेरा कहना यह भी है कि गवर्नर महोदय मैम्बर्ज को एट होम भी देते रहे हैं । इस बार क्यों नहीं दिया गया? पता नहीं किस नाराजगी की वजह से नहीं दिया ।

चौधरी भजन लाल : कोई नाराजगी नहीं है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह गवर्नर ि गवर्नर होना चाहिये । मुख्य मंत्री जी की तरफ से नही होना चाहिए ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई बडा मेहमान हो या छोटा मेहमान ही, कोई भी इन्सान लाने पर उसको बुला सकता है । इसके लिये हमने अकेले डाक्टर साहब को ही नहीं, सारे हाउस के मैम्बर्ज को इन्वीटेशन भेजा हे और कहा है कि मेहरबानी करके उस खाने में जरूर शामिल हों । (व्यवधान व शोर).. गवर्नर साहब गर कोई पाबन्दी नहीं है कि वे कोई खाना नही दे सकतेय (व्यवधान व शोर) अगर किसी को अब तक इन्वीटेशन कार्ड न मिला हो तो मिल जायेगा । अगर न भी मिले तो भी मैं हाथ जोडकर अब सबसे यदु कह रहा हूं कि आज शान को 8 बजे मेरे घर खाने पर जरूर आयें क्या इससे बेहतर कोई रिक्वैस्ट हो सकती है ' अध्यक्ष महोदय, अर्जुन सिंह जी, रो बार मुख्य मंत्री रहे हैं और बहुत सालों तक हमारे साथी रहे हैं । हमने

उनके औनर में खाना अरेंज किया है । डाक्टर साहब, का इस बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है । डाक्टर साहब बड़े सीनियर मैम्बर हैं । डाक्टर साहब, अगर खाना खिलाना चाहे तो हम डाक्टर साहब का खाना भी खाने के लिये तैयार हैं आप हमें जब भी कहेंगे तो हम आपकी तरफ से खाना खाने के लिए तैयार हैं । (व्यवधान व शोर) दूसरे अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने एक बात मजाक में कह दी कि भजन लाल ने खौवे मटकाते हुए कुछ कहें. दिया । डाक्टर साहब, अब आपको क्या कहूं । खौवे मटकाने या हिलाने का आपको तो पता ही नहीं है । जो आदमी बाल बह मचा री हो, उसको हुस बारे में क्या पता होगा (हंसी) । आप इस झगड़े में क्यों पड़ा करते हो, आपको तो ऐसे झगड़ों में पड़ना ही नही चाहिये । (व्यवधान व शोर)

श्री मंगल सैन : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट रह गया । मैं सबमिशन करना चाहता हूं कि प्रैसीडैंट और प्रोटोकोल यह कहता है कि गवर्नर टू गवर्नर होना चाहिये । यह बात हो सक्ती है कि वे उनके दोस्त हों और इसके अलावा भी कोई दूसरी बातें हो सकती हैं । हो सकता है कि श्री राजीव गांधी जी ने इनसे पूछ कर उनके। यहां पर गवर्नर बनाया होगा । यह उनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए भी पसीना पसीना हो रहे थे । उस वक्त आपको बडी मेहनत करनी पड़ी थी । स्पीकर साहब, मुझे इनकी तरफ से बै से भोज देने में कोई एतराज नहीं हए लेकिन बात सिर्फ

प्रोटोकोल की है । मैं आपके द्वारा अपने सैंटीमैंट्स को बनी साहब तक कन्वे करना चाहता हूं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात माननीय सदस्य ने बार–बार एस ० वाई ० एल ० की चर्चा करते हुए कह दी । यह सब को पता है कि सब के सैटीमैंट्स इसके साथ जुडे हुए हैं । हरियाणा के बच्चे–बच्चे का हित इसके साथ जुड़ा हुआ है । हरेक मैम्बर यह चाहता है कि पड़ोस के प्रदेश में यह नहर जल्दी से जल्दी बने ताकि एस ० वाई ० एल ० का पानी हरियाणा के किसान को मिल सके और गांव–गांव में तरसते हुए लोगों तक पहुंच सके । जिस तरह से इन्होंने यहां पर उठकर यह प्वायंट रेज किया कि ऐसे माहौल में जिसमें प्रदेश का अहित होता हो तो भारत सरकार को अपने कन्ट्रोल में यह काम लेना चाहिए । इसमें कोई दो राय नही । उनकी यह बात बिल्कुल ठीक है लेकिन इसमें कुछ काम ऐसा होता है कि जो काम स्टेट गवर्नमैंट से ताल्लुक रखता है, वह काम उसी स्टेट गवर्नमैंट को करना होता है । जै से जमीन एक्वायर करनी थी । जमीन एक्वायर जब तक नहीं होती, तब तक आगे कोई काम नहीं हो सकता । इसलिए ऐसे काम में बड़ी मुश्किल आती है । फिर भी मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमने बार–बार भारत सरकार को यह कहा है कि आप मेहरबानी करके इस नहर को जल्दी से जल्दी बनवाओ । हमने इस नहर की कस्ट्रकशन में देरी के लिए उनको प्रोटैस्ट भी किया है । पहले तो हमने उनको यह कहा कि आप इसकी

क्स्ट्रक्शन का काम हमें करने दो । उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं बना सकते । हमने कहा कि फिर इसके लिए भारत सरकार खुद इन्तजाम करे । उन्होंने यह कहा कि भारत सरकार अभी नहीं बनाएगी । पहले हम पंजाब सरकार को यह मौका देंगे । अगर वह नहर नहीं बना सकेंगे और जान–बूझ कर देरी करेंगे तो भारत सरकार देखेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार हर तीसरे महीने एक–एक बात को देखती है कि नहर का काम कैसे चल रहा है । ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है । प्रगति में कोई रुकावट तो नहीं है और गति धीमी तो नहीं है । एक–एक बात को भारत सरकार देखती है । उनकी बाकायदा तसल्ली होती है, तब जाकर हम उनको आगे पैसा देते हैं । इसलिए मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि जितनी इस बारे में चिन्ता इस हाउस के मैम्बर्ज को है, उससे कहीं ज्यादा चिन्ता हमारी सरकार को है कि यह नहर जल्दी से जल्दी बने ताकि हरियाणा के किसान जो पानी की एक–एक बूद के लिए तरस रहे हैं, उनको पानी मिल सके । मैं कहता हूं कि आप विश्वास रखिए जहां तक हरियाणा के हितों ,का सवाल है, हरियाणा के हित श्री राजीव गांधी जी के हाथों में सुरक्षित हैं । वे भी यह चाहते हैं कि एस ० वाई० एल० नहर जल्दी से जल्दी बने । इसके लिए वे भी समय–समय पर इस बात को खुद देखते हैं । मैं सदन को केवल यही बताना चाहता था । (व्यवधान व शोर)

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, भारत सरकार के बिहाफ पर क्या मुख्य मंत्री महोदय इस हाउस को इस विषय में अश्योर कर सकते हैं '

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं अपने विश्वास पर कहता हूं और भारत सरकार भी पूरी कोशिश में है । भारत सरकार को इस बात के लिए पूरी चिन्ता है कि यह नहर बहुत जल्दी बने । (व्यवधान व शोर)

श्री मंगल सैन : स्पीकर सर, भारत सरकार अभी इस बात के लिए चिन्ता ही कर रही है । चार साल हो गए । एक प्रधान मंत्री चला गया और दूसरा प्रधान मंत्री आ गया । अभी चिन्ता ही कर रही है । (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लाल : सरदार लछमन सिंह जी और कई मैम्बर यह कहते हैं कि इस बजट में केवल 70 करोड़ रुपया इसके लिए रखा है । अध्यक्ष महोदय, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि 70 करोड़ तो हमने एक साल के लिए रखा है । इससे पहले हम 48 करोड़ रुपया दे चुके हैं । 70 और 48, 118 करोड़ रुपया हमारा खर्च हो जाएगा । हमारे हिस्से का 130 करोड़ रुपया है । अब 12 करोड़ रुपया केवल बचता है । बाकी का खर्चा पंजाब सरकार का शेयर है । उन्होंने भी अपना शेयर देना है क्योंकि पंजाब के कुछ एरियाज को भी यह नहर पानी देगी । जितना उनका शेयर बनता है, वह देंगे । इसके अलावा मैं एक और बात

कहना चाहता हूं कि अगर यह नहर एक साल में बनकर तैयार हो जाए तो हम दूसरे सारे काम बन्द करहे यो इसके लिए वाली का पैसा देंगे ताकि इस नहर के बनने में रुकावट न आए ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके जरिए बाईस चांसलर, एम० डी० यू ० को हटाया गया हैं । हमें पता लगा है कि हरियाणा सरकार चांसलर पर यह दबाव डाल रही है कि वे सूप्रीम कोर्ट में अपील करें । (व्यवधान एवं शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब कोई जजमैंट आती है तो जो आदमी हटाया गया हो, वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाता है । सरकार भी इसमें एक पार्टी है । सरकार पार्टी होने के नाते भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी क्योंकि हमने एक्ट को अमैंड किया था । उस अमैंडमैंट के बारे में हो सकता है हाई कोर्ट ने ठीक फैसला दिया हो । मैं नहीं कहता कि वह ठीक नहीं है क्योंकि कोई भी उसके ऊपर इल्जाम नही लगा सकता । सरकार को अपील दायर करने का हक है । अध्यक्ष महोदय, सरकार अपील दायर करने जा रही है ताकि जो ठीक बात इन्साफ की हो वह हो जाए ।

श्री हीरा नन्द आर्य : चांसलर पर आप दबाव क्यो डाल रहे हो?

चौधरी भजन लाल : दबाव डालने का कोई सवाल ही नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मेरा कैमीकल फैक्टरीज के बारे में सवाल था । उस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि दादरी, गुड़गांव और दूसरी जगहों पर इनकी हालत खराब है और ये बड़ी खतरनाक हालत में हैं । (विध्न)

श्री अध्यक्ष : मैंने फाइल मंगवाकर अच्छी तरह से देखा है और जो सवाल की इंगलिश ट्रांसलेशन की गई है वह एग्जैक्टली आपके सवाल के मुताबिक है ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि उसका सही ढंग से जवाब नहीं दिया गया तथा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर की बजाए इसका जवाब भी दूसरे मन्त्री ने दिया था ।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर्ज की ज्वांयट रिर्स्पासीबिलिटी होती है । एक मिनिस्टर जवाब दे या दूसरा जवाब दे इसमें कोई फर्क नहीं पडता ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, हरियाणा एक दिन भोपाल बन जाएगा । दादरी में, गुडूगांव में और दूसरी जगह फैक्टरीज की हालत खराब एं और इन कारखानों की वजह से हरियाणा एक दिन भोपाल बन जाएगा ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जिस दिन भोपाल का कांड हुआ था उसके बाद हमने सारी स्टेट में एक–एह फैक्टरी. को चौक करवाया था और पानीपत में जो भारत सरकार की फटीलाइजर फैक्टरी है उसको भी चौक करवाया । स्टेट में तीन सौ के करीब फैक्टरीज को हमने चौक करवाया था और हमने बाकायदा हिदायत दी हुई हैं कि अगर कहीं जरा भी सन्देह हो तो फिर चौक किया जाए ।

श्रीमती चन्द्रावती : आप एक दफा फिर चौक करवा लो ।

चौधरी भजन लाल : अभी दो महीने पहले ही चौक करवाई हैं । आप निश्चित रहें । दादरी, भिवानी और लोहारू कहीं पर भी कौई खतरा नहीं है । हमने इस काम के लिए ड्यूटी लगाई हुई है कि कहीं पर भी कोई. ऐसी बात न होने पाए ।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैंने हरियाणा एजूकेशन बोर्ड के बारे में एक काल अरैन्शन मोशन दी थी

श्री अध्यक्ष : वह मैं कंसिडर कर रहा हूं ।

मास्टर शिव प्रशाद : स्पीकर साहब, अम्बाला शहर में पीने का पानी नहीं मिलता और जो मिलता है वह बहुत ही गन्दा है और उसमें कीड़े हैं । इस बारे में मैंने एक काल अटैन्शन

मोशन दी थी । आज मैं उस पानी का सैम्पल भी ला या हूं और उसमें कीड़े दिखाई देते हैं । वह पानी पीने के लायक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैंने गवर्नमैंट के कमैन्ट्स मांगे हैं ।

मास्टर शिव प्रशाद : स्पीकर साहब, मेरा दूसरा काल अटैन्शन मोशन डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के कुछ हिस्सों जैसे कालका, सढौरा और बिलासपुर आदि में वर्षा न होने के कारण ड्राउट की कंडीशन के बारे में था ।

श्री अध्यक्ष : वह कल के लिए एडमिटिड है ।

प्रो ० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन, स्लैक कोल में तीन करोड़ रुपये के स्कैण्डल के बारे में भेजी है । उसके बारे में क्या पोजीशन है?

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में मैंने गवर्नमैंट के कमैन्टस मंगवा रखे हैं ।

चौधरी मांगे राम : स्पीकर साहब, बहादुरगढ़ में पीने के पानी की समस्या काफी गम्भीर है उसके– बारे में मैंने एक काल अटैन्शन मोशन भेजी है ।

श्री अध्यक्ष : आपने सुबह ही दी है । में उसको कसिडर करूंगा ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, चौधरी सम्पत सिंह ने कोल के स्कैण्डल की बात की है । जब स्कैण्डल की बात आती है तो उस का जवाब देना जरूरी हो जाता हैं । अध्यक्ष महोदय, बात क्या है कि इन साथियों का एक ही प्रोग्राम है कि पहले तो ये लोग अखबारों में लिखवाते हैं और अखबार भी ऐसे हैं जिन का मैं नाम नहीं लेना चाहता । स्पीकर साहब, पहले तो वे उन में लिखवाते हैं और फिर अखबार को हिला कर और उसका हवाला दे कर कहते हैं कि अखवार मे आया है कि ऐसा स्कैण्डल हुआ है । दो–तीन अखबार ऐसे हैं जब से मैं मुख्य मन्त्री बना है के यही कहते हैं कि भजन लाल आज गया कल गया । सीकर साहब, प्रजातन्त्र में अखबारों का एक बड़ा भारी रोल होता है (शोर एवं व्यवधान) । स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि दों–तीन अखबारों का यह रवैया है और वे अखबार अपनी प्रतिष्ठा को नहीं देखते कि गल्त बात लिखने से अखबार की प्रतिष्ठा को कितना धक्का लगेगा । स्पीकर साहब, पहले एक ट्रिब्यून में लिखता था लेकिन ट्रिब्यून वालों ने उसको हटा दिया । अब दो अखबार ऐसे हैं एक इंडियन ऐक्सप्रैस और दूसरा पंजाब केसरी । इनका एक ही सूत है कि अखबार में गल्त बात लिखवाई जाए और सरकार की प्रतिष्ठा को डैमेज किया जाए । इन दो अखबारों के पत्रकार इन अखबारों की प्रतिष्ठा कम करने पर लगे हुए हैं ।

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । स्पीकर साहब, क्या यह उन अखबारों का नाम लेकर उनको डिस्कस कर सकते हैं । (भोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : मैं नाम क्यों नहीं लूंगा । जब आप लोग उन में गल्त बात लिखवाते हैं तो मैं नाम क्यों नहीं लूंगा । स्पीकर साहब, आप के नोटिस में मैं पहले भी लाया था कि एक–दो बात आपने हाउस की कार्यवाही से निकाल दो लेकिन फिर भी उन अखबारों में छापी गई । ये अखबार कितनी गैर–जिम्मेदारी की बात लिखते हें । स्पीकर साहब, एक पत्रकार ने चार–चार जगह प्लाट ले रखे हैं चण्डीगढ में भी है, पंचकूला में भी है, फरीदाबाद में भी है ओर लुधियाना में भी हे । लोग अपनी तरफ तो देखते नन्हीं हैं । कोई बात अबरारों में लिखने से पहले इन्सान को अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए । स्वीकर साहब, अखबारों का एक रोन होग है, एक करैक्टर होता है । एक अच्छे अखबार को बेसलैस बात नहीं लिखनी चाहिए और ऐसी बेसलैस बातों की ओर लोग भी नहीं देखते हैं । लोग सोचते हैं कि यह बात इंडियन ऐक्वप्रैस में छपी है छोड़ो इसको यह बात पजांब केसरी में छपी है छोडो इसकी बेसलैस बात लिखने से अखबार का स्टैण्डर्ड गिरता है ।

स्पीकर साहब, जहां तक कोल स्कैंडल की बात है, आसाम से पिछले तीन साल में बहुत ही थोड़ा कोयला आया है । कोटे का कोयला बिहार और बंगाल से आता है । स्पीकर साहब,

आसाम से पिछले दो तीन साल में नाम मान कोयला . आया हे । बंगाल और बिहार के कोपलें के लिए लाटरी निकाल ते हैं और जिस का नाम लाटरी में निकलता है, उसी का नाम रिकमैड कर के भेज देते हैं । जहां तक आसाम मेघालय का सम्बन्ध है, वह अन–अनौटिंड है और 1980, 1981 से ही फर्स्ट–कम–फर्स्ट–सवर्ड के आधार पर आबेदन पत्र भेजे जाते रहे है । जिसकी दरख्वास्त पहले आई और जिसकी वाद में आई उसी तरह से रिकमैड कर के भेज दिया जाता है । स्पीकर साहब, जों भी एप्लीकेशन हमारे पास आई, उन को रजिस्टर में, दर्ज किया हुआ है । नम्बरवार सब की दरख्वास्तें भारत सरकार को भेज दी जाएंगी ताकि प्रदेश में कोयला आ सके । जिसने ऐप्लाई किया हमने रिकमैड कर के भेज देना है कोई ऐप्लीकेशन पैंडिंग नहीं रहेगी । किसी के साथ न कोई भेदभाव बरता गया है और न बरता जाएगा । जब भजन लाल किसी तरह से इन के काबू में नहीं आया तो इन्होंने एक सूती प्रोग्राम बनाया कि बेसलैस बातें अखबारों में छपवाओ जिससे सरकार की इमेज डैमेज हो । इस बात को इस देश के लोग जानते हैं । जो देश के पौलिटी– शियंज हैं वे सब इस बात को जानते हैं । स्पीकर साहब, बेबुनियाद बात लिखवाने का कोई फायदा नहीं । कभी यह कोई बात पंजाब केसरी में लिखवा देते हैं और कभी इंडियन ऐक्सप्रैस में । स्पीकर साहब, अखबारों की कोई मर्यादा होती है और उस मर्यादा और करैक्टर को कायम रखना सब का फर्ज है । इस लिए मेहरबानी कर के पहले गहराई में जाना चाहिए और फिर कोई बात छापनी चाहिए ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर महोदय, मैं यह समझती हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय ने यहां पर जो अखबारों का नाम मैन्शन किया है, यह कोई उचित बात नहीं है । स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने एक तरह से उन्हें धमकी दी है । लोगों के फण्डामैन्टल राईट्स की रखवाली करना, प्रैस वालों का एक बड़ा भारी रोल होता है, इसको फोर्थ एस्टेट मानते हैं । कहते हैं कि there is a very thin line between a good press correspondent and a good statesman. तो जनाब स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने इस तरह की बात कह कर कोई अच्छा उदाहरण नहीं दिया है । फिर यहां पर कोल की बात कही गयी । स्पीकर साहब, 1982–83 की औडिटर एण्ड कम्पट्रोलर जनरल आफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि 29 लाख 12 हकार रुपये की कीमत की कोयले ये भरी एक पूरी ट्रेन की ट्रेन ही गायब हो गई । इस लिए जो सरकार की कमियां हैं, सरकार की खामियां हैं, उनके बारे में यहां न बताएंगे तो यहां पर फिर किस लिये बैठे हैं? हम अपने प्र देश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए यहां पर बैठे हैं । चाहे सरकार को कितना ही बुरा लगे, हम तो लोगों के हितों के लिए बोलेंगे और बोलना हमारा फर्ज भी है । हमें कोई नहीं रोक सकता । जिस ढंग से यहां पर चीजें हो रही हैं, जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रैस वालों को धमकी दी है, वह गश्त बात है । मैं चाहूंगी कि यहां पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिएं ।

11.00 बजे

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री जगदीश नेहरा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब प्रैस वालों की यहां पर बात हुई थी तो विरोधी भाई पाक आउट कर के चले गए थे । उन्होने यह विरोध प्रकट किया था कि प्रैस वालों से सरकार नाजायज बर्ताव कर रही है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज के इंडियन ऐक्सप्रैस अखबार में लिखा है कि कल जब श्री मनचन्दा के दाह संस्कार के लिए जा रहे थे तो उस समय बी० जे० पी० के लोगों ने श्री आर ० पी ० शर्मा, फोटोग्राफर को मैन हैंडल किया और उस को पीटा और अब वह लोग यहां पर प्रैस के बारे में दुहाई देते हैं लेकिन खुद प्रैस फाटोग्राफर के साथ इन्होंने ने इस तरह का कल व्यवहार किया । इस लिए मैं आप के नोटिस में यह बात माना चाहता था कि एक तरफ तो यह खुद प्रैस वालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और दूसरी तरफ यहां सरकार का केवल क्रिटीसीजम करने के लिंए यह लांछन लगाते हैं कि सरकार प्रैस को धमकी देती हुं । यह तो यू ही मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, एक औनरेवल मैम्बर ने अपना काल अटैन्शन मोशन आपको भेजा और अपनी टर्न पर खत होकर ही उन्होंने यह अर्ज किया था और अपने काल अटैन्शन मोशन का सबंजैक्ट भी उन्होंने बताया That deals with coal scandal इस पर मुख्य मन्त्री महोदय ने खड़े होकर बड़ा भारी भाषण दे दिया । मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि शायद आप इनके मसले से गो थ्रु नहीं होंगे । इन्होंने यह नही कहा था कि

क्नेयला कोई खा गया है । इन्होंने यह कहा था कि फूड एण्ड एग्रीकलचर विभाग वालों ने ऐप्लीकेशन फारवर्ड कर दी – हैं और दस–दस फमें एक ही हाउस में लोकेटिड है ' उन सभी फर्मो का एक ही एड्रेस है और वे फमें एक पाई भी इन्कम टैक्स के तौर पर नहीं भरती हैं । करोड़ों रुपए के आर्डर प्लेस कर रखे हैं । ऐसी फर्मी को सरकार ने कोयले के परमिट दिए है । यह इन्होंने अपने कारन अटैन्शन में दिया है । इतनी सी बात पर मुल्य मन्त्री महोदय बड़े पारसा बन रहे है और कहते हैं कि नाम भाव कोयला आसाम से आया है । हम कहू सकते हें कि आया है । हम तो यह कहते हैं कि इनके फूड एण्ड एग्रीकलचर विमान ने ऐप्लीकेशन्ज फारवर्ड की हैं । स्पीकर साहब, कोल इंडिया को हम किन–किन लोगों की ऐप्लीकेशन्ज काल दिलवाने के लिए रिकमैड करते हैं, इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वे वे लोग हैं, जिनकी बल्कि एक–एक घर के अन्दर 15– 15 फमें हैं । एक ही नाम की फमें हैं कोई नई दिल्ली है, that smacks of the scandal ये जिस खबर का हवाला देकर कह रहे हैं, यह खबर आज की नहीं है । यह खबर आज से पाच दिन पहले की अखबारों में आई हुई है । हम ने इस बारे में कोई काल अटेन्शन मोशन मूव नहीं किया । हमने एक आदमी को बल्लभगढ में नई सड़क के पचे पर भेजा । स्पीकर साहब, आप भी किसी एक निष्पक्ष आदमी को यहां पर भेज वें तो आपको सारी स्थिति का पता लग जाएगा कि कितनी ऐसी फमें हैं, जिनके शम इन्होंने रिकमैड किये हैं और जो एक ही पत्ते, एक ही जगह पर विराजमान हैं । वे झड़प पड़े अखबारों के ऊपर

कि उन्होंने ऐसी यात की है । उनमें इंडियन ऐक्सप्रैस, पजांस केसरी है पहले ट्रिंब्यून भी हुआ करता था । एक जर्नलिस्ट इनको कंवीनिऐन्स के अनुसार न लिखता हो सब को अखबार का स्तर नीचा है और अगर उसका तबादाला हो जाए तो अखबार का स्टैण्डर्ड ऊंचा । जो जर्नलिस्ट इंडीपैनडैन्ट हो, इसके काबू में न आता हो, इनकी परचौजऐबल कोमोडिटी न हो और यह कुछ लिख दे तो उसका स्तर गिर जाता है । अब इन्होने अखबारों का नाम ले दिया कि भाई कौन सा अखबार है पंजाब केसरी रख दो, इसी तरह दूसरे अखबार के बारे में भी कहा । स्पीकर साहब, यह वही पंजाब केसरी अखबार है जिसने एक बार अपने ऐडीटोरियल मे यह लिखा था कि पंजाब को भजन लाल चाहिये । उस वक्त इन्होंने कहा कि बहुत प्यारा अखबार एं, बहुत प्यारा लगा अगर पंजाब केसरी यह छाप दे कि इनके फूड ऐण्ड एग्रीकलचर विभाग ने यह ऐप्लीकेशन फारवर्ड की हैं जो बोगस फमें थी, उनके नाम दे दिये, यह कह दिया कि हिस्सेदार बेनामी उन फर्मो में है किसी तरह का टैक्स तक अदा नहीं करती । तो इन बातों से उस जैसे अखबार का स्तर गिर जाता है । कितनी हैरानगी की बात है? (विध्न) स्पीकर साहब, ये हमें बोलने से नहीं रोक सकते । जितना क्रिटीसिजम इस बारे में हम कर सकते हैं करेगे एक्सपोज जितना हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हमें सरकार की कमियों को यहां हाउस में कहने का पूरा–पूरा हक है । इन्होंने हमारे ऊपर ये ऐलीगेशन लगाये कि हम लोग अखबारों में लिखवाते हैं । सर हमने कुछ नहीं लिखवाया । स्वयं इनके फूड एन्ड एग्रीकलचर

विभाग वालों से फिगर्ज मिली होंगी । वे विभाग इनके काबू में है, हमारे काबू में नहीं है । इनके फूड एण्ड एग्रीकलचर विभाग में मेरी दखल अन्दाजी नहीं है । डा ० मंगल सैन जी, चन्द्रावती जी और सम्पत सिंह की उनमें किसी तरह की दखल– अन्दाजी नहीं ऐं । जो विभाग इनके काबू मैं है अगर वहां से किसी जर्नलिस्ट ने कोई फैक्टस ले लिये और अपने अखबार में छाप दिये तो अब क्या चीफ मिनिस्टर साहब इससे इन्कार करने की हिम्मत रखते हैं? क्या ये इन्कार कर सकते हैं कि जो दरखास्तें इन्होंने कोल इंडिया को कोल के वितरण के लिए रिकमैड करके भेजी हैं और अखबारों ये जो इस बारे में छपा है, वह गलत है? क्या यह कहने की वे हिम्मत रखते हैं? स्पीकर साहब, यह किसी बात को छुपा नही सकते क्योंकि ये जो डाकूमैंन्टस हैं, वे अखबार वालों के कब्जे में युग चुके हैं उसको क्या ये डिनाई कर सकते हैं ? सीकर साहब, ये ऐसा नहीं कर सकते ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, ये सारी बाते तो पहले आ ही चुकी हैं । इनको दोहराने का क्या मतलब. है? कितनी देर तक ये बातें कहते रहेगे? हमें भी इसका जबाव देना पड़ेगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं कहना हूं कि वे डाकूमैन्टस अखबार वालों के पास पहुंच चुके हैं । क्या आप इससे डिनाई कर सकते हैं? आप यह बताए कि जो लिस्ट अखबारों में छपी है, क्या आप उससे डिनाई करते हैं? मैं यह गुजारिश करूंगा

कि हम तो उस डिपार्टमैन्ट तक पहुंच नहीं सकते लेकिन एक जर्नलिस्ट ने यह छाप दिया और अब उसका स्तर इनकी नजरों में गिर गया और उसके पीछे भी अब ये पड़ जाएगे । इन्होंने किस नफरत के साथ हमें ऐड्रेस किया है, किस कंटैम्पचुअस वे में ऐडैरस किया है कि ये लोग, वे लोग । यह कौई प्रोपर वे नहीं है और स्पीकर साहब, अगर हम यूं ऐडैरस करनें लगें तो हमारी आत्मा नही मानती, हम तो इज्जत से बोलते है । मुख्य मन्त्री कहते हैं, चौधरी साहब कहकर बुलाते हैं और ये यू एंड्रैस करें, ये लोग, वे लोग, यह नकाबले बर्दाश्त है और मैं इसके लिए आपसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह की इनकी टोन को बन्द करवाया जाए । We take strong exception to that. This is not proper.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, इस सदन में सदस्यों को बत करने के लिए एक नियमावली है जिसका नाम रुल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडकट अरफ विजनैस इन हरियाणा असैम्बली है । इसके रूल 73 में हमेंको यह अधिकार है कि हम काल अटैन्शन मोशन मूव करें । कवैश्चन आवर के तुरन्त बाद और अगला बिजनैस शुरू करने से पहले हम आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कर सकते हैं और निवेदन कर सकते हैं कि हमारे मोशन का क् ग बना । हमारे आनरेबल साथी प्रो० सम्पत सिंह ने गक सबजैक्ट उठाना चाहा जिस पर मुख्य मन्त्री आग बबूला हो गये । He lost his temper. डैमोक्रेसी में प्रैस चौथी एस्टेट है । इन्होंने अपने कह से कहा कि 4– 4 प्लाट अलाट करवाए हुए हैं । कोई पंचकूला में

है और कोई फरीदाबाद में है । इन्होंने कहा कि बहुत घटिया स्तर के लोग हैं, इन्होंने प्रैस को कंडैम किया । मैंने उस समय प्वांयट आफ आर्डर के जरिये निवेदन करना चाहा था कि इस हाउस में जो अपने आपको डिफैड नही कर सकता है उस पर हमला नहीं करना चाहिए । आपने कहा था कि मुख्य मन्त्री में चारे को इतनी तो रियायत दे दो । (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने बे चारा नहीं कहा ।

श्री मंगल सैन : आपने बेचारा नहीं कहा होगा तो समझा होगा । हमारी समझ में शायद फर्क हो गया होगा । स्पीकर साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यी कहना कि 4– 4 प्लाट लिए हुए हैं ठीक नहीं है । मुख्य मन्त्री ने खुद अपने नाम से प्लाट ले रखा है । उन लोगों की तो शायद जायदाद भी नहीं होगी लेकिन ये तो साहब जायदाद हैं । किसने प्लाट दिया है, अगर किसी ने दिया कुए तो किस मोटिव से दिया है । क्या उनको मुलायम करने के लिए दिया था या उनको परचेज करने की कोशिश की थी या कोई और खतरा था । वह ईमानदार आदमी था इनके चक्क र में नहीं आया । इसलिए हम इनके एटीब्यूड को हाइली कंडैम करते हैं जो इन्होंने फो रथ एस्टेट के बारे मैं कह है । हमने इनकी बात बर्दाश्त की है और ये हमारी बात भी सहन करें । मेरी हम्बल सबमिशन यह है कि इस तरह से बात करना और प्रैस वालों को धमकाने की कोशिश करने का इनको यही मतलब है कि शायद वे इनके काबू मैं आ जाएं । इनकी यहां पर

ऐसी भी स्टेटमैंट आई है कि ट्रिब्यून में एक कौरसपौडैंट होता था अब उसको ठिकाने पर लगा दया है । स्पीकर साहब ये अपनी अडवरटाइजमैंट पालिसी के माध्यम से प्रैस बालो को धमकाते हैं कि तुम्हारी एडवरटाइजमैंट रोक दी जाएगी और भूखे मरोगे वरना फलां कौरसपौडैंट को बदल दो । हमने पिछले सैमन में भी कोशिश की थीं इस मामले को उठाने की लेकिन हमारी बात उस समय किसी वजह से बीच में रह गई थी । सीकर साहब, मुख्य मन्त्री के डस एटीच्यूड को जितनी निन्दा की जाए उतनी बोड़ी है । ये हमें वे लोग कहते हैं, हम भी इन्हें बइ मुख्य मन्ली कहते हैं । हम तो हमेशा इनको आदरणीय मुख्य मन्त्री कहते हैं और सदन के नेता कहते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी टची हो जाते हैं । अगर ये इतने नाजुक है तो हाई कोर्ट का एक जज बिठा दें और एफीडेविट दें । अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो प्रैस को धमकाया गया है इसे हम स्ट्रोगली कंडैम करते है ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब की बात कर मुझे बडा सीरियस आबजैकशन है । चीफ मिनिस्टर साहब बड़े नर्म दिल हैं ये ऐसी बातें नहीं कहते । लेकिन इन्होने आव गुस्से में आकर अखबारों के बारे में ऐसी बातें कह दी । आज पंजाब केसरी अखबार एक नम्बर पर है और नव भारत टाइम्ज दो नम्बर पर है । इनकी सरकुलेशन सादे चार लाख की है । में इनको एक ही बाल कहूंगा कि ये अपने लफ्ज वापिस लें । अखबार डैमोक्रेसी का एक अंग है । इन्होंने 1975 में एमरजैंसी के

दौरान अखबारों पर पाबन्दी लगाई थी गैर ये अपना राज गंवा बैठे थे । इसलिए अखबार वालों को धमकाना ठीक नहीं है । हो सकता है ये ऐसी बात न कहना चाहते हों लेकिन हीट आफ मोंमैंट पर कह गए होंगे । इसलिए अपने लफज वापिस ले ले तो कोई हर्ज नहीं है ।

चौधरी तव्यब हुसैन : स्पीकर साहब, गूफ्त गू का जो रवैया चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनाया है वह बहुत न मुनासिब है । इस तरह से अखबार वालों को धमकाना और बुरे अलफाज कहना ठीक नहीं है । जहां तक कोल स्कैंडल का सिलसिला है उसके बारे में शायद ये खुद भी बताएंगे । मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले इसका लाटरी सिस्टम था लेकिन इन केस में इन्होंने खास तौर पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वम् वाली बात की । पहले वाला सिस्टम बदला क्यों गया । कोरसपोंडैट ने सही बात लिखी इसलिये ये ऐसी बात कह गए । वह तो आज भी वही बात कहते हैं । मैं समझना हूं कि प्रैस के लिए धमकी की बात मुनासिब नहीं है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था । (शोर)

श्री अध्यक्ष : उस बारे में मैने आपको बताया था कि वह गवर्नमैंट को कमैंट्ड के लिए भेजा हुआ है । '

(इस समय बहुत से विपक्षी सदस्य बोलने के लिए खडे हो गए)

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब आप सर कृपया बैठ जहर । मैंने सभी पार्टीज के लीडर्ज को अपनी अपनी जल कहने का मौका दे दिया है ताकि किसी के मन में कोई ऐसी रात न रहे ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, मेरा प्यांयट आफ आर्डर है । स्पीकर साहव, जिस काम अटैन्शन मोशन पर आपने गवर्नमैंट के कमैंट्स मांगे हैं, उस पर हम तो अपनी बात नहीं कह पाए कि कोयले का स्कैंडल है लेकिन उसी विषय में मुख्य मन्त्री जी सब कुछ कह गए? (शोर)

श्री अध्यक्ष : एक–एक मैम्बर को एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं कैसे टाइम दे सकता हूं । इसी बात को देखकर मैंने सभी पार्टीज के लीडर्ज को टाईम दिया है ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साइज, मैं शुरु में आपके नोटिस में लाया था कि इस विषय पर मैंने अपना काल अटैन्शन मोशन दिया हुआ है । आपने कहा कि मैंने इस पर कमैंट्स मांगे है । स्पीकर साहब, हम जब भी कोई बात करते हैं तो फैक्टस के साथ करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने बड़ी डिटेल में बात कह दी' है. । उसमें सारी बातें आ गई हैं इसलिए आप बैठे ।

प्रो ० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, पैसे का जिक्र करते करते बीच मे प्लाटों का जिक्र आ गया था । मैं कलैरिफिकेशन चाहता हुं कि जो प्लाट लुधियाना, फरीदाबाद और पंचकुला में ले रखें हैं वे किस ने ले रखे हैं? (शोर)

श्री अध्यक्ष : वह मैं आपको बता दूंगा । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रैस को ले करके कई माननीय सदस्यों ने काफी जोरदार भाषण दिया । उन्होंने जोरदार भाषण इसलिए दिया ताकि वे प्रैस से ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी हासिल कर लें । इसी मकसद के लिए उन्होंने भाषण दिया । मेरे अपोजीशन के भाईयों ने यह भी कहा कि सरकार प्रैस को खरीदना चाहती है । अध्यस्त महोदय, यह बात आप भी जानते हैं कि इन्होंने ऐसी बात कह करके प्रैस का कितना अपमान किया है । (शोर) आपने यह कहा कि सरकार प्रैस को परचेज करना चाहते थी । इससे ज्यादा तोहीन प्रैस की नहीं हो सकती । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहुंगा कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह और डा० मंगल सैन को ये लकब वापिस लेने चाहिए उन्होंने ऐसी बात कह करके प्रैस की बड़ी भारी तौहीन की है । यदि मैं कोई और वात कहूंगा तो फिर वे कुछ और बात कहेंगे । अध्यक्ष

महोदय, इनकी यह नीति रही है और मेरे पास इनके कारनामों के फोटो तक हैं कि किस तरह से ये लोग दो तीन प्रैस रिपोर्टर्ज को हर वक्त जहां चाहे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं । मैं हाउस में यह फोटो पेश कर सकता हूं । अध्यक्ष महोदय, उन अखबारों की वटी भारी प्रतिका है । उन अखवारों के मालिकों ने इस देश की आजादी के लिए बड़ी–बड़ी कुर्बानियां दी हैं और जेल काटी हैं । लाला जगत नारायण, जिन्होंने देश की आजादी के लिए जेल काटी थी छोर उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़े कदम उठाए थे । आप सभी को यह याद होगा कि उनकी कितनी कुर्बानी है उन्होंने अपनी कलम से ठीक बात लिख करके अपनी जान तक की परवाह नहीं की । मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि कुछ अखबारों के पत्रकार ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अखबारों की प्रतिष्ठा को गिराने में लगे हुए हैं । जो इंडियन एक्सप्रैस अखबार है यह कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है । इस अखबार के मालिकों ने भी देश की आजादी के लिंए जेल काट. रखी है । लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो उन अखबारों में रह करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन अखबारों की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं । उनको इस बात का लाईसैसं नहीं मिला हुआ है कि जो मर्जी आए वह लिख दें । (शोर एव विध्न) हमने आपकी बातों को शांति से सुना है इसलिए आप शांति से सुने । में इन अखबारों की आपसे कहीं ज्यादा कद करता हूं । (शोर)

Shri Mangal Sein : You can go to the court.

चौधरी भजन लाल : कुछ मर्यादाएं होती हैं । हर वक्त कोर्ट में जाने की बातें नहीं होती । ऐ सा भी नही होना चाहिए कि अखबारों में आपकी मर्जी आए बह लिखवा दें । मैं फिर यह बात कहता हूं कि क्उछ पत्रकार ऐसे हैँ जो अखबारों. की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं और प्रतिष्ठा को गिराने में लगे हुए हैं । यह उन अखबारों के मालिकों को देखना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भी कहता हूं कि मैंने जो बात कह दी है वह ठीक है उन अखबारों के मालिकों को इस बारे में जरुर देखना पड़ेगा । इसके अलावा इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि साहब हमने उन फर्मो के नाम दिए हैं । मैंनै अखबारों में उनके नाम पढे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बाकायदा लाटरी सिस्टम होता है । उस जगह के लिए जहां से कोटे का कोयला आता है । मैं कहना चाहुंगा कि पिछले तीन साल से आसाम से कोयला बहुत कम आया है । हमने मीटिंग करके यह फैसला किया कि किसी तरह से आसाम से भी हमारे यहां कोयला आना चाहिए । इसलिए एडवरटाईज कर दिया कि यदि कोई आदमी आसाम सैं कोयला लाना चाहे तो वह हमें एप्लीकेशन दे हम रिकमैड करके वहां पर एप्लीकेशन भेज देगे और हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंज आई वे सारी की सारी हम वहां पर भेज देंगे ताकि वह कोयला ला सके । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरुर कहना चाहूंगा कि जो आदमी जिस माहौल में पला है वैसी ही बात कहेगा, जो इन्सान जिस माहौल में रहा है वैसे ही उसके इरादे होंगें और जो इन्सान जिस

माहौल में पढ़ा है वैसी ही बात कहेगा । इनके पास ऐसी बातें कहने के सिवाय दूसरी बात कोई नहीं है । इनको अपना जमाना याद आता है । ये अपने जमाने में लोगों को शराब के ठेके तक अलाट करते थे । (शोर)

डा० भीम सिंह दहिया : स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मैं आपकी रुलिंग चाहूंगा । मुख्य मत्री जी को हमारी बातों का जवाब देना चाहिए इनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि जो आदमी जिस माहौल में पला है वैसी ही बात कहेगा, कोई भी बात जब सदन के सामने आती है, चाहे वह काल अटैशन मोशन का जवाब देने. की है चाहे एडजर्नमैंट मोशन का जवाब देने की है उसका जवाब देना चाहिए लेकिन मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देने की बजाय हम किस माहौल में पले हैं क्या हमारे इरादे ई इस बारे में बोल रहे हैं । मैं आपके द्वारा इनसे कहना चाहूंगा कि हमने जो बातें कही हैं आप उनका जवाब दें । स्पीकर साहब, आप मुख्य मंत्री जी को समझाएं कि वे हमारी बातों का जवाब दें । हम किस माहौल में पले हैं और क्या हमारे इरादे. पैं और क्या हमारा दिमाग है इन बातों को छोड़ दे ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको बताना तो पड़ेगा ही । मैं ज्यादा न कहते हए इतना ही कहूंगा कि मदन की मर्यादा को कायम रखना चाहिए । ऐसे ही कोई बात नहीं कहनी चाहिए । जब भी आप खड़े होकर सदन के अन्दर कोई बात कहें

उस समय परमात्मा को सामने रखकर ठीक बात कहें ताकि सदन कीं मर्यादा कायम रह ।

श्री अध्यक्ष : अब बजट की डिमांडज पर चर्चा होगी ।

वर्ष 1985– 86 के बजट की डिमांडज कार ग्रांटस पर चर्चा

तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब वर्ष 1985–86 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर डिस्कशन होगी । पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाईम बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी । आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर बोल सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलनी चाहते ही ।

That a sum not exceeding Rs. 7,62,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1985-86 in respect of charges under Demand No. 4 Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 31,30,83,000 for revenue expenditure and Rs. 38,44,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1985-86 in respect of charges under Demand No. 8 Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 74.94,49,000 for revenue expenditure and Rs. 1,37,32.75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1985-86 in respect of charges under Demand No. 15 Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 43,33,26,000 for revenue expenditure and Rs. 4,00,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charge; that will come in the course of payment for the year 1985-86 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum of exceeding Rs. 13,45,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1985-85 in respect of charges under. Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 34,89,37,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of paymerit for the year 1985-86 in respect of charges under Demand No.21 Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 5,93,84,000 for revenue expenditure and Rs. 5,52,52,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1985-86 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मेरी एक अर्ज है कि सभी डिमांडज पर इक्ट्ठी ही डिस्कशन हो जाए । कुछ मैम्बर्ज नए

हैं उनको पता नहीं लगता इसलिए इक्ट्ठी ही डिस्कशन हो जाए तो ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : डिमान्डज पर डिस्कशन दो दिन रखी है । आधी डिमाण्डज आज रखी हैं और आधी कल के लिए रखी है!

श्रीमती चन्द्रावती : डिस्कशन मिल जुल कर हो जाए तो ठीक रहेगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि सब पर डिस्कशन इक्ट्ठी हो जाए ।

श्री अध्यक्ष : जो डिमाण्डज आज के आर्डर पेपर पर हैं, उन पर इक्टठी डिस्कशन कर सकते हैं

ठाकुर बहादुर सिंह (दडबा कलां) : आनरेबल स्पीकर साहब, आपने मुझे डिमांडज पर ओलने का मांका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद । आज जितनी भी डिमांडज इस पेपर में रखी हुई हैं वे तकरीबन सारी की सारी एग्रीकल्चर से लिंकड हैं इसलिए सभी डिमांडज के बारे में मेरे मुंह से बातें निकल ही जाएंगी । मैं खास करके रिमांड नम्बर 8 डिमांड नम्बर 15 जोकि इरीगेशन के बारे में है, डिमांड नम्बर 17 जोकि एग्रीकल्चर के यारे में है और डिमांड नम्बर 18 एनीमल हसबैंडरी के बारे में है और इसी तरह से डिमांड नम्वर 22 कोआप्रेशन के बारे में है ये सारी की सारी डिमांडज एग्रीकल्चर से लिंकड हैं इसलिए में इन सभी डिमांडज के वारे में अपने विचार प्रकट करूंगा । (इस समय भी उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमांड नम्बर छ है

यह बिल्डिगज एंड रोडज के सारे में है । बिल्डिंगज एंड रोडज प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । हमारे प्रदेश में बहुत सी सडकें बनी लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने पहले भी अर्थ किया था कि हमारी बहुत सी सबके जो बहुत लम्बाई में एक प्वायंट से चलती हैं और वे एक दूसरी के पैरलल चलती हैं उनको सिंक रोड से जोरने का प्रावधान किया जाए उन सरको को लिंक रोड द्वारा जोड़े जाने से हमारे प्रदेश के एग्रीकल्चर सैक्टर में और इंडस्ट्रीयल सैक्टर में हर लिहाज से हमें रोजमर्रा के कामों में तरक्की मिलेगी । उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के साथ साथ बिल्डिगों का मामला है । हमारे प्रदेश के हर मांद में हम आज देखते हैं कि हर गांव में चाहे कोई लय सैंटर की बिल्डिंग है चाहे स्कूलों की बिल्डिंग है ये सारी पी० डब्ल्यू० डी० बसा रहा है । कई जगहो पर इस तरह के काम पी० डल्ब्यू० डी० ने किए हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं प्रदेश के फायदे के लिए, प्रदेश के हित के लिए और किसानों के फायदे और हित के लिए थोड़े से सुझाव देना चाहूंगा । हमारे कर्मचारियों और सरकार की तरफ से कोशिश होती है कि काम की बेहतरीन परफारमैंस हों और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फालदा मिले । डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल्डिंग सरकार की तरफ से बनाई जाती हैं उनमें कुछ कमी रह जाती है । यह कमी या तुाए हमारे कर्मचारियों की लापरवाही से रहती है या ठेकेदार की लापरवाही से रहती है । हमारे डैमोक्रेटिक देश के अन्दर डैमोक्रंटिक तरीके से गांवों में पचायतें बनाई गई हैं । सारे गांव के लोग मिलकर अपनी पंचायत चुनते हैं । मेरा

कहना यह है कि जो बिल्डिंग या रोडज गांवों के एरिया में बनाई जाएं उसमें पंचायतों को भी शामिल कर लिया जाये । जब कोई रोड या बिल्डिंग गांव में पूरी होती है तो कम्पलीशन के समय गाय की पंचायत के या नम्बरदार वगैरा के दस्तखत करा लिए जाएं कि गांव में फलां काम पूरा हो गया है । ऐसा होने पर हमारी भी यह शिकायत्त दूर हो जाएगी कि बिल्डिंग ठीक नहीं बनी । जब लोग हमसे पूछेंगे कि बिल्डिंग ठीक नहीं है तो फिर हम उनसे कह सकते हैं कि भाई आपके गांव के सरपंच ने इस काम के ठीक होने पर दस्तखत किए हैं, हम क्या करें और पंचायत ने सर्टिफिकेट दिया है । मैं तो यह समझता हूं कि जो रुपया इस मांग के जरिए मांगा गया है अगर इससे ज्यादा भी मांग लिया जाए तो कोई हर्ज नही है । मैं इस डिमांड का पूरी तरह से समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही यह भी अर्ज करता हूं कि जो भी कक्ट्रैक्शन का वर्क गांव की सीमा में हो उसके बारे में गांव के एक यूनिट माना जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमाड नं. 15 जो इरीगेशन से सम्बन्धित है, बोलना चाहता हूं । इरीगेशन का मामला बहुत अहम मामला है । हमारा प्रदेश ज्यादातर कृषि पर निर्भर करता है । खेती के लिए पानी सबसे जरूरी बात है । बदकिस्मती से हमारी एस० वाई०एल० जो बहुत पहले बन कर तैयार होनी थी, वह आज तक तैयार नहीं हो सकी ' है । अब हमें आई० पी० एम ० साहब के कहने पर आशा बंधी है कि यह नहर

दो साल में कम्पलीट हो जाएगी । इस नहर की खुदाई के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है । इस मामले पर वहुत सी बातें होती रहीं । बहुत से साथियों ने इस. अहम मसले को आरोपों की शक्ल में लेकर अपनी बाते यहां पर कही हैं । इन' साथियों द्वारा आरोप लगामें पर सरकार ने ज्यादा समय इनका जवाब देने में लगाया । यह बहुत अहम मसला है । हमारे प्रदेश में नहरों के जरिए सिंचाई करने के सिर्फ दो ही साधन हैं । एक भाखड़ा कैनाल और दूसरे वैस्ट्रर्न जमना कैनाल । भाखडा कैनाल के जरिए हमें 9600 कयूसिक पानी मिलता है और वैस्ट्रर्न जमना कैनाल से मेरे ख्याल में सिर्फ 2000 क्यूसिक पानी ही हमें मिल पाता है । बारिश के दिनों में तो काफी पानी बैस्टर्न जमना कैनाल से मिल जाता है लेकिन वैसे बहुत कम पानी मिलता है । इस कैनाल के जरिए 2000 क्यूसिक पानी मिल जाना बहुत कम है । ऐसे कृषि प्रधान प्रदेश के लिए पानी बहूत जरुरी है । मैं सरकार सैं निवेदन करूंगा कि जब तक एस० वाई० एल० तैयार नहीं हो जाती जो आल्टरनेटीव अरेंजमैंट हमारे किसानों ने सिंचाई के लिए किए हुए हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए । बजट के अन्दर हमारे वित्त मती जी ने साढ़े सात हार्स पावर वाली मोटरों पर से सेल्ज टैक्स खत्म कर दिया है । यह टैक्स खत्म करके सरकार ने एक अच्छा काम किया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारे सात हार्स पावर की मोटर से पानी उठाने वाले किसान को और साढ़े बारह पावर की मोटर से पानी उठाने वाले किसानों को अपनी उपज के कोई कम या ज्यादा दाम नहीं मिलते

। अब कनक का भाव 157 रुपये किवटल फिक्स किया गया है । मैं बताना चाहूंगा कि साढ़े सात हार्स पावर वाली मोटर से खेती करने वाले किसान को भी कनक का भाव 157 रुपये क्विंटल मिलेगा और साढ़े बारह हार्स पावर वाली मोटर से खेती करने वाले किसान को भी 157 रुपये ही एक किवटल पर मिलेगे । किसानों को एस ० वाई० एल० आने की बहुत आशाएं बन्धी हुए है। जब तक यह एस ०वाई०एल० नहीं तैयार होती तब तक किसानों मैं अपने प्रबंध किए हुए हैं । किसानों ने 100– 100 फुट से अधिक गहराई पर ट्यूबवैल आदि लगा कर आबपाशी के साधन बनाये हुए है । मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस एरिया में 100 फुट से ऊपर तानी उठाया जाता है उस एरिया मैं कुछ रियायत सरकार नैं बशु के किसानों को बिजली की दरों में दी हुई है । मैं यहां पर यह भी बताना चाहूगा कि हिसार और सिरसा का भी बहुत सा इलाका ऐसा है जहा पर 100 फुट की गहराई से ज्यादा पानी ऊपर उठाया जा रहा है लेकिन उस एरिया में सरकार ने कोई रियायत नहीं दे रखी । इसलिए मेरी आई० पी० एम ० साहब से प्रार्थना है कि जहां पर साढ़े बारह हार्स पावर की मोटरें लगी हुई हैं, वहां पर भी किसानों को रियायतें दी जाए । डिप्टी स्पीकर साहब हुमारे प्रदेश में दो ही तरीकों से सिंचाई की जाती है । एक नहर के द्वारा औंर दूसरी ट्यूबवैलों कई जरिए । घग्गर का पानी बारिश के दिनों में हमारे इलाके में तबाही पैदा करता है । इस पानी का फायदा उठाने के लिए आज तक कोई स्कीम नहीं बनाई गई है । कुछ

समय पहले आई० पी० एम० साहब हमारे इलाके में गए थे । मैंने आई० पी ० एम० साहब को वह साइट दिखाई थी जहां पर घग्गर के पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन मैं नहीं समझता कि क्या कमी' रही और क्यों नहीं उसका कोई प्रबंध हो पाया? मैंने बताया था कि गंगूर माइनर घग्गर नदी के साथ टच होती है । मैंने सुझाव दिया था कि घग्गर के पानी को इकट्ठा करके गंगूर माइनर के जरिए प्रयोग में लाया जा सकता है । मैंने बड़ी अच्छी तन्य से सुझाव दिया था कि बारिश के दिनों 'के बाद इस घग्गर के 'पानी को उठा कर इस माइनर में डाल कर 10— 15 गावों को पानी दिया जा सकता है । दूसरा मेरा सुझाव यह था कि मुसाहवाला के पास एक नहर वनाई जाये जिससे पानी को लिफ्ट करके 500 क्यूसिक की एक नहर बनाई जाये । वहां पर से 4 नहरें गजरती हैं । मेरे कद्रुने का मतलब यह है कि घग्गर के पली को बारिश के दिनों मे इकट्ठा कर लिया जाये और बाद में जब पानी की जरूरत हो तो किसानों को दे दिया जाये । मैं चाहूंगा कि सरकार घग्गर दरिया का पानी इस्तेमाल करने के लिए अपने इन्जीनियरों से एक स्कीम बनवाये जिससे इस दरिया का पानी इस्तेमाल हो सके । इसी तरह से एक स्कीम राजस्थान कैनाल के बारे में दी थी । डिप्टी स्पीकर साहब, राजस्थान कैनाल की पानी की बहुत बड़ी कैपेसिटी है । आज के दिन सिरसा और हिसार पानी के बिना प्यासा है । हिसार और सिरसा जिले के अन्दर भाखडा नहर के जरिए पानी आता है । यह पानी भी फतेहाबाद ब्रांच से आता है । फतेहाबाद साच की पानी की ज्यादा कैपेसिटी

नहीं होने की वजह से हमारे इलाके को पूरा पानी नहीं मिल पाता । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल की जो बहुत बड़ी मात्रा में पानी की कैपेसिटी है, उसमें पानी की माता को बढ़ा कर और उसमें से यानि राजस्थान कैनाल हैं से एक अलग नहर निकाल कर उस एरिया वे पानी पहुंचाया जाये ताकि वहां पर भी पूरी माता में पानी पहुंच सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं ० 17 जो एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के बारे में है, कुछ कहना चाहूंगा । पिछले साल एग्रीकल्चर के लिए 71 लाख रुपये रखे गए थे और इस साल 75. 1 लाख रुपया रखे गए है । यह ठीक है कि सरकार ने कृषि के लिए किसानों को बहुत सुविधाएं प्रदान की हैं । उसी के फलस्वरूप आज किसानों की मेहनत का नतीजा है जिसके कारण हमारी उपज बढ़ी हे । इसके अलावा इस काम में को–आप्रेटिव सोसायटीज का भी बड़ा भारी योगदान कृषि की उपज बढ़ाने में रहा है क्योंकि इन सोसायटीज के जरिए किसानों को समय पर अच्छा बीज और अच्छी खाद मिल पाई है । जो सुविधायें किसानों को दी है, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अन्दाजा लगाया है इस साल 85 लाख टन गन्ना और 8 लाख कोटन की गांठें पैदा होंगी । लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज एग्रीकल्वर की कोस्ट आफ प्रोडक्शन बहुत बढ गई है । कोस्ट आफ प्रोडक्शन कम करने में शायद सरकार ज्यादा सहायता नहीं कर पायेगी, लेकिन एक चीज की तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो

किसानों को बहुत फायदा हो जायेगा । किसान को अपने ट्रैक्टर का कोई पार्ट लाने के लिए या छोटी मोटी कोई चीज रगने के लिए शहर जाना पड़ता है और इस छोटे से कुम के लिए खाहमखाह कई कई चक्कर लगाने पड़ते है । इन चक्करों में किसान का खर्चा काफी बढ़ जाता है । मैं चाहता हूं कि इस खर्चे को किमी तरह कम किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाइंड अप करें ।

ठाकुर बहादुर सिंह : अभी खत्म करता हूं जी । मैं इस सिलसिले में एक सुझाव दूंगा । किसान को वन–विडो–सर्विस दी जाए । किसान के गांव को एक यूनिट मान लिया जाए । उसी गांव में एक ही विंडो से खाद मिले, परमिट मिले और पैस्टिसाईड्व मिले । आज ट्रैक्टर और ट्यूबवैल्ज पर बहुत ज्यादा एक्सपैडीचर आ रहा है जिसके लिए किसान को महर जाना पड़ता है । हम असैंशियल कमोडिटिज के लिए सस्ती दुकानें खोलते हैं । इसी तरह से मैं चाहूंगा कि गांवों में भी हैफेड या किसी दूसरी एजैसी के जरिये से किसान के लिए सस्ते दामों पर ट्रैक्टर और ट्यूबवैल के स्पेयर पार्टस खरीदने के लिए एक वर्कशाप का इन्तजाम कर दिया जाए । इसका क्राइटेरिया यह हो जागा कि जिस गांव में 20 से ज्यादा ट्यूबवैल या ट्रैक्टर्ज होंगे, वहां यह वर्कशाप खोली जाएगी । इससे किसान का बहुत–सा पैसा बच जाएगा जिससे किसान को बहुत राहत मिलेगी । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, विलेज को एक यूनिट माना गया है जिस में

डैमोक्रैटिक–वे से पंचायतें बनी हुई हैं । मेरे इलाके में जो माईनर लगती है, उसकी टेल से यह शिकायत आती रहती है कि उनको पूरा पानी नही मिला है । इसका कारण यह हद कि गेज की रिपोर्ट गेज–रीडर सही तौर पर नहीं देता । मैं आपसे दखर्वास्त करूंगा कि गेज–रीडर नहर के गेज की रिपोर्ट पर हर गाव के सरपंच या नम्बरदार के दस्तखत करवाये और यह बताये कि टेल पर इतना पानी है । सरपंच और नम्बरदार के दस्तखत करवाने से नहर के पानी एपी जो चोरी होती है, जो फल्कचुएशन होती है, वहू द्र हो जायेगी । एक प्रोब्लम यह है कि डिस्ट्रिब्यूटरी की टेल पर. एक एस० सी० का कंट्रोल है और हैड पर किसी और का कंट्रोल है । मैं सरकार से दर्ख्वास्त करूंगा कि हैड के एस०सी० का और टेल के एस०सी० का ज्वायंट कंट्रोल हो जाए ताकि पानी की डिस्ट्रिव्यशन में जो गडबड़ है वह दूर हो जाए । इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांड्ज का समर्थन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं ।

मास्टर राम सिंह (रादौर अनुसुचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं० 8, 15, 17, 18, 21 और 22 पर अपने ख्यालात का इजहार करूंगा । बजट के अन्दर हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने बड़ी अच्छी तरह से इन डिमांड्ज का प्रावधान किया है । सबसे पहले मैं डिमांड नं ० 8 पर बोलूंगा । यह डिमांड भवन तथा सड़कने के बारे में है जिसके लिए 38, 44,09,00 रुपये की मांग की है । डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि

हमें मालूम है, डिस्ट्रिक्ट कुरूक्षेत्र एग्रीकल्चर के मामले में सारे हिन्दुस्तान मैं अव्वल नम्बर पर है, लेकिन सड़कों के मामले में बहुत पीछे हुए जो सड़कें बनी हैं, वे ट्ट गई हैं । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां पर सड़कें नहीं बनी हैं वहां बनाई जाएं और जाए टूट गई कुए उनकी रिपेयर की जाए। मैं आपके नोटिस में कुछ लडके लाना चाहूंगा । कलैसरा से दौलतपुर जाने वाली सड़क पर सिर्फ एक किलोमीटर का टुकड़ा है, मेरी प्रार्थना है कि इसको बनाया जाए । इस समय रादौर आने के लिए 6 किलोमीटर का सफर तय करना पडता छउ । अगर यह एक किलोमीटर का टुकडा बना दिया जाए तो यह सफर बच सकना एं । इसी तरह से जोगीमाजरा से सजोदपुर रोड पर एक किलोमीटर का टुकड़ा है । अगर. इसको बना दिया जाए तो काफी सहूलियत होगी । यहां से इस समय रादौर भाने के लिए 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है । इसी तरह से हीरांचापर से वीर बरटौली सड़क है । इस सड़क से रादौर आने के लिए 16 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है । एक किलोमीटर का टुकड़ा है, इसको बनाया जाए । अगर यह बात गई गर्व तो काफी सफर बच सकता है । इसी तरह से 'हुंडियां से अलावलपुर रोड पर एक किलोमीटर का टुकड़ा है । इस सड़क से रादौर आने के लिए 25 किलोमीटर का सफर तब करना पड़ता एं । यह सड़क बनाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों का टाईम फजूल में खराब न हो । बरथली से बुहावी सड़क पर डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा बनना है । इस सड़क से रादौर आने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है

। इसी तरह लाडवा लाया बबैन से शाहबाद रोड पर मंडी बनी हुई है । इसी रोड पर एक शूगर मिल लगी है इस कारण इस सड़क पर यातायात बहुत बढ़ गया है । बहुत–सी बसे जमुनानगर और करनाल के लिए लाडवा होती हुई शाहबाद जाती हैं । यह सड़क बहुत नैरो है, इसको चौड़ा किया जाना चाहिए ताकि यातायात में कोई कठिनाई न हो । धिलौर से हीरा चापडा रोड पर आधा किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बना है । इस टुकड़े के बन जाने से जमुनानगर जाने के लिए बहुत कम रास्ता तय करना पड़ेगा । डिप्टी स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र–जमुनानगर रोड पर रादौर 'और जमुनानगर के बीच में कुछ ऐसे पुल हैं जो बहुत ही तंग हैं । इन पुलों पर से दो बसे एक साथ नहीं गुजर सकतीं और बहुत ज्यादा एक्सीडैंटस होते है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन पुलों को चौड़ा किया जाए ताकि एक्सीडैंट्स से बचा जा सके । घौलरा से सोगीपुर रोड हैं, इस पर डेढ़ फरलांग का टुकड़ा है । अगर यह डेढ़ फरलांग का टुकड़ा बना दिया जाए तो रादौर आने के लिए जो चार पांच किलोमीटर का रास्ता फजूल में तय करना पड़ता है, वह तय न करना पड़ेगा । अगर इस टुकड़े को बना दिया जाए तो यह सफर बच सकता है । बहुत सी सड़कें हैं जिनमें से कुछ तो बन चुकी हैं और कुछ बिलकुल नही बनी हैं । जो कुछ बन गई हैं, जैसे बबैन–बरगट रोड है, यह कम्पलीट हो गई है लेकिन इस रोड पर पुल नहीं बने जिसकी वजह से किसानों को मंडी में अनाज लाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । इस सड़क पर जो पुल जाता है,' इसको बनाया

जाए ओर जो जो काम मार्किट कमेटी लाडवा को सौंपा गया है, वह उससे. पूरा करवाया जाए ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो । एक सड़क है बुहावा से यारा । इसके बारे में अनाउसमैंट भी को थो कि इसको बनाया जाएगा । इस रोड से शूगर मिल बहुत नजदीक पड़ती है । इस सड़क को सरकार जल्दी बनाये ताकि किसानों की दिक्कत दूर हो सके । गुमथला से खुखनी अनाज लाने के लिए गुमथला से खुखनी सड़क का बनाया जाना बहुत जरूरी है । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कुछ गांव ऐसे कुए जिनमें कोई सड़क नहीं जाती । जैसे गुड्डा से गुड्डी, वीर वैटोली से लाडवा मुस्तावल–पोलो से दंस्तीपुरवैन, बबैन बरगट से वरगट सपुरिया, सुलतानपुर से पाठक माजरा और अपडा से दयालमाजरा । इन गांवों को सड़क बिलकुल टच नहीं करती । मेरी सरकार से दरखास्त है कि इन गांवों को सड्कों से जोड़ा जाए ।.

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं० 15 पर, जो सिंचाई के बारे में एं, कहना चाहूंगा । कुरूक्षेत्र जिले का जो उत्तरी हिस्सा है, जैसे शाहबाद हल्का, कुरूक्षेत्र हल्का और रादौर हल्का, वहां नहर का पानी नहीं लगता । यह सारे का सारा क्षेत्र ट्यूबवैल्ज पर आधारित है । मेरे ख्याल में जितने ट्यूबवैल्ज इन तीनों हल्कों में हैं उसने सारे हरियाणा में नहीं हैं लेकिन ट्यूबवैल्ज को पूरी माता में बिजली नही मिलती । यदि बिजली मिले तो यह ऐसा एरिया है कि इसके अन्दर सब से ज्यादा

पैदावार हो सकती है । मेरी प्रार्थना है कि इन तीनों क्षेत्रों को प्रायरिटी बेसिज पर बिजली दी जाए, पानी दिया जाए और फर्टिलाइजर दिया जाए ताकि इस उपजाऊ एरिया की और ज्यादा डिवैल्पमैंट हो सके । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी आपके द्वारा –सरकार से प्रार्थना है कि बबैन के 33 के० वी० सब–स्टेशन को 66 के० वी ० का बना दिया जाए । जठलाना, मैसूर पुर और बरतोली या छपरा में 6 6– 66 के० दी ० के सब– स्टेशन्ज जल्दी से जल्दी लगाए जाएं । डिप्टी स्पीकर साहब, खेड़ा सब–स्टेशन बी०बी० एम०बी० का है । इससे इस इलाके को कम बिजली मिलती है जिससे सिंचाई नहीं हो सकती । इसलिए मैं चाहूंगा कि पानीपत से जो सरप्लस बिजली इन्दरी को आती है वह इस एरिया को दी जाए ताकि काम अच्छी तरह से चल सके । (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहब, कृषि में हमारा जिला सबसे ऊपर है । यहां पर कुछ सड़कें ऐसी है जो मार्किट कमेटी ने दस साल पहले बनाई थी लेकिन आज वे टूट चुकी हैं । उनका बुरा हाल हो चुका है । मैं चाहूंगा कि उनकी जल्दी से जल्दी रिपेयर की जाए । मेन–मेन सडकों के नाम इस प्रकार है । मेहरा से खरकली, खुर्दबन से धनौरा और छोटा बांस से रादौर मंडी । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं सभी डिमांडज का समर्थन करता हूं और आशा रखता है कि ये जो मैंने जरूरों जरूरी काम बताए हैं इनको अवश्य किया जाएगा ।

चौधरी नर सिंह ढांडा (पाई) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि बजट के बाद जो डिमांड्ज रखी जाती हैं, जो पैसा पास करवाया जाता है विकास और तरक्की के कामों के लिए वह पास होने के बाद मिस यूटिलाइज होता है, मिस ऐप्रोप्रिएट होता है । जितनी भी मांगे रखी गई हैं मैं इनके विरोध में कुछ कहना चाहूंगा । मांग नं ० 4 रैवेन्यू के बारे में हे । डिमांड नं ० 8 बिल्डिग्ज, रोडज एंड ब्रिजिज के बारे में है । डिमांड नं ० 15 इरीगेशन के बारे में है । डिमांड नं ० 17 ऐग्रीकल्चर, डिमांड नं ० 18 ऐनिमल हसबैंडरी, डिमांड नं ० 21 कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट और डिमांड नं ० 22 कोआप्रेशन के बारे में है । (विस्त) डिप्टी स्पीकर साहब, अमर आप थोड़ा सा टाईम दें तो मैं सभी डिमांडज के बारे में बोलना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका 10 मिनट का समय है क्योंकि दोनों तरफ से बोलने वालों की लिस्ट बड़ी लम्बी है ।

चौधरी नर सिंह ढांडा : डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं रैवेन्यू की डिमांड पैर बोलूंगा । तहसीलदार, एस०डी०एम० और डी०सी०एम० को तनखाह इसलिए मिलती है कि वे लौगों का कार्य करें लेकिन होता क्या है? कोई काम नहीं करता । इन्तकाल के मामले में और तकावी के मामले में पटवारी और तहसीलदार बहुत बदनाम हैं । ज्यादा तो मैं नहीं कहता लेकिन 80 परसैटं औफिशियल्ज गांव में जाकर एक एक इन्तकाल

के 5 सो रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक लैते हैं । गिरदावरी करने के तो पता नहीं कितने पैसे लेते हें । इससे किसान लिटिगेशन में पड़ते हैं और कचौहरियों में घूमते रहते हैं । (विघ्न) इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, स्माल सेबिंग्ज के नाम से हजार, दो हजार और पांच हजार रुपये तक लिए जाते हैं । तहसीलदार और एस०डी० एम० रजिस्ट्री के समय सीधे मेज के ऊपर पैसे लेते हैं कभी टिकट के नाम पर और कभी किसी और नाम पर । (विघ्न) चपड़ासी पैसे लेता है, कलर्क पैसे लेता है और तहसीलदार सीधे पैसे लेता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जनरल बात न करें । अगर आपके नौटिस में कोई बात है तो स्पैसिफिक इंस्टांस दे दे ।

श्री लछमन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आप करनाल में जाते हैं । आप देख लेना कि रैड क्रास के नाम पर किसान से कितने पैसे लिए जाते हैं । कभी कहते हैं डि दो हजार रुपया दे दो पर्ची ले लो । कभी कहते हैं कि पांच सौ रुपया चपडासी को दे दो । यह सब जगह है । कालका में भी है और दूसरी जगह भी है । कौन सा ऐसा एम०एल०ए० है जिसको यह पता नहीं है । आप ट्रेजरी बैंचिज के एम ०एल०एज० से ही पूछ लीजिए हु सबको पता है । लाखों और करोड़ों रुपये की बंगलिग है क्योंकि रैड कांस का खुला खाता है । (विघ्न)

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बिल्कुल स्टैटं ऐग्जाम्पल दिया एं । मैंने कहा था कि मैंने खुद तहसीलदार से पांच सौ रु से वापस करवाए हैं । इससे ज्यादा पेटैन्ट ऐग्जाम्पल हम और क्या देंगे? (विघन)

चौधरी नर सिंह डांडा : डिप्टी सीकर साहब, जब कभी कांग्रेस पार्टी का जलसा होता है तो तहसीलदार, एस०डी०एम० और डी०सी० बाकायदा पैट्रोल पम्प पर 'बैठकर नाजायज दबाव डालकर ट्रकों में पैट्रोल डलवाते हैं और लोगों को भर–भर कर कांग्रेस के जलसे में भेजा जाता है । अब आप देखें कि तहसीलदार, एस०डी०एम० और डी०सी० का यह काम रह गया है ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, ये कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर यहां गलत बातें लिखवा देते हें जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती ।

चौधरी नर सिंह डांडा : डिप्टी स्पीकर साहब, आप कभी भी देख लेना। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, अव मैं बिल्डिग्ज रोडज एंड– ब्रिजिज आदि की डिमांड. के बारे में कहना चाहूंगा । इसके तहत ये 38, 44,09,000 रुपये मंजूर करवाना चाहते हैं । दु:ख की बात यह है कि पाई कांस्टिचुऐसी में पिछले पांच सान में ये केवल तीन किलोमीटर का टुकडा बना ६ पाए हैं जबकि उस सड़क को बनाने की योजना पिछले दस साल में है । अब भी ये

बताएं कि पाई हलके के लिए अगले साल में फलां फलां स्कीम मजूर की जा रही है या फलां फलां सड़क बनाई जाएगी । मैंने पहले भी दो तीन सउको का यहां जिक्र किया अ । कठवाड से मुन्दरी के बीच एक सड़क ऐसी है जहां बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती । भोगों को पैदल जाना पडता है । पानी मोंडों तक आ जाता है । बहन बेटियां अपने पशुओं के लिए चारा नहीं ला सकतीं । डिप्टी स्पीकर साहब, आप ही बताएं कि क्या ऐसे इलाके में सडक जरूरी है या नहीं? अफसर लोग दफ्तरों में बैठ करके सड़कें मंजूर कर देते हैं । अपोजिशन के मैम्बर्ज के हलकों की कोई सड़क मंजूर नहीं की जाती । यह बड़े दुष्ट की बात है । सारे हरियाणा को सरकार को एक नजर से देखना चाहिए । अपोजिशन के हलकों में भी लोग रहते हैं । वे सरकार को रैवन्यू देते हैं और शायद इतना पैसा देते हों जितना दूसरे हलफी से न आता हो ।

12.00 बजे

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमान्ड 15 के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । एस० वाई० एल० के बारे में तो रेज्योलूशन के टाईम पर काफी लम्वा चौड़ा जिक्र हाउस में हो. चुका है । मैं उसके वारे थें न कहते हुए ड्रैनों के बारे में कहना चाहता हूं । हरियाणा में ड़ेनों के बारे में यहां हाउस से पैसा पास हो कर चला जाता है लेकिन जो वहां पर ऐक्सीयन और एस०ईज० बैठे रहते हैं वे कभी भी खुदाई और उनकी सफाई वगैरह का काम

नहीं करवाते हैं । जयं बारिश आ जाती है तो बन दिनों में सौ–पचास या दस–बीस बेलदार रख लेते हैं । वे ड़ेन पर कस्सी लिए घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं करते । जिस ड्रेन को खोदा ही न गया हो वह पानी कहां से ले जायेगी । ड्रेन्ज की पूरी खुदाई और सफाई नहीं हो पाती है इसलिए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । जब खेमों में पानी नहीं चलता है तो वह पानी देहातों में चला जाता है और वहां के खेतों तथा गांवों को बरबाद करता है । जब हम किसी अफसर से यह वात कहते हैं कि आप इनकी खुदाई या सफाई क्यों नहीं करवाते हो तो वे कहते हैं कि सरकार के पास तो कर्मचारियों को तनख्बाह देने के लिए रुपया नहीं है तो आप की ड़ेनों के लिए कहासे पैसा आयेगा? डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी कास्टीचूएंसी पाई में प्यौदा और कसान ड्रैन्ज कम्पलीट नहीं हैं इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाया जाये । दूसरे जो गांव में सरकार ने रिंग बान्ध बान्धे हैं उनके ऊपर से जा कर पानी गांव में चला जाता है । जज बारिशें होती हैं तो पानी खड़ा रहता है और सरकार के भेजे हुए बेलदार, पम्पिंग सैंटस वाले या अन्य कर्मचारी वहा खड़े पते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते । अगर सरकार बारिशे होने से पहले ध्यान दे हो भोगों का कुछ भला हो सकता है । ड्रेनों को खुदवाया जाये ताकि गांवों में पानी न धुसे । एक बात मैं एम० आई० टी० सी० के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं इतने भी नाले पक्के होते हैं चाहे वे रजवाहे हैं या छोटे नाले हैं, सब में सब– स्टैन्डर्ड मैटीरियल लगाया जाता है । थे पक्के नाले इसलिए बनाये गये थे

कि जहां किसानों के खेतों मे पूरा पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पर पूरा पानी पहुंच सके लेकिन सब–स्टैन्डर्ड मैटीरियल लगने की वजह से हर जगह पर पक्के नाला में से निकलता रहता है और टेल पर पानी नही पहुंच पाता है । सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि नाले पक्के करके टेल पर पानी पहुंचाना है लेकिन इस सब–स्टैन्डर्ड मैटीरियल के कारण देखा जाता है वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता ।

डिप्टी स्पीकर साहब कैनाल और रजबाहों की लाईनिग के बारे में तीन साल से लगातार हाउस में लिख कर दिया गया है । जब यहां हाउस में क्यैश्चन पूछा जाता है तो यह जवाब दे दिया जाता है कि एक साल से पहरने ही पक्का कर दिया जायेगा लेकिन एक साल से वहां. पर न कोई कार्य हुआ है और न ही वे पक्के होने जा रहे हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एग्रीकलचर के बारे में कहना चाहूंगा । जहां हरियाणा के किसानों का 45 परसैन्ट बजट का हिस्सा उनकी जेब से निकाल कर जमा होता है वहां उन पर केवल 11– 12 परसैन्ट खर्च होता है । वित्त मंत्री महोदय ने बताया था कि बिजली हरियाणा में सारे लोगों को मिलती है चाहे वे देहाती किसान हैं या शहरी किसान हैं, सब को पूरी बिजली मिलती है । उन्होंने और बहुत सारी सुविधाओं का भी जिक्र किया । आप ही बताइये कि कौन सी सुविधाये किसानों को दी जा रही हैं । किसानों कौ टैरक्टर्ज का लोन दिन प्रति दिन बढ्ता जा रहा

है । उनकी जमीनें गिरवी रखी हुई हैं । उनको इस ऋृण में कोई राहत देने की बात नही की गई है । डिप्टी स्पीकर साहब, यूक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि किसानों को टाईम से पहले दवाइयां, पैस्टी– साइडज और बीज आदि मिलने चाहिएं । लेकिन होता यह है कि किसान बाजरे की फसल बोने जा रहे होते हैं लेकिन उनको समय पर बीज नही मिलता और बहत से किसान लोकल मार्किट से ब्लैक में बीज खरीद लेते हैं उनके बाद ये बीज लोगों कों देना शुरु करते हैं । हमेशा ही यह हालत होती हए । किसान ब्लैक में मार्किट से बीक खरीदते है । जहां 28 रुपये का थैला होता है वहां मार्किट से वे 40 रुपये का खरीदते है । किसानों को लूटा जाता है । उन्हें कीटनाशक दवाइया भीं टाईम पर नहीं मिलती । अगर वे बाजार से लेते हैं तो मंहगी होती हैं और वें अच्छी भी नहीं होती हैं इससे किसानों की फसलें बरबाद हो जाती हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहब कम्यूनिटी डिवैल्पमेंट के बारे में भी वित्त मंत्री जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया । उन्होंने कहा–''ग्रामीण क्षेत्रों में, बेकार श्रमिकों को, विशेषतः बेकारी के मौसम में, रोजगार के अवसर प्रदान करन, तथा स्थायी परि–सम्पतियों का निर्माण करने के लिए राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू है ।'' इन्होंने दो स्कीमें दी हैं । एक तो अन–एम्पलाएमेंट खत्म करने की फूड फार वर्क की स्कीम है जिससे हरियाणा के मजदूर, किसान और मेहनतकशों को रोजी

रोटी मिलेगी। डिप्टी स्पीकर साहब मेरा पाई हल्का दो इलाको में बंटा हुआ है । एक पू डरी और दूसरा कैथल बराक है । मेरे हल्के के आधे आधे गाव इन ब्लाकों में हैं । सरकार ने दो स्कीमें दी हैं एक नेशनल रुरल एम्पलाएमेंट प्रोग्राम और दूसरी रुरल लैन्डलैस एम्पलाएमेंट गाक्टी प्रोग्राम । दोनों प्रोग्रामों के तहत पाई कांस्टीच्यूएंसी में एक हजार रुपया भी नहीं मिला है । बी०डी०पी० औज० और दूसरे ब्लाक आफिसर्ज हैं उनसे कांग्रेस के मती और एम० एल ०ए० मिल कर अपने लोगों और सरपंचों को पैसे देते रहते हैं । मैं आपके जारिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या पाई हल्के में अन–एम्पलाएमेंट खत्म कम्ने की कोई स्कीम नहीं है, क्या वहां पर बेरोजगार नहीं हैं? वहाँ पर इस ओर सरकार बिल्कुल ध्यान नही देती है, इस लिए मेरे छ्ल्के की ओर भी ध्यान दिया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एजूकेशन और कोआप्रेशन के वारे में कहना चाहता हूं । एजूकेशन में दस प्लस दो की स्कीम हए । (विघन एवं शोर)

श्री उपाध्यक्ष : इन डिमान्डज मं एज्केशन की डिमान्ड आज नही है ।

चौधरी नर सिंह हांडा : डिप्टी स्पीकर साहब मरे पास लिस्ट पहुंची एं । यह डिमान्ड भी आज के बिजनेस में रखी गई एं । इसलिए मैं एजूकेशन पर भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं ।

वित्त मन्त्री (श्री सागर राम गुप्ता) : डिप्टी सीकर साहब, इस बारे में जो कनफयूजन हो गया है उसे पहले दूर कर लें ताकि उन्हीं डिमान्डज पर एम०एल ०एज० साहेबान बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : आज सात डिमान्डज हैं, उन्हीं पर बोलना है । '

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, कल बोलते हुए फिर दिक्कत आयेगी । कल डिमान्डज पर ये फिर बोलेंगे । कल इन्हे फिर टाईम दे देंगें तो डुप्लीकेसी हो जायेगी । पहले यी निर्णय हो चुका है कि मारी डिमांडज पर इकटठी डिस्कशन होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : यह निर्णय नहीं हुआ कि आज ही सारी की सारी डिमाडज पर बोलेंगे । चौधरी सुरेन्द्र सिह जी मैंने स्पीकर साहब से बात कर ली थी । जो डिमांडज आज के आर्डर पेपर पर हैं, आज उन पर ही डिस्कशन होगी ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : मेरी सबमिशन यह है कि आप स्पीकर साहब से मिल कर यह तय कर लें कि सभी पर बोलना है या सात डिमांडज पर बदी बोलना है । अभी एक ही मैम्बर बोला है और दूसरों ने बोलना है ।

श्री राम विलास शर्मा डिप्टी स्पीकर साहब, आज पर्टिकूलरली हाउस में पद कर सुनाया है कि हाउस का टाईम बचाने कें लिए सारी ही डिमान्डज पर चर्चा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : लिस्ट आफ बिजनैस चेंज नही हुई है । जो डिमांडज आज के एजंडे पेपर पर हैं, उन्हीं पर ही मैम्बर साहेबान डिस्कशन रेज कर सकते हैं ।

चौधरी नर सिंह ढांडा : डिप्टी स्पीकर साहब, अगर कल आपने इजाजत दी तो बाकी डिमान्डज पर वोल्गा । यहां पर कोआप्रेशन की मांग नम्बर 22 है । देहातों में लोगों को जो पैसा दिया जाता है, उसकी रिकवरी के टाईम पर कितनी बेदर्दी और इल्लीगल तरीके से डिटेन्शन करते हैं यह किसी से छिपी हुई बात नही है । ये लोगों को पीटते रहे हैं, मारते रहे हैं । सरकारी कर्मचारियों का किसानों से रिकवरी का तरीका बहुत ही गलत है । पीछे लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गये । वहां से रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया । रेड हुआ औंर मौके पर पकड़े गये । किसानों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता रहा है । उनको बहुत बुरे तरीके से पीटा और मारा जाता है । जबरदस्ती उनसे पैसा वसूल किया जाता है जबकि उनके पास पैसा वापिस करने का टाईम रह जाता बुश जिसमें कि वह अपना पैसा जमा करवा सके । डिप्टी स्पीकर साहब, इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं कि जितनी भी यह मांगे रखी गयी हैं, मैं इनका विरोध करता हूं और सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के सारें इलाकों को यकसां हिस्सा दे और उनका पूरा–पूरा ध्यान रखें ताकि किसान मजदूर और मेहनतकश को पूरा हिस्सा मिल सके । धन्यवाद ।

श्री कंवल सिंह (धिराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 4– 5 डिपार्टमैंटस के मुताल्लिक बोलने का विचार रखता हूं । मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अभी स्पीकर साहब, कह कर गये थे कि हम लोग बोरन सभी डिमांडज पर सकते है इससे आग सहमत होंगे । जो डिमांडज आरन लिस्ट आफ बिजनैस पर है, उनके बारे मैं जवाब आज आ जायेगा और जो डिमाडज कल टेक–अप होंगी, उनका जवाब कान आ जायेगा । (व्यवधान व शोर)

श्री उपाध्यक्ष : जो डिसीजन हुआ था, वह यह हुआ था कि जो आज 7 डिमांडज हैं, केवल उनके ऊपर ही बोल सकते हैं । ऐसी बात नहीं है कि आप सारी डिमांडज पर बोल सकते हैं । (व्यवधान व शोर)

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : चौधरी कंवल सिंह जी के बोलने से पहले में दोबारा एक बात सबमिट करूंगा कि कुछ मैम्बर्ज तो पार्टीज की तरफ से आज नामजद किये गये एं, कुछ कल को किये जायेंगे । जैसे हमारी पार्टी की तरफ से किये गये हैं, वैसे हो दूसरी पार्टीज की तरफ से भी कुछ मैम्बर्ज आपको बताये गये हैं कि ये आज बोलेंगे । कल को जब बाकी की डिमांडज पर डिस्क्शन होगी तो पार्टीज की तरफ से दूसरे मैम्बर्ज की लिस्ट आपको दी जायेगी कि भे वोलेगे । इसलिये जो मैम्बर्ज आज बोल लेंगे, उनको तो दोबारा टाईम नहीं मिलेगा । यह एक छोटी सी बात एं । आप स्पीकर साहब से बेशक इस बारे में बात कर लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो डिसीज न हो चुका हए, उसको दोबारा री–ओपन करने धात्री कोई बात नहीं है । मैने रूल्ज भी देख लिए है।

श्री कंवल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जो वित्त मत्री जी ने बजट पेश किया था उसके कांसीक्यूएंटली यह डिमांडज डस हाउस में आयी हैं ।

श्री लछमन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज मुझे बोलने के लिये टाईम मिलेगा? (व्यवधान व शोर)

श्री उपाध्यक्ष : आज तो मुश्किल है ।

श्री लछमन सिंह : कल स्पीकर साहव ने कहा था कि आप बोल लेना । फिर क्या आप मुझे कल को टाईम दोगे? (व्यवधान व ओर)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, कल बोल लेना । (व्यवधान व शोर)

श्री लछमन सिंह : तो कल के लिए पक्का हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आए कल बोल लेना ।

श्री कंवल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो यहां पर 114 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया है

मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि मुतवातिर घाटा हमारें बजट सें चल रहा है। जो आंकडे दिये गये हैं, उनके हिसाब से हरियाणा की एनुअल प्लान पंजाब कं मुकाबले में बड़ी है । प्रान्त की पोग्रैस के लिए एनर्जी का होना सबसे पहली और बेसिक चीज है । आज हरियाणा में बिजली की कमी है । उसकी वजह से आज गवर्नमैंट को नुक्सान हो रहा है, किसानों को नुक्सान हो रह है और कारखाने भी बन्द पड़े हैं । लोग बेरोजगार बैठे हैं । इस बात की तरफ जितना ध्यान फाइनांस मिनिस्टर सा हब को देना चाहिए था, मैं समझना है उससे थोड़ा कम रहा है और उनको इस दिशा में कुछ ज्यादा कोशिश करनी चाहिये । मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहूंगा कि नाथपा झाकडी प्रौजैक्ट हरियाणा के लिये एक प्रैस्टीजीवस प्रोजैक्ट था । यह बात ठिक है कि किसी भी हाईड़ो पावर प्रोजैक्ट का जैस्टेशन पीरीयड कुछ लम्बा होता है । उसको एक्जीक्यूट करने में और पाये–तकमील तक पहुंचा ने में कछ टाईम लग जं ता है, उसके मुकाबले में थर्मल पावर' स्टेशन लगाने में लाम जल्दी मिल जाता है । इसी के बारे में मैं यह बात कहना चाहता हूं । हमारे आई ० पी ० एम ० साहब यहां पर बैठे नहीं हैं । मेरा सरकार से एक पुरजोर अनुरोध है कि हमें नाथपा झाकडी प्रोजैक्ट अपनी ओर से बिल्कुल अबन्डन नहीं करना चाहिये । नेशनल हाईड़ो कारपोरेशन अगर कुछ बनाना चाहती है तो बनाये । सतलुज रिवर के कम से कम 10 प्रोजैक्ट हैं । नाथपा झाकडी उनमें से एक है । इसका कास्ट बंनीफिट रेशो सबसे अच्छा है । यही वजह थी कि हमने इस प्रोजैक्ट को अपनाया था

। हरियाणा में इसके ऊपर और दूसरे प्रोजैक्टस के ऊपर काफी दिनों से विचार–विमर्श चल रहा था । हमारी कोशिश यह थी कि इसको टेक–अप किया जायें । अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक साथी मिले । मेरी उनसे बात हो रही थी । वह कहने लगे कि एक इंडस्ट्रीयलिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि अगर गवर्नमैंट इजाजत दे तो जितनी भी कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह हम बीयर करेंगें और हम बिजली–घर बना कर उससे भी कम खर्च में हरियाणा को बिजली दे सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी शमशेर सिंह जी चूंकि इस समय सदन में आ चुके हैं इसलिये मैं उनसे यह अर्ज करूंगा कि वे इस चीज को स्टडी करें । इसमें क्या हर्ज है सरकार इसके लिये तैयार क्यों नहीं शं । जितनी भी कारपोरेशन्ज और कारखाने सरकार की तरफ से लगाये गए हैं, वे सब के सब घाटे में चल पे हैं । उनकी डिफरैंट वजुहात हैं । क्यों नहीं अगर थर्मल प्लान्ट लगाना ही है तो इसको किसी प्राईवेट पार्टी को दे दिया जाये । आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में टाटाज इन प्लान्टस को चला रहे हैं । दूसरी कई जगहों पर भी बड़े–बडे सेठ चलाने के लिए तैयार हें, थर्मल प्लान्ट लगाने में किसी को कोई एतराज नहीं है । स्टेट के बैनीफिट के लिए हम अगर इस काम को प्राइवेट सैक्टर में दे दे और नाथपा झाकडी प्रौजैक्ट को जो कि एक प्रैस्टिाईजीयस प्रोजैक्ट है, अपने हाथ में ले तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिये । आप एक और बात देखेंगे । हाईड्रो की जो पावर जनरेशन होती है, उससे कोई पौल्यूशन नहीं होती । जितने दिन वह पानी उस रिवर में वह रहा है, उसका

एक–एक दिन, एक–एक पल बेकार जा रहा है । यह हमारा नैशनल लौस हो रहा है जबकि इसके मुकाबले में हमारा कोयला जो थर्मल प्लान्टस में यूज किया जाता है, वह कोई ऐसी चीज नहीं है जो वेस्ट चली जाए । कोयला हमारी जमीन के नीचे पड़ा हुआ है, उसे हम चाहे जब मर्जी निकाल कर यूज कर सकते हैं । मैं आई ० पी ० एम ० साहब से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इस नाथपा झाकडी प्रोजैक्ट को इम्पोर्टेन्स देते हुए दोबारा हमारी सरकार सैटल गवर्नमैंट से टेक–अप करे कि यह प्रोजैक्ट हम एक्जीक्यूट करेंगे । हरियाणा के लिए बहुत हितकर और स्टेट की तरक्की के लिए यह एक बहुत ही अच्छा कदम होगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आई० पी ० एम ० साहब के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं । इन्होंने अब नहरें पक्की करने के लिए कार्यक्रम चला रखा है । एक बात अफसर हर जगह देखने में आई है –कि नहर तो अब पक्की होने लग रही हैं लेकिन खाल एम० आई ० टी० सी ० ने पहल पक्के कर दिये थे । नहर का लैवल पहले कुछ था । अब जब कि नहर पक्की हो जाएगी तो उसका बैड लैवल दो–तीन–चार फुट ऊंचा हो जाएगा ।

यह उठना भी चाहिये । कुछ इलाके हमारे ऐसे है जहां पर गेम एजीटेशन कर रहे हैं, जब खालें बनाई गई, तो उस समय हम उनको ऊंचा नहीं बना सकते थें क्योंकि हम अगर ऐसा करते तो पानी नही पहुंचना था । अब नहरें परकी करने से पानी का बैड लैवल ऊंचा हो जाएगा । इस बारे में जब अधिकारियों से

बातचत की गई कि इसका अब क्या इन्तजाम होगा, तो वह कहने लगे कि अब खालें दोबारा बनानी पड़ेगी । मेरा आई० पी ० एम० साहब से आगे के लिए अनुरोध है कि जहां पर खालें पक्की बननी हो वहां पर एम० आई ० टी० सी० से यह स्टडी करवा लें कि अगर वह चौनके एवकी हो जाती है, तो क्या फिर उनको दोबारा पक्का तो नहीं करवाना पड़ेगा क्योकि उनका उस वक्त बैड–लैवल कम होगा । छ बात को मद्दे नजर रखते हुए कि खालें जब बनाते हैं, तो चाहे उसका खर्चा किसान को देना पड़ता है या सरकार को उसे मुआफ करने की वजह से सहन करना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिये कि चौनल जब पक्की हो जाएगी हो क्या उसमें पानी आ सकेगा । अगर इस चीज को नहीं देखेंगे तो वेस्टफुल एक्सपैडीचर होगा । डिप्टी स्पीकर साहब, जहां इस बजट में वित्त मंत्री जी ने बहुत सी जगह छूट दी हैं, वहां कुछ जगहों पर टैक्स भी लगाये हैं । कुछ तो रोडवेज का किराया बढ़ाया है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये स्टेट के फाइनैसिज को बढाने की तरफ ध्यान दें । स्टेट की तरक्की के लिए वहां पर जो रिसोर्सिज हैं उनको मोबिलाइज करना जरूरी होता है । डिप्टी स्पीकर साहब, 1977 से पहले स्टंट के अन्दर दौ टैक्स लगे हूए थे । एक तो अर्बन इममूवेबल प्रौपर्टी टैक्स था और दूसरा प्रोफैशनल टैक्स था । ये दोनों टैक्स पैसे वाले तबके कर लगे हुए थे । मैं चाहता हूं कि सरकार अगर चाहती है कि रिसोर्सिज मोबिलाइज किए जाएं तो दोनों टैक्सों को रिवाइव किया जाए । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से दस करोड़ से

ज्यादा रैवेन्यू आएगा । प्रोफैशनल टैक्स वकीलो, पर और डाक्टरों पर लगता है । डिप्टी स्पीकर साहब, आपको यह जानकारी होगी कि हर शहर में दस–दस नरसिंग होम खुले हुए हैं और इनसे इडिविजूवल डाक्टर्ज को तीस हजार से पचास हजार रुपए की पर–मंथ आमदनी होती है और ये लोग न तो कोई डायरेक्ट टैक्स देते है और न इन्डायरेक्ट टैक्स देते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक इंकम टैक्स का सम्बन्ध है आपको पता ही है कि वकील और डाक्टर्ज किस तरह से करते हैं और कोई इंकम टैक्स नही देते । (बंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मैं' दो तीन जति मेर पहना चाहूंगा । पहली बात तो शह है कि बैस्टफुल ऐक्सपैडीचर की तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए । आप किसी शहर मैं चले जाएं, बाजार में चले जाएं, सिनेमा हाउस में चले जाएं जितने भी सरकारी विहकल्ज हैं उनमें से ज्यादातर विहकल्ज बाजार में मिलेंगे । अगर स्कूल का टाईम है तो स्कूल में मिलेंगे और जिस काम के लिए ये विहकल्ज है वे उस काम में वहुत कम भाते हैं । ज्यादातर समका मिसयूज होता है । जिस काम के लिए ये विहकल्ज दिये जाते हैं उसके आधे काम के लिए भी ये विहकल्ज यूज नहीं होते हैं । मुझे पता है कि बहुत से सैक्रेटरी लैवल के अफसर अपने काम के लिए प्राईवेट विहकल्ज यूज करते हैं लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर गवर्नमैंट विहकल्ज का मिसयूज होता हैं। टेलीफोन का भी काफी मिसयूज होता है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गुप्ता जी को इस तरह का जो

बेस्टफुल ऐक्सपैंडीचर है उसको खत्म करने की तरफ ध्यान देना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जिस वक्त हरियाणा बना था उस वक्त हमारे पास 67 के करीब आई०ए०एस० अफसर थे । 1 करोड़ 29 लाख की आबादी पर आज हमारे यहां 177 आई०ए०एस० अफसर हैं उस वक्त पंजाब में 30 आई०ए०एस० अफसर थे और आज वहां पर 140 हैं । हम इस मामले में पंजाब से भी आ गे बढ गए एं । डिप्टी स्पीकर साहब, ये लोग काफी काबिल हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों का स्तर नीचा है लेकिन इतने अफसरों का होना यह जाहिर करता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टौप हैवी है । इतने अफसरों का होना एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर टौप हैवीनैस को जाहिर करता है । इसको कम करना चाहिए (घंटी) । डिप्टी स्पीकर साहब, अव मै आरने इलाके में सड्कोंके बारे में कहना चाहता हूं । मेरे यहां एक सड़क राजली से बाडौपट्टी है । इस समय राजली से अगर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हिसार आया जाए तो वाया बरवाला आना पड़ता है । अगर यह सड़क बन जाए तो डिसटैस आधा रह जाता है । इस सड़क को मन्जूर हुए पांच सारन हो गए हैं लेकिन अमी तक इस पर काम नहीं हुआ है । मैं चौधरी अमर सिंह से प्रार्थना करूंगा कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी सड़क पाबडा से किनाला की है । कहने को तो किनाला पाबडा का माजरा एं लेकिन इसकी आबादी पांच हजार है और इस

सड़क का फातला पांच किलोमीटर है । इस वक्त गे जीलन यह है कि अगर पाबडा से किनाला आया जाए तो वाया उकलाना आना पड़ता है और यह फासला पन्द्रह किलोमीटर है । अगर पाखडा से किराला वाली सटक बन जाये तो फासला काफी कम हो जाएगा । इसके बारे में भी मैं चौधरी अमर सिंह से दरखास्त करूंगा कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एजूकेशन के बारे मैं कहना चाहता हूं हमारी एजुकेशन का लैवल तकरीबन आल इंडिया लैवल के बराबर है । किसी भी स्टेट की तरक्की के लिए यह जरुरी है कि वहां पर एजूकेशन की परसैन्टेज ज्यादा हो । गवर्नमैंट गर्ल्ज एजूकेशन को काफी बढावा दे रही है । मैं पिछले दिनों. राजस्थान गया था । वहां पर मुझे पग लगा कि गर्ल्ज एजूकेशन कालेज तक की है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा में भी गर्ल्ज एजूकेरान को कालेब तक फ्री करें । एजूकेशन के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार लेना चाहे वह ले और एजूकेशन की परसैन्टेज बढ़ाई जाए । डिप्टी स्पीकर साहव, पाबडा गांव में चालीस एकड़ जमीन जे ०बी०टी० स्कूल के लिए दी गई थी । मुख मन्त्री जी वहां पर गए थे उस वक्त यह जमीन दी गई थी । अब जे० बी०टी ० क्लासिज दुबारा शुरू हो गई हैं और एजूकेशन मिनिस्टर साहब यहां बैठे है वे इस बार का इन्तजाम करें कि गाव में जो जबान जे०बी०टी० स्कूल के लिए दी गई थी और वहां पर स्कूल बना हुआ है वहां पर जे०बी०टी०

क्लासिज शुरू की जाएं और जे०बी०टी० में रिजर्वेशन जो पहले थी वही द्विधा अब भी दी जाए । इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री निहाल सिंह (अटेली) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांडज नम्बर 8, जो बिल्डिंग्जएण्ड रोडज की है, डिमांड नं० 15 जो इरीगेशन कीहै और डिमाण्ड नं० 17 जो एग्रीकल्चर की है, के बारे में बोलना चाहता हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एग्रीक्लचर हरियाणा की कल्चर है । देश की एग्रीक्लचर में जितनी कामयाबी मिली है उस कामयाबी में हरियाणा का बहुत बड़ा हाथ है । देश के अन्दर अनाज की पैदावार बड़ाने में हरियाणा के किसान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है । लेकिन जिन हालात में हरियाणा के किसान नें पैदावार बढ़ाई हैं ओर पैदावार बड़ाने के लिए किसान को जो इनपुटस मिलते हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा है और इसके बदले में किसान को जो मुआवजा मिलता है वह बहुत कम है । डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के किसान ने पैदावार बडाने के लिए जितनी मेहनत की उसका क्रेडिट किसान को नहीं दिया गया । गवर्नर ऐड्रैस में एग्रीक्लचर के बारे में यह कहा गया है––

"It has been made possible by taking steps to ensure availability of required inputs including timely transfer of farm technology to farmers through a network of extension machinery".

डिप्टी स्पीकर साहब, इनपुट्स के बारे में सभी जानते हैं कि इनपुट्स में बिजली, अच्छा बाद, इरिगेशन फैसीलिटीज और बीज ये चीजें आती हैं । लेकिन ये चीजें किसान को ठीक समय पर और सही हालत में नहीं मिलती लेकिन इसके बावजूद किसान ने जो उपज बढ़ाई है उसके लिए किसान को क्रेडिट नहीं दिया गया । सारा का सारा क्रेडिट सरकार ने खुद लिया है और कहा है कि हमने यह किया है और किसान को ये– ये फैसीलिटीज दी हैं और तब यह पैदावार बड़ी है । मैं चाहता हूं कि इनपुटस के मामले में किसान की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा और उनको अच्छी रियायत देनी चाहिए । डिप्टी सीकर साहब, अब मैं इसके साथ ही साथ स्पोर्ट प्राईस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । गवर्नमैंट आफ इंडिया ने सरसों और बाजरे की स्पोर्ट प्राईस 385 रुपया और 130 रुपया मुकर्रर की लेकिन यह रिकार्ड की बात है कि सरसों तीन सौ से लेकर तीन सौ पच्चीस में बिकी लेकिन सरकार कभी भी मार्किट में इसको खरीदने के लिए नहीं आई । मेरा कहना यह है कि सरसों के मामले में सरकार को किसान की मदद के लिए आगे आना चाहिए था । इसी तरह से बाजरे के लिए स्पोर्ट प्राईस एक सौ तीस रुपया मुकर्रर की हुई है लेकिन मार्किट में बाजरा 95, 98 और सौ रुपया बिकता रहा लेकिन सरकार कभी भी बाजरे की खरीद के लिए मार्किट में नहीं आई और इस मामले में सरकार ने किसान की कोई मदद नहीं की । इसलिए मेरा कहना है कि जब सरकार ने स्पोर्ट प्राईस सरसों और बाजरे की फिक्स की है तो उसको टाईमली किसान की मदद के लिए मार्किट

में आना चाहिए । अगर सरकार मार्किट में नहीं आयेगी तो किसान को स्पोर्ट प्राईस फिक्स करने का कोई फायदा नही होगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं बाजरे के सीड के बारे में भी कहना चाहता हूं कि एक तो वह बीज दस रुपये किलो के हिसाब से बिका मंहगा भी था और साथ में मिलावट भी थी, उसकी क्वालिटी अच्छी नही थी । किसानों की आम शिकायत थी कि उस बीज में दाना है । इसलिये मैं सरकार से यह रिकवैस्ट करूंगा कि किसानों को बीज सप्लाई करने से पहले उस बीज को टैस्ट करवा लेना चाहिये और साथ ही सरकार की तरफ से जो पासशुदा दुकानें हों, डिपोज हों, वहीं से ही केवल सीड सप्लाई करवाया जाना चाहिये । आज कल जिसकी मर्जी होती है, अपनी दुकान खोल कर बैठ जाता है और इस तरह का घटिया किस्म का माल किसानों को सप्लाई होता है जिससे किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं और ऐसे आदमियों को कोई पूछने वाला नहीं हैं । इसलिये मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि किसानों की भलाई का ध्यान रखते हुए इस तरफ खास ध्यान दिया जाए जिससे किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज सप्लाई किया जा सके । इसी तरह से फर्टीलाईजर के बारे में भी शिकायत आती हैं कि किसानों को फर्टीलाईजर महंगे भाव पर और घटिया किस्म का दिया जाता है जहां तक अनाज की पैदावार का सम्बन्ध है, जव तक हम किसान को समय पर अच्छा बीज, अच्छी खाद और दूसरे ऐग्रीक्लचर इलीमैन्टस सस्ते भावों पर

सप्लाई न करेगे तब तक किसान अच्छी पैदावार नही कर पाएगा औंर न ही प्रदेश एग्रीकल्चर के फील्ड में तरक्की करेगा । लेकिन इस बजट में किसान के लिये इस तरह की कोई भी राहत दिखाई नहीं देती है । फर्टीलाईजर, बीज और दूसरे किसान के रोजा ना के इस्तेमाल के जो इम्पलीमैन्टस है उनमें किसान कौं किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गयी है। डिप्टी स्पीकर साहब, किसानों को जो सबसिडी फर्टीलाईजर्ज पर दी जाती है उस बारे मैं यह कहना चाहता हूं. कि वह किसानों तक पहुंच नही पाती है और जो मिडल मैन हैं, वे ही उसको खा जाते हैं इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और इस सिस्टम को फूल प्रूफ बनाना चाहिये ताकि सही आदमियों तक सरकार द्वार दी गयी सबसिडी का पैसा ठीक ससय पर पहुच सकें और वे इस पैसे का सही उपयोग कर सके ।

इसके साथ साथ आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सोमिन्ट का रेट काफों बढ़ गया है । कोई भी किसान जो अपने खेत में कुआं बनवाना चाहता है या टयूबबैलज लगाना चाहता है तो उसको सीमिन्ट की आवश्यकता पड़ेगी और वह आजकल के हालात में इतना महंगा सीमिन्ट खरीदने की हैसियत में नहीं है । इसलिये किसानो को सबसिडाइज्ड रेट पर सीमिन्ट सरकार की तरफ से मिलना चाहिये । रीजनेबल रेटस पर सीमिन्ट लोगों को मिलना चाहिये । इसी तरह से किसान को इरीगेशन की फैसिलिटीज भी सरकार की तरफ से मुहैया होनी चाहिये । आज

हमारे हरियाणा के अन्दर दूसरी स्टेटस के मुकाबले मैं ट्रैक्टज काफी महंगे हैं और अगर किसान के पास ट्रैक्टर न होगा तो किसान आजकल माडर्न तरीके से खैतीबाडी नही कर पाएगा । ट्रैक्टर की कीमत बढ़ने के कारण किसान ट्रैक्टर खरीद नही सकता और खेतीबाडी भी अच्छे रंग से नहीं हो सकती है । लेकिर भारत सरकार ने और हमारी इस सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि किसान के हित के लिये प्रदेश के हित के लिये ट्रैक्टर की कीमतें घटती चाहियें । आज सरकार कारों के उत्पादन की तरफ ध्यान दे रही है जिससे कारों का उत्पादन ज्यादा हो आज मारूति जैसी कार 55 हजार तक बिक रही है और लोग एक और डेढ़ लाख तक उसको चौक में भी खरीद कर रहे हैं । सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि ट्रैक्टर भी सस्ते बनाए जाए और किसान को ज्यादा से ज्यादा 30—40 हजार तक ट्रैक्टर मिल जाना चाहिये । ज्यादा महंगा ट्रैक्टर किसान नहीं खरीद सकता क्योंकि आज यहां के किसान की हालत बड़ी सस्ता है । इसी तरह से सरकार टेलीविजन के बारे में भी सोचती रहती है कि किस तरीके से नये नये डिजाइन बनाकर लोगों को सस्ते भावों पर दिये जांए लेकिन अगर सरकार किसानों का हित चाहती है और यह चाहती है कि खेती का काम माडर्न तरीके से हो तो सरकार को किसानों को सस्ते भावों पर खेती करने के सारे इम्पलीमैन्ट्स सप्लाई करने चाहियें जिससे किसानों को काफी राहत मिल सकेगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अगली बात मैं मार्किट कमेटियों के बारे में कहना चाहता हूं । इनकी आमदनी तो अच्छा है लेकिन कमेटीज उसका सही उपयोग नहीं कर पा रही हैं । मार्किटिंग बोर्ड ने विजली बोर्ड को बहुत कम रेट आफ इंट्रैस्ट पर पैसा दिया है जबकि ऐसे बोर्ड जैसे हाउसिंग बोर्ड एं, ये लोगों से बहुत ज्यादा इंट्रैस्ट चार्ज करता है । मार्किट फीस की रिकवरी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि रिकवरी सही तरीके से नही हो रही है । फीस इवेजन को रोकने के लिये भी सरकार खास तवज्जो दे ताकि सरकार की आमदनी और बड़े । रिकवरी ठीक हो इसके लिये मंडियों कं बाहर निकलने के हर रास्ते पर बैरियर्ज होने चाहिएं और वहां पर समय समय पर चौकिंग भी होनी चाहिये जिससे कोई भी बगैर मार्किट फीस दिये बाहर न जा सके । एक और बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो मार्किट कमेटियों को जीपें दे रखी हैं, उनका भी दुरुपयोग हो रहा है । इस की जांच भी होनी चाहिये और समय–समय पर उनका रिकार्ड भी चौक किया जाना चाहिए कि उन्होंने मिनस–किस समय कहां–कहां पर रेड्ज किये हैं, जीप का इस्तेमाल आया सही हुआ है या नही हुआ है उनके पास जीप के आने जाने का कोई हिसाब है कि नही? जीपें जो हैं, बजाये इस के कि मार्किट कमेटियों के यूज के लिये इस्तेमाल हों एस ० डी ० एम ०, डी ० सी० इन जीपों का इस्तेमाल करते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है । इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हू कि किसानों को पूरी बिजली नहीं मिलती है । इसका भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये और साथ में किसानों को डीजल सैट्स, पम्पिंग सैट्स भी रिडयुसड रेट्स पर सरकार की तरफ से मुहैया किये जाने चाहिये और जो डीजल किसान को अपने ट्यूबवैल्ज चलाने कें लिये दिया जाए वह भी सबसिडाइज्ड रेट पर मिलना चाहिए ताकि इरीगेशन के कामु में सुधार लाया जा सके और पैदावार को बढाया जा सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, किसान– को पम्पिग सैट्स और स्प्रिंकलर सैट्स खरीदने के लिये सरकार की ओर से जो लोन दिया जाता है उसके लिये यह पाबन्दी लगा दी जाती है कि आपको एक पर्टीकुलर डीलर से यह माल खरीदना होगा चाहे वह डीलर किसान को गन्दा माल या सबस्टैण्डर्ड माल दे । वह किसान को लेना ही पड़ता है । इस तरह की पाबन्दी सरकार की तरफ से किसानों के ऊपर नहीं होनी चाहिये । किसान को यह छूट हो कि वह अपनी मर्जी सं कहीं से भी सैटस खरीद सके । किसानों को यह इस बात की औपशन होनी चाहिये कि वह जहां से भी मात्र खरीदना चाहे, खरीद ले क्योंकि किसान ने इन सभी कामों के लिये अपनी जमीन गिरवी रखी होती हो मार्टगेज की होती है । उसने इस खेती के लिये अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया होता है । अगर उसे अच्छी खेती करके लाभ न हो तो बहु बेचारा तो मर जाएगा ।

इन सब बातों को देखकर किसान की सरकार को हर तरह से मदद करनी चाहिये और सस्ते भावों पर एग्रीकलचर इम्पलीमैन्ट्स मुहैया करवाने चाहियें ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अश्व मैं बी० एण्ड आर० के बारे में कुछ अज करना चाहता हूं । हमारे अटेली हल्के मैं जिला परिषद की रोड्ज हैं । जब से वे टेक ओवर की गयी हैं, उनकी हालत बड़ी ही खस्ता है । उन रोड्ज को लिंक रोड्ज से कनैक्ट नहीं किया यथा है । मुख्य मन्त्री महोदय एक बार नारनौल गये थे और वहां बार एसोसीऐशन के साथ जब मीटिंग हुई थी तो उस वक्त वे कह कर आये थे कि इन रोड्ज का काम जल्दी ही करवा दिया जाएगा । यह बात 15 अगस्त, 1983 की है । आज दो साल बीतने को हो रहे रहे हैं लेकिन इन रोड्ज का काम अभी तक नहीं हो पाया है । मैं उनसे रिकवैस्ट करूंगा कि यह फासला केवल 800–900 गज का छोटा सा है जोकि सिविल सेक्रेटेरिएट नारनौल के साथ जुड़ता है । इसको कली ही कम्पलीट करवाया जाए ताकि लोगों को आने जाने की सहूलियत हो सके । आशा है कि सरकार इस तरफ खास तवज्यो देगी और सड़कों का काम जल्दी ही पूरा करवाएगी । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे दोनने का समय दिया । जय हिन्द ।

श्री राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो डिमांडज हाउस में रखी मई हैं मैं इन पर बोलना चाहता हूं ।

वैसे तो सरकार चल रही है परन्तु इन डिमांडज के तइरा इन्होंने जो रकम मांगी है उसका पूरा लेखा जोखा इस वजट एस्टीमेट्स में मैंने देखा है । जैसे डिमांड नं० 8 है । इसमें 31 करोड़ रुपया सिर्फ वेतन और किताबों पर खर्च होना ई । दूसरी तरफ सारे हरियाणा की सड़कों के लिए केबल सात करोड़ रुपया र?ा मया है । वैसे हरियाणा सरकार इस वास को कहते हुए वकतों नदी है कि हरिदाभा विकास की परम सीमा पर पहुंच गया है । ये कहते हैं कि हर गौर में बिजली पहुंच गई है और गोय भे सडक दे ही है । भले ही रात के अन्धेरे में दारू डकैतिया कर रहे है । आज से 5– 7 साल पहले जो प्रोग्राम था ये उसी की रट लगा रहे है । उसके बाद या तो ये सरकारी कर्मचारियों को तनखाह दे रहैं हैं या कैबिनिट अपने टी०ए ०डी०ए० ले रही है । इसके अलावा इनकी और कोई परपोजल नहीं है । आज सड़कों की क्या हालत है? मेरे जिलें में एक सड़क गुजरती है जो राजस्थान से दिल्ली को मिलाती है– । वह सड़क झुनझुनू से मदेन्द्रगढू कनीना होते हुए दिली जाती है । उस सड़क पर आप महेन्द्रगढ से कनीना नहीं जा सकते क्योंकि उस इलाके के लोगों का यह कसूर है कि उन्होंने विपक्ष के लोगों को वोट दिए । मोहन लाल पिपल जी का फार्म भी उसी हल्के में पड़ता है । एक बार ये कार पर वहाँ गए तो इनकी कार का टायर पंचर हो गया । फिर ये इधर उधर से चालीस किलोमीटर का रास्ता घूम कर आए क्योंकि इनके लिए तो पैट्रोल का खर्चा कोई खास बात नहीं है । मैं चौधरी अमर सिंह जी से कहूंगा, क्योंकि ये हमारे साथ थे और मेरा ख्याल है कि

अभी कुछ पुराने संस्कार इनमें बाकी होंगे । महेन्द्रगढ़ और कनीना के बीच में यह जिले की सड़क है । सरकारी कागजों मैं इसकी सैकशन हो चुकी है और इसके एलोकेशन आफ फंड्ज भी हौ चुके हैं । लेकिन वहां एक एस ० ई० है जो अपने मन के मुताबिक ठेकेदार को ठेका देना चाहता है और वद्रु ठेकेदार अपनी सुविधा देख रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि वैसे तो हमारा जिला ऐसा है कि हम हरियाणा मे शामिल ही नहीं हैं । पीने के पानी की बात आ जाए तो बताया जाता है कि महेन्द्रगढ के लोगों को सिर्फ पांच लिटर प्रति व्यक्ति पानी दिया जाता है । इतना कहू कर ये कागजों का पेट भर देते हैं । हम हरियाणा में सब से ज्यादा टैक्स देते हैं । हरियाणा में जा कु ड और बिहाली की सलेट है यह इम्पोर्ट की आइटम है । उसने हरियाणा को करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती शं । फिर भी उस इलाके की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता । मैंने नेहरा साहब को कई बार रिकवैस्ट की है कि महेन्द्रगढ में एक गर्ल्ज हाई स्कूल है । वहां की लड़कियां अपनी क्लास अटैंड करने के' लिए चार जगह जाती हैं । एक तो धर्मशाला है, एक पहले पशुओं का हस्पताल था उसमें जाती हैं । इसी तरह से दो जगहें और हैं । नेहरा साहब' मौके पर भी देखने गए परन्तु पता नहीं स्कूल को बिल्डिंग क्यों नहीं बनवाते । इसी तरह से महेन्द्रगढ का वैस' अड्डा है । उसके वारे में विधान सभा में जवाब आया था कि उसके लिए जमीन एक्वायर करने का नोटिफिकेशन हो चुका है लेकिन वह भी अह तक नही बना । पता नहीं क्या अड़चन है । महेन्द्रगढ़ एक जिला

है और –उसके कुछ दफतर नारनौल में हैं और कुछ महेन्द्रगढ़ मैं हैं । डिप्टी स्पीकर साहेब, महेन्द्रगढ का जो मेन बाजार है वहां से बसें गुजरती हैं । वहां पर थाने के सामने दो वाइ एक्सीडैंट में नौजवान लड़के मारे गए । वहां की जिला ग्रीवैंसिज कमेटी में सिफारिश की कि महेन्द्रगढ में बस अड्डा बनाए बिना भी बसों को खड़ा करनेके लिए शहर से बाहर इन्तजाम किया जाए. । फिर भी कोई एकशन नहीं हुआ । डिप्टी स्पीकर साहबा यह सरकार बहुत लोकप्रिय है । हमने एक गांव मैं चीनी और मिटटी के तेल की सप्लाई में धांधली के बारे में शिकांयत की । जब इनक्वायरी की तो इनस्पैक्टर ने कहा कि यहां के डिपो होल्डर ने 40 बोरी चीनी बेच दी और 70 हजार लिटर मिट्टी का तेल ब्लैंक में बेच दिया । लेकिन डी०एफ०एस०ओ० ने उसको सौ रुपया जुर्माना करके दोबारा डिपो दें दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : शर्मा जी इसमें फूड एंड सप्लाई की कोई डिमांड नहीं हैं।

श्री राम विलास शर्मा : चलो मैं दूसरी तरह कह देता हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, उसकी शिकायत हुई लोगों ने कहा कि रात को अन्धेरा रहता है और अन्धेरे का फायदा डाकू उठाते हैं । बावन हल्के में रसियावास गांव है । वहां रात के अन्धेरे मे डकैती हो गई । लोगों ने कहा कि बिजली नहीं है तो हमें मिट्टी का तेल दे दो । तेल कहां से दें तेल तो 70 हजार लिटर ब्लैक में बिक गया । जब इस बारे में डी०एफ ०एस० ओ० को कहा गया तो

उन्होंने केवल सौ रुपए जुर्माना करके उसको छौड दिया । मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच करवाई जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं० 17 एग्रीकल्चर की है । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल बाजरे के चीज को चेपे की बीमारी लग गई । हमारे दो तीन जिलों जैसे भिवानी, गुड़गांव और महेन्द्रगढ के कुछे हिस्से में बाजरे की पैदावार होती है । हमने एक काल अटैन्शन मोशन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाया था' कि बाजरे का बीज खराब है । मुख्य मत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम एस०डी०ओ० एग्रीकल्चर को पकडेंगे कि तुम्हारे हल्के में गलत बाजरे का बीज कैसे बिका है । लेकिन उस संबंध में फाइल अब तक भी कम्पलीट नहीं हुई । उस बीज से बाजरा पैदा भी हो गया और खराब बाजरा लोगों को चला भी गया लेकिन यह सरकार अब तक उस मामले का फैसला नहीं कर सकी । मैं अपनी लोकप्रिय सरकार के बारे में अर्ज करना चाहता है कि इस बार हमारे हल्के में सरसों की पैदावार अच्छी हुई लेकिन इस बार उसका भाव नहीं हूँ । आज सवा तीन सौ रुपए क्विंटल सरसों बिक रही है जोकि पहले 800 रुपए क्विटल बिक रही थी । सरकार ने इसकी स्पोर्ट प्राइस 385 रुपए तय की हुई है लेकिने यह उससे भी' कम भाव पर बिक रही है । मैं कहता हूं किं सरकार सरसों खरीदने के लिए क्यों नहीं मैदान में आती? हमारे महेन्द्रगढ में मार्किट कमेटी के पास सरप्लस फंडज हैं और हरियाणा इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को वह लोन दे रही है । उस कमेटी की यहं हालत है कि उसके चारों तरफ कोई ट्रक नहीं निकलरू

सकती । हम 'चाहते हैं कि जो टैक्स वहां से इकट्ठा किया जाता है वह वहीं पर ही खर्च होना चाहिए । आखिर उस मार्किट कमेटी के फंडज कहां खर्च किए जाते हैं । उस इलाके 'की. जो सड़कें हैं वह पैसा उन पर खर्च किया जाना चाहिए । महेन्द्रगढ़ मेन बाजार में सब्जी मडी है । सब्जी मंडी के लिए जमीन एक्वायर हौ चुकी है दो तीन दौर उर्सका नोटिफिकेशन हो चुका है यह कह दिया जाता है कि' अब दुकानों के लिए प्लाटों का वितरण करेंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया हैं । मैंने पिछले दिनों सदन 'में यह कहा थी कि महेन्द्रगढ़ के मैन बाजार में नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर ने गंदगी के ढेर डलवा दिए हैं मैंने इस बारे में स्पीकर साहब को एक फोटो भी दिया था । मैं कहना चाहता हूं कि जो नई मंडी है उसको सरकार बनाना नहीं चाहती है । सरकार को इतना पक्षपात नहीं करना चाहिए और उस नई मंडी को जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए । महेन्द्रगढ भी इसी प्रांत का एक हिस्सा है उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए । अगर सरकार वहां से टैक्स प्राप्त करती है तो कम से कम उस पैसे को वहां पर खर्च किया जाना चाहिए । यदि सारा पैसा नहीं तो टैक्सों का कुछ हिस्सा तो वहां पर खर्च कर दे । महेन्द्रगढ़ के साथ इस सरकार को इतना सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, आप बार बार घंटी बजा रहे हैं मैं बस एक मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं । मैं डिमांड नम्बर 21 के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस डिमांड के तहत सरकार ने महेन्द्रगढ नगरपालिका को

औरतों की लैटरिन बनाने के लिए कुछ पैसा दिया था वह पैसा अभी तक उस काम के लिए खर्च नहीं हुआ है क्या वह पैसा लैप्स हो गया है? इस बारे में सरकार जवाब दे । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं ।

श्री दयानन्द शर्मा (राजौंद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 8, 15 और 17 पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सवसे पहले मैं इन डिमाडज का समर्थन करता हूं । जहां तक डिमांड नम्बर 8 की बात है इस वजट'' के अन्दर इस साल लगभग 200 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने का सरकार ने प्रावधान किया है । इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में पिछले दो अढ़ाई साल के दौरान पांच किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने के लिए मिटटी तो डाली गई है लेकिन एक किलो–मीटर भी सड़क पक्की नहीं की गई । राजौंद से सफीदों को जो रास्ता जाता है अगर उसको बिरथेवारी से बिगाणा तक मिला दिया जाए तो यह चण्डीगढ़ तक सीधा रास्ता बन जाता है इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बिरथेवारी से विगाणा तक सड़क बनाई जाहू । इसी तरह से मेरे हस्के में तीन गांवों के स्कूलों की विल्डिगें बहुत खस्ता हालत में है वे गांव हैं ठाठरथ, किठाणा और राजौंद । इन गावों के स्कूलों की बिल्डिंगें बहुत खस्ता हालत में हैं । गवर्नमैंट ने उन स्कूलों की बिल्डिंग टेकअप भी कर रखी हैं लेकिन उनकी मुरम्मत नही की जा रही है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उन स्कूलों की बिल्डिंगों की मुरम्मत करवाई जाए ।

इन गांवों के स्कूलों की बिल्डिंगें बहुत ज्यादा खराब हालत में हैं । बरसात के दिनों में बच्चे उनके नीचे नहीं बैठ सकते । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी मुरम्मत जल्दी से जल्दी करवाई जाए । इसके इलावा अब मैं डिमाड नम्बर 15 के वारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । यह डिमांड सिंचाई के बारे में है । डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने जींद में शूगर मिल स्थापित करने पर काफी पैसा खर्च किया है और उस मिल में सालाना 7. 66 लाख टन गन्ना आएगा । लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जींद जिले में जो राजौंद उचाना का हल्का लगता है उनमें कोई भी नहर नही है मौर वहुत सारे इलाके में सूखा पड़ा हुआ है इसलिए उस मिल में गन्ना कहां से आएगा यह बात मेरी समझ में नही आती । मैं इस बारे में कहवा चाहूंगा कि इस शूगर मिल को चलाने के लिए यदि सरकार को पूरी माता में – गन्ना चाहिए तो चन्दाना हैड से एक रजबाहा निकाला जाए जिससे उचाना और राजौंद का एरिया सिचित हो सके और जींद शूगर मिल को गन्ना पूरी माता में मिल सकेगा । डिप्टी स्पीकर साहब जय पिछले दिनों भाखडा नहर टूटी थी तो सरकार ने किसानों को उनकी फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया था । यह मुआवाजा भी बाद पर सबसिडी के रूप में दिया था । उससे छोटे–छोटे किसानों को कोई फायदा नही हुआ । जो बड़े बड़े जमींदार थे वे खाद ले गये और छोटे किसानों को खाद नहीं मिल सकी जिसके कारण उनको सबसिडी का कोई फायदा नहीं हुआ । सरकार को यह करना चाहिए था कि उस समय किसानों

का माल माफ कर देती ताकि छोटे किसानों को भी फायदा हो जाता । डिप्टी स्पीकर साहब मेरे हल्के में दो नहरें थीं जिनके रिटोली से नगूरा और गजामली से पान्डो तक रजबाहे आने थे । ये दो रजबाहे बनाने की स्कीम बनी थी लेकिन दो साल हो गए हैं उन रजबाहों को बनाने के बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी छउ । यदि ये दोनों रजवाहे निकल जाते है तो उनसे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होगी और इन इलाकों में गन्ना बहुत माता में पैदा होगा जिसका शूगर मिल को काफी योगदान मिलेगा । आप कमी देखते हैं कि सरकार कृषि पर पैसा तो काफी इन्वैस्ट करती है लेकिन बाद में उसका रिजल्ट थोड़ा कम ही मिलता है । रिजल्ट इसलिए थोड़ा मित्रता है क्योंकि जो कीड़े मारने की दवाई हैं वे सारी की सारी प्राईवेट फैक्ट्रियां बनाती हैं जोकि काफी घटिया स्टैन्डर्ड की होती हैं । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस तरह की दवाईयां बनाने की फैक्ट्री सरकार खुद लगाए ताकि किसानों को दवाईयां सस्ते रेट पर मिल सकें और अच्छी मिल सकें । इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 18 के बारे में बोलना चाहूंगा । यह डिमांड एनीमल हसबैंडरी के बारे में है । सरकार ने अगले साल में 40 नए पशु अस्पताल खोलने का प्रावधान किया है । मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि मेरे हल्के में एक बहुत बडा गांव है नगूरा जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है वहां पर एक पशुओं का अस्पताल खोला जाए । पहले वहां पर कोई अस्पताल नहीं है । यदि उस गांव के पशु बीमार पड़ जाते हैं तो उनको दूसरे अस्पतालों में ले जाना पड़ता है जिससे गांव के

किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पडता है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस गांव में एक पशु अस्पताल जरूर बनाया जाए । इस गांव के आस पास भी. कोई अस्पताल नहीं है इसलिए वहां पर एक पशु अस्पताल जरूर बनाया जाए । जो बड़े बड़े गांव हैं बिग्को आबादी काठों है वहां पर पशुओं के लिए अस्पताल जरूर बनाए जाने चाहिएं । इसके अलावा मैं बिजली के बारे में एक बात कहना चाहूगा । आज हम देखते हें कि बिजली की कमी तो है क्योंकि कुदरत ने बारिश नहीं की इसलिए बिजली की कमी है । आप लोग यह महसूस करते होंगे कि देहातों और शहरों में बिजली अकसर चोरी हो जाती है । सरकार को चाहिए कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए । डिस्ट्रिक्ट लेबल पर जो विजिलैस डिपार्टमैंट बनाया हुआ है वह तो इसकी चोरी को चौकिंग नहीं करता । इसलिए इसी तरह का कोई दूसरा सैल बनाना चाहिए जो इसको चौक वार सके । डिप्टी स्पीकर साहब, लोग मोस्टली रात को बिजली की चोरी करते हैं । हम देहातों में भी जाते हैं शहरों. में भी जाते हैं हम देखते हैं कि यदि कोई आदमी नई बिल्डिंग बनाता है तो रात को उस बिल्डिंग पर काम करने के लिए बिजली के खम्बों पर तार फेंक देते हैं और बिजली की चोरी करते हैं । उसको चौक करनें वाला कोई नहीं होता । जो चौकीदार होता है गार्ड' की ड्यूटी करने के लिए वह उसको चौक नही कर सकता । इस तरह से रात को बिजली की चोरी होती है उसको जरूर रोका जाए । इसके अलावा मैं डिमाड नम्बर 22 के बारे में बोलना चाहूंगा । यह

डिमांड सहकारिता के बारे में है । सरकार ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में 300 मिनि डेरी खोलने का प्रावधान किया है । इससे गरीब लोगों को काफी फायदा होगा । लेकिन सरकार डेरी के लिए लोगों को लोन देने की जो व्यवस्था करती है उसमें थोड़ा डिफैक्ट है । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय जब किसान लोग लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको लोन बैक के थ्रु मिलता है और वह पी०एन०बी० और स्टेट बैंक आफ इंडिया से लोन लेते हैं । जव किसान लोन लेने के लिए बैक वालों के पास जाते हैं तो बैंक वाले उनसे कहते हैं कि हम आपकी भैस देख कर पैसा पास करेंगे या उन्होंने जो पहले लोन लिया हुआ होता है उसके बारे में कहते है कि वह वापिस करो । जब लोग डी ०सी० से यह शिकायत करते है कि हमें बैंक वाले लोन नहीं देते हैं तो डी०सी ० साहब से बैंक वाले कह देते हैं कि हम सैन्ट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं स्टेट गवर्नमैंट की नौकरी नहीं करते । इस बारे में मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि किसानों को बैक से लोन लेने में बड़ी दिक्कत आती है इसलिए सरकर अपनी खुद की कोई एजैन्सी बनाए जिसके थू किसानों को लोन दिया जाए जिससे सहकारिता विभाग अच्छी तरह से तरक्की कर सकता है । जब तक सरकार कोई ऐसा सुधार नहीं करेगी तव तक किसानों को लोन लेने में काफी दिक्कत आएगी और उनको सही तरीके से पैसा, बैक से नहीं मिलेगा । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो जो म्यूटेशन का चक्कर है उसमें बड़ी भारी तकलीफ होती है ।

जब एक आदमी कोई जमीन खरीदता है तो उस जमीन की म्यूटेशन उसके नाम एटोमैटीकली हो जानी चाहिए बेशक इसके लिए एक्ट में अमैंडमैंट करनी पडे । मैं यह कहना चाहूंगा कि 30 दिन के अन्दर अन्दर वह म्युटेशन रजिस्टर में चढ जानी चाहिए । इससे आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी । ऐसे केस भी देखने में आए हैं कि लोग जमीन खरीदते हैं उनकी 10– 10 साल तक रजिस्टर में म्यूटेशन दर्ज नहीं की जाती है । मैं सरकार से प्रार्थना करुंगा कि इस बारे में सरकार कोई न कोई विचार अवश्य करे । इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांडज का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

13.00 बजे

श्री लछमन सिंह कम्बोज (इन्द्री) : स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं डिमांड ने छ पर बोलना चाहता हूं । मैं तीन साल से इस हाउस में लगातार आ! या हूं । इन तीन सालों के दौरान सरकार ने हरियाणा के अन्दर सड़कें बनाने के लिंए बजट में पैसे रखे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरे इलाके में इन तीन सालों के दौरान कोई भी सड़क नहीं बनाई गई । मेरे इलाके के 17 गांवों के लोग तो ऐसे हैं जिन्होने आज तक कोई सड़क नहीं देखी है । इन 17 गांवों में सड़कों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैं हर बार सैशन में कहना रहा हूं लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया । इन 17 गांवों से इन्द्री कस्बा सिर्फ 8, 7 या 10 किलोमीटर के फासले पर ही पड़ता है । लोर्गो की इन्द्री आने के

लिए संगोहा, रम्बा, संगोही और कमालपुर का रास्सा तय करते हुए आना पडता है । कमालपुर से इन्द्री कस्बा सिर्फ 6– 7 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है लेकिन कमालपुर में सड़क न होने की वजह से उन्हें 30 किलोमीटर घूम कर इन्द्री आना पड़ता हैं । इस बारे में मैं पी ०डब्ल्यू० डी ० मंत्री जी से प्रार्थना करूगा कि यदि इन 17 गावों में सड़कें बना दी जायें तो लोगों को इन्द्री आने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर से लेकर 6– 7 किलोमीटर तक का फासला तय करना पड़ेगा ।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से अब मै स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहूंगा । करनाल जनरल हस्पताल की बिल्डिग की हालत भी बहुत खराब है । जब बारिश होती है तो हस्पताल की सारी छत टपकने लग जाती है जिस की वजह से मरीज ठीक होने के बजाये और बीमार हो जाता है और मर जाता है । रूस बारे में मैंने पिछली बार भी हाउस में जिकर किया था कि इस होस्पिटल की बिल्डिंग बहुत पुरानी है इसलिए वहां पर हस्पताल के लिये एक नई बिल्डिंग बनाई जाये । स्पीकर साहब, करनाल के अन्दर एक मिली सैक्रैटेरियट बनाने के लिए मुख्य मत्री जी पत्थर रख कर आये थे । लगता है कि अब वह पत्थर धरा का धरा रह गया है और अब वह पत्थर भी गिरने को जा रहा है, मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना हए कि करनाल के अन्दर एक मिनी सचिवालय जल्दी से जल्दी बनाया जाए ।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमौड नं० 17 जो कृषि के बारे मे है, कहना चाहता हूं । करनाल का किसान और अम्बाले का किसान ज्यादा गन्ना पैदा करता है और उनकी जीविका गन्ना ही है । इसके साथ–साथ कुरूक्षेत्र जिले के आधा हिस्सा में भी गन्ना ही अधिक बोया जाता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जमुना के साथ लगते इलाके के लोगों की जीविका गन्ना ही है । स्पीकर साहब, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि करनाल शूगर मिल 1976 में लगा था 1976 से ही करनाल शूगर मिल के अन्दर किसानों का एक रुपया पर–क्विंटल के हिसाब से काटा जा रहा है, इस प्रकार से किसानों का एक रुपया पर–क्विटल के हिसाब से जो पैसा काटा आ रहा है. उसका आज कोई हिसाब किताब नहीं है । स्पीकर साहब, किसान को गन्ना–मिल में लाने के लिए 3 रुपये किराया भी देना पड़ता है और एक रुपया मिल वाले अलग से काट लेते है । सरकार कहती है कि हम किसानी को 21 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं । जैसा मइने बताया है कि तीन रुपये उनके किराये के कट गए और एक रुपया मिल वालों ने काट लिया तो इस प्रकार से एक क्विंटल पर 4– 5 रुपए कट जाने से किसानों को सिर्फ 16– 17 रुपये ही एक क्विटल पर मिल पाते हैं । इतना रुपया कम मिलने पर वहां के किसानों को काफी घाटा रहता है । इसी बात को लेकर वहां के किसानों में रोष है । इसलिए मैं चाहता हूं कि किसानों का जो एक रुपया 1976 से काटा जा रहा है, वह उनको वापिस मिलना

चाहिए ताकि किसान लोग उस पैसे से अपने बच्चों के पेट का पालन–पोषण कर सकें । .....

श्री अध्यक्ष : बी० डी० ओ० के बारे में जो कहा गया है, वह रिकार्ड न किया जाये ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, बी० डी० ओ० का लफज आप बेशक रिकार्ड न करवायें लेकिन जमीन खरीदी गई और मकान बनाया गया एं, वह तो आना चाहिए । (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : B. D. O. is a particular person who cannot defend himself in this House.

श्रीमती चन्द्रावती : .....

श्री लछमन सिंह : कम्बोज स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हु कि करनाल शुगर फैक्टरी में जो करोड़ों रुपया किसानों का काटा गया हूँ वह किसानों को वापिस कराया जाये । स्पीकर साहब, अब मैं यमुना नगर शूगर मिल की बात कहना चाहता हूं । पंजाव और यू ० पी० की सरकार अपने किसानों को यहां की अपेक्षा एक रुपया हुक क्विटल पर ज्यादा दे रही है । उसी एक रुपये की मांग के लिए यहां के किसानों ने आन्दोलन किया । मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि यहां पर गन्ने का रेट कम हो तो चीनी का रेट भी सस्ता होना चाहिए । जब यू ० पी० और पंजाब के किसानों को 22 रुपये क्विंटल के हिसाब से पैसा मिल रहा है

तो यहां के किसानों को भी उतना ही सरकार को देना चाहिए । इसी एक रुपये की खातिर यहां के किसानों ने आन्दोलन किया था । स्पीकर साहब, यमुना नगर में जो मिल लगा है उसके लिए गन्ना लाने के लिए वहां के –सिपाही, थानेदार, इन्सपैक्टर और डी०एस०पी ० ने खुद पुलियां उठा कर ट्रालियों में लादी हैं । यह सारा काम यमुना नगर शूगर मिल का जो मालिक डी० डी० पुरी है, उसके लिये किया गया है । जब किसान अपनी मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे थे तो पुलिस ने लाठियां चलाई और किसानों को पीटा । आन्दोलन के समय मुख्य मंत्री जी दादूपुर गाव में गए थे । जिस दिन मुख्य मंत्री जी दादूपुर गए थें उस समय भी किसान अपनी मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे थे । वहां पर मुख्य मंत्री जी के सामने चर्चा हुई थी कि किसान आन्दोलन इस लिए कर रहे हैं कि किसान एक रुपया पर–क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट बढवाना चाहते हैं । उस समय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था और अखवार में भी आ गया था कि मैं एक रुपया क्विटल के हिसाब से किसानों को दू गा ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज वाइंड अप ।

श्री लछमन सिंह कम्बोज : सर मैं जली ही खत्म कर रहा हूं ।.....

श्री अध्यक्ष : यह कुछ भी रिकार्ड पर नहीं आयेगा ।

चौधरी रोशन लाल आर्य : यदि उस दिन मुख्य मंत्री जी दादूपुर गए हों तो क्या आप अस्तीफा दे देंगे । (शोर एवं विघ्न)

श्री लछमन सिंह कम्बोज : जिस दिन मुख्य मंत्री जी आये थे उस दिन आप खुद किसानों को लेकर दादूपुर गए थे । (विघ्न) (घन्टी)

स्पीकर साहब, मैं सिर्फ यूक मिनट में ही समाप्त कर देता हूं । स्पीकर साहब, चन्द्रक गांव के लोगों को बारिश के दिनों में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है. क्योकि उस गांव के एक तरफ नाला लगता है और दूसरी तरफ जमुना लगती है । वहां पर पुल बनाने के लिए सरकार ने एक पत्थर भी रखा था और पुल को बनाने के लिए ईटें भी डाली गई थीं । अब वे ईटें तो उठा ली गई हैं और अब पत्थर धरा का धरा रह गया है । थेरी सरकार से प्रार्थना है कि चन्द्रो गांव में पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाये ताकि वहां के लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो । (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती : आन ए प्वायंट आफ आर्डर स्पीकर साहब, आप हर बात को जनरेलाइज करते हैं । अभी आपने आर्डर दे दिया कि यह बात रिकार्ड नहीं होगी । ठीक है आपका आर्डर सिर–माथे पर,– लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज अगर हाउस में बताई जाए, जैसे अभी हाउस में दो करोड़ की बात कही है उसको आप रिकार्ड पर आने दीजिए । अगर ये चीजे रिकार्ड नहीं होंगी तो

क्या रिकार्ड होगा? जो एलीनेशन मैम्बर साहब ने लगाये हैं, वे जरूर रिकार्ड होने चाहिएं ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन ।

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री जगदीश नेहरा) : स्पीकर साहब माननीय सदस्य ने बोलते हुए अपनी स्पीच मैं कहा..... ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष यह 'रिकार्ड न किया जागृ । प्लीज सिट डाउन । अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोलेगे ।

श्री बीरेन्द्र सिंह स्पीकर साहब, मेरा सुझाव है । फाइनेंस मिनिस्टर साहब आज न बोलें, कल इक्टठा ही जवाब दे दें तो अच्छा है । आज दो तीन मैम्बर और बोलना चाहते हैं, इनको बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष : इनको कल टाईम दे देंगे । (व्यवधान)

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, मेरी आपसे एक सबमिशन है । आप मुझे बोलने दें, फाइनेंस मिनिस्टर कल इकटठा ही जवाब दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, प्रोसीजर ऐसा नहीं है । आज की डिमांडज प्रोसीजर के मुताबिक पास हो जानी चाहिए । अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोलेगे ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : आन ए प्यायंट आफ आडर्र सर । स्पीकर साहब, मेरे माननीय दोस्त ने एक बात कही, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपकी इजाजतसे अर्ज कहना चाहता हूं । किसानो का एक डैपुटेशन चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया था. (व्यवधान)

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, आप मुझे बोलने दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किताब 'सिंह जी, आप बैठ जाइए, आप को कल टाईम दूंगा ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जब जगाधरी मैं किसानों का एजीटेशन चरा रहा था तो बहुत से किसान इकटठे होकर मेरे पास आये थे और मैं उनका डंपुटेशन लेकर मुख्य मन्त्री जी के पास गया था । मेरी मौजूदगी में डैपुटेशन के साथ बातचीते हुई थी । मुख्य मन्त्री जी नैं कोई ऐसा विश्वास नहीं दिलाया था कि गन्ने की कीमत एक रुपया पर 1 क्विंटल बढायेंगे । जो बात आनरेबल मैम्बर कह रहे हैं, यह बिल्कुल निरा–बार हैं और बिल्कूल गलत है । (व्यवधान)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, डिनर वाली बात थी ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाईए । अब फाडनेन्स मिनिस्टर साहब बोलेंगे ।

वित्त मन्त्री (श्री सागर राम गुप्ता) : स्पीकर साहब, पहले मैं डिनर वाली बात बता देता हूं । तीन दिन के लिए डिनर का इन्तजाम कर दिया है । आज सी ० एम० साहब दे रहे हैं, कल गवर्नर साहब और 29 तारीख को स्पीकर साहब आप दे रहे हैं । 28 तारीख को मैं डिनर दूगा. आप चिन्ता न करें । (व्यवधान)

श्री मनफूल सिंह' : स्पीकर साहब, मुझे 'बोलने दीजिए कल मुझे शायद टाईम नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए ।

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, गरिमापूर्ण सदन के सामने सात डिसाड्ज पर बहस चल रही थी । ये डिमांड्ज हैं रेवेन्यू, बिल्डिंगज एंड रोड्ड़, इरीगेशन, एग्रीकल्चर, ऐनिमल हसबेंडरी, कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट और कोआप्रेशन । स्पीकर साहब, मुझे बडी खुशी हुई कि माननीय सदस्यों ने एग्रीकल्चर, इरीगेशन, बिल्डिंग एंड रोड्ज और रैवेन्यू के बारे में अपनी अपनी बाते कहीं, कुछ सुझाव दिए और अपनी–अपनी मांगे भी सदन के सामने रखी । जैसा कि आपने देखा है, स्वीकर साहब, दो–तीन सद्रों के ऊपर माननीय सदस्यों ने कोई खास बात नहीं कहीं । ऐनिमल हसवैंडरी के बारे में शायद कोई बात नहीं हुई और को–आप्रेशन डिपार्टमैंट ओर कम्युनिटी डिवैल्पमैंट पर कुछ माननीय सदस्यों ने पच्छिम रिमार्क्स किए । सीकर साहब, जैसा कि मैं कल अर्ज कर रहा था, आज भी उसी बात को रिपीट करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से

बजट बनाकर सदन में पेश किया हुए । क्य साल किसी भी माननीय उदस्थ को इन मांगों को पास करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए । मइं इस बात को मानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों के हल्कों –में मुखतलिफ किस्म की कमियां हैं । कहीं सडकों की कमी है, कहीं नहर की कमी है, कहीं बिजली की कमी है । लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रदेश डिवैल्प कर रहा हो, उसमें कुछ इस प्रकार की कमियां रह ही जाती हैं, हम इन कमियों को आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि अनि बारने सालों में हरियाणा बहुत आगे बढ़ेगा चूंकि समय की कमी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इधर–उबर की बात नही करूंगा । मैम्बर साहेबान ने जो बातें डायरैक्ट तौर पर कहो हैं, मैं उन्ही पर आना चाहता हूं । ठाकुर बहादुर सिंह जी ने जिक्र किया था कि किसानो पर से खर्चा कम किया जाए । इन के सुझाव से किसी भो रचनात्मक सरकार को राय मिल्न नहीं हो सकती । इनकी सूचना के लिए मैं अर्ज करना चहता हूं कि हरियाणा सरकार किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इनपुटस पर, यानी जो फटिलाईजर्ज हैं, बीज पैं या और चीजें कुए, जो किसान को मिलती है, इन पर काफी माला में सरकार सबसिडी दे रही है । इस सबसिडी के लिए 10 करोड़ साढ़े 42 लाख रुपए के करीब सरकार ने प्रावधान किया है । कुछ सदस्यों ने कहा कि शायद कुछ मुद्दों पर यह सबसिडी एक्चुअली किसान के पास नहीं पहुंचती । स्पीकर साहब, हो सकता है न पहुंचती हो । मैं इस बात से इंकार नहीं करता, क्योंकि एग्रोकल्चर एक बहुत बड़ा डिपार्टमैंट

हए और सारे हरियाणा में फैला हुआ है । अगर कहीं कोई पार्टिकुलर शिकायत हो तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस शिकायत पर जरूर एक्शन लेंगे । अगर कोई पार्टिकुलर शिकायत होगी और सरकार के नोटिस में लायेंगे तो निश्चित तौर पर इन्कवायरी करेंगे । जो भी सरकारी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसका पूरा इलाज करेंगे । स्पीकर साहव, ट्रैक्टर के बारे में एक बात कल कही थी कि ट्रैक्टर्ज सस्ते कर दे । स्पीकर साहब, सस्ता करने के बारे में एक अर्ज कर दूं कि हरियाणा एक वाहिद स्टेट है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर श्री सागर राम जी कह रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर शिकायत आयेगी तो वे फौरन एक्शन लेंगे । इनके पास और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास एक शिकायत पहुंची है जिस में जींद के 4 ए० डी ० ओज ० और एक एस० डी० ओ० इन्वालवड हैं । यह एक फर्टिलाइजर स्कैंडल है । इस केस में ए० डी ० ओज ० को तो सस्पैंड कर दिया गया है लेकिन एस ० डी ० ओ ० को नहीं किया है क्योंकि वह बड़ा आफिसर है, वह कहीं पहुंच गया होगा । आज वह दनदना कर बाहर घूम रहा है । रिपोर्ट के अनुसार उस पर एलीगेशन लगे हुए हैं । क्या ये उस के खिलाफ एक्शन लेंगे?

श्री सागर राम गुप्ता : जो रिपोर्ट आई है, उस पर निश्चित तौर पर जांच करेगे ओर जो भी कार्यवाही कायदे के अनुसार उचित होगी, जरूर करेंगे ।

श्री किताब सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, 9 सितम्बर को कृषि निदेशक ने एक लाइसैसं कैंसिल कर दिया और 19–11–84 को कृषि आयुक्त ने इसको स्टे दे दिया । इस फर्म का सैम्पल 11– 11–84 को फेल हो गया था । यह फर्म 12–32–0 और 12– 32– 18 एन.पी.के. खाद बनाती है । इन दोनों के सैम्पल फेल हो गये थे, इस बिना पर इस फर्म का लाइसेस कैसल कर दिया था, लेकिन इसको स्टे मिल गया । इस फर्म के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हु ई और वह फर्म आज भी बाद बना रही है । क्या इस केस की इक्वायरी करवायेंगे? (व्यवधान)

श्री अष्यक्ष : आप–बैठ जाईए ।

श्री सागर राम गुप्ता : स्पकिर साहब, मैं ट्रैक्टर्ज के बारे में अर्ज कर रहा था । यह हमारी खुशकिस्मती है कि हरियाणा स्टेट में ट्रैक्टर्ज बहुत ज्यादा पैदा होते हैं । ट्रैक्टर्ज अनाने की चार कम्पनियां स्टेट में लोकेटिड हैं एस्कोर्ट, फोर्ड, आयमर और एच० एम ० टी ० ।

स्पीकर साहब, माननीय सदस्यो को मै यह भी अर्ज कर दूं कि ट्रैक्टज के ऊपर सेल्ज टैक्स की दर इसलिए कम रखी है

ताकि ट्रैक्टर्ज किसानों को सस्ते मिल सकें । ट्रैक्टजं के ऊपर केवल 4 परसैट सेल्ज टैक्स रखा हुआ है जबकि आम सेल्ज टैक्स की दर 10 परसैंट है । स्पीकर साहव, यदि माननीय सदस्य और भी कोई अच्छे सुझाव देंगे जिससे ट्रैक्टर्ज सस्ते हो सकते हों तो निश्चित तौर पर उन पर विचार किया जाएगा ।

स्पीकर साहब, कुछ माननीय सदस्यों ने बाजरे के बीज की बात यहां को औक बीज समय पर नहीं मिला ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, मैं एक सूझाव देना चाहता हूं । उससे स्टेट का रेयेन्यू बढेगा । वित मंत्री जी एक साल की फिगर्ज रजिस्ट्रींग अथोरिटीज से मंगवा कर देख ले । उससे इनको यह पता लगेगा कि एक भी ट्रक की चौसी हरियाणा में सेल नहीं हुई है बल्कि सारी गोआ, दमन और दीयू से आई हैं । (विघ्न) वहां सेल्ज टैक्स बहुत कम है जबकि हरियाणा में बहुत ज्यादा है । इससे सरकार को रैवेन्यू का काफी हर्जा हुआ है । क्या सरकार ट्रक की चौसीज पर भी सेल्ज टैक्स की दर कम करने पर विचार करेगी ताकि बाहर के डीलर्ज की बजाए हरियाणा के डीलर्ज को काम मिले और सरकार को भी फायदा हो?

श्री सायर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, इस बारे में मैं इतना ही अर्ज कर दूं कि नोर्दर्न जोन में जो कम्पिटिशन होता है हम केवल उसको ध्यान में रखते हैं । गोआ में क्या स्थिति है इस

बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह तो साउथ बैस्ट में पटु गया । नोदंर्न जोन में तो हम त्तकी कोशिश करते हैं कि आपस में किसी किस्म का फर्क न हो और जहां तक हो सके युनिफामिटी पड़े ।

स्पीकर साहब, मैं बाजरे के बीज की बात कह रहा था । एक सदस्य ने कहा कि बाजरे का बीज समय पर नहीं मिला । एक सदस्य ने यह कहा कि बीच मंहगा मिला । स्पीकर साहब, बाजरे का बीज हरियाणा में पैदा नही होता । बाजरे का बीज गुजरात से लाना पड़ता है जहां फसल अप्रैल में कटती है । पिछली दफा बीज आने में लेट हो गया । उसका कारण यह हुआ कि वहां जो सर्टिफाइंग एजेन्सी थी उसने सर्टिफिकेशन में काफी टाईम लगा दिया लेकिन अब की दफा सरकार ने ऐसे पग उठाए हैं कि सब जगह बीज समय पर मिलेगा और कोई दिक्कत फार्मर्ज को नहीं आएगी । राव निहाल सिंह जी ने भी बीज के बारे में एक बात कही थी । इन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं । स्पीकर साहब, बीज पर सबसिडी देने के लिए इस सात्र 41.46 लाख रुपये का प्रावधान है । हम कोशिश करेंगे कि फार्मर्ज को बीज ज्यादा से ज्यादा सस्ता दिया जाए । फर्टिलाइजर के ऊपर कोई सबसिडी देने का प्रावधान अभी नहीं है । अगले सालों मैं देखेंगे अगर सरकार के पास रिसोर्सिज की पोजिशन ऐसी बनी तो अवश्य देने की कोशिश करेंगे । स्पीकर साहब, यह कहना गलत है कि किसान जब डीजल इन्जन या स्प्रिंकलर सेट लेना चाहते हैं तो

उन्हें पार्टिकुलर बैड लेने के लिए मजबूर किया जाता है । इनको इस बारे में कोई गलतफहमी है । इस बात की कोई रिस्ट्रीम्क्शन नहीं है । कोई पार्टिकुलर इंस्टांस ये बता दे, हम देख लेंगे ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : स्पीकर साहब, यह पेमैंट थर्ड पार्टी 'को होती है । अगर पेमैंट सीधी किसान को कर दी जाए तो बेहतर होगा ।

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, थर्ड पार्टी को पेमैंट इसलिए की जाती है ताकि किसान को सही चीज सप्लाई हो और अगर उसमें बाद में कोई कमी निकले तो हम सप्लायर को मजबूर कर सके कि उसे ठीक किया जाए । असर किसान को डायेरक्ट पेमैंट कर दें और मार्किट में उसने धोखेबाज आदमी से चीज खरीद ली तथा बाद में उसे वापस नहीं किया तो इस पेमैंट का सारा मूद्दा खत्म हो जाता है ।

चौधरी नर सिंह ढांडा : स्पीकर साहब, ये थर्ड पार्टी को पेमैंट देते हैं । उसमें होता ऐसे है कि जिस लैड डिवैल्पमैंट बैक से लोन लेले हैं वह पार्टिकुलर दुकान निश्चित कर देता है क्योंकि उससे कमीशन ली जाती है । इससे किसान उस पाटिकुलर दुकान से चीज लेने के लिए बाउन्ड डाऊन हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : आप यह भी तो देखें कि जिस फर्म को थर्ड पार्टी पेमैटै करते हैं, अगर वह माल गलत देती है और उसे

ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो उस फर्म को कितना लौस होगा । हर मामले में आप इस तरह की बात न किया करें ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, थर्ड पार्टी पेमैंट के बारे में मैं एक अर्ज करना चाहता हूं । नारनौल में थ्रैशर्ज के लिए लोन दिया गया है । थर्ड पार्टी पेमैंट कर दी गई है लेकिन लोगों को न तो थ्रैशर्ज मित्ने और न ही पैसा मिला । ऐसे कोई 30–40 केसिज हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे लिस्ट दे देना । I will get it examined.

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक ऐंग्रीक्ल्चरिस्टस को, फार्मर्ज को राहत देने का सवाल है, हरियाणा सरकार बहुत कुछ कर रही हैं । मैंने कल भी कहा था कि अगले साल तकरीबन 80 परसैट बजट फार्मर्ज की बहबूदी के लिए निश्चित किया गया है । यह हो सकता है कि कही किसी स्कीम में छोटी मोटी कमी हो । माननीय सदस्य उन्हें यदि नोटिस में लाएंगे तौ निश्चित तौर पर हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे ।

स्पीकर साहब, इरीगेशन एंड पावर के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं । इस मुद्दे पर बोलते हुए सरदार लछमन सिंह जी ने एक बात कही थी कि इरीगेशन पोटैशियल को बड़ाने के लिए कालका और छछरौली के तराई के इलाके में छोटे–छोटे बंध

बनाये जाएं । इनका यह सुझाव बहुत अच्छा है । मैं उनकी सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि कृषि विभाग ने ऐसे छोटे–छोटे वध निर्माण की योजना बनाई हुई है । इस समय लगभग 92 स्कीमों पर काम चल रहा है जिनसे 29, 900 हैक्टेयर भूमि को पानी मिलने की सम्भावना है । अगले वर्ष 139 ऐसे और स्पौर्टस पर जहा का सर्वे कर लिया गया हुं बंध बनाए जाएंगे । 28 नई वाटर साईटस पर काम किया जाएगा जिससे 1० हजारे हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : आप कितना टाईम और लेंमें ।

श्री सागर राम गुप्ता : तकरीबन 15– 20 मिनट और लूंगा । (विध्न)

आवाजें : केवल पांच मिनट में ही खत्म कर दीजिए ।

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों की इच्छा है कि मै पांच मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दू ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है मैं 10 मिनट के लिए हाउस का टाईम बढ़ाता हूं ।

वर्ष 1985– 86 के बजट की डिमांड्ज कार फार पर चर्चा तथा रक्तदान (पुनरारम्भ)

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, मोटी–मोटी स्कीम्ज के बारे में तो इन्होंने पड़ लिया होगा क्योंकि बजट में सारी डिटेल्ज दी हुई हैं लेकिन फिर भी कुछेक बातें मैं माननीय सदस्यों को बता देता हूं । स्पीकर साहब, मेजर–मीडियम इरीगेशन के लिए 118.12 करोड़ रुपये का प्रावधान है । इसमें एस० वाई० एल० के शिरा 70 करोड़ रुपये है । मौड़ेनाईजेशन आफ प्रोजैक्टस तथा लाईनिंग के लिए 26 करोड़ रुपये है । अदर स्कीम्ज जैसे जे ० एल०एन०, लोहारू ,सिबानी, वैखंन जमुना कैनाल आदि के लिए 22.12 करोड़ रुपये रखे गये है । नई स्कीम्ज जैसे लाडवा नलवी, मेवात ओर पटौदी के लिए 308 लाख रुपये रखे गये हैं । ड्रेनेज और क्यड कंट्रोल के लिए 14.07 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है । इससे ड्रेनेज की कैपेसिटी इनक्रीज की जायेगी । ड्रेन नं ० 8. पुन्डरीं ट्रेन और छुड़ानी ड्रेन के लिए 235 लाख रुपये रखे गये है । लिक ड्रैन्ज के लिए 414 लाख रुपये का प्रावधान है । ऐमबैंकमैंट औफ रिजर्व के लिए 55 लाख का प्रावधान है । मसानी बैरेज के लिए 510 लाख का प्रावधान है । एम०आई० टी०सी० का एक संपरेट मेंटेनैस डिबिजन बनाया गया है जो इस काम को अच्छी तरह से करेगा ।

स्पीकर साहब, फामर्ज और अफसर को एजुकेट करने के लिए सैमीनार कर रहे है । एम० आई० टी०सी०भी जीन्द और हिसार में अफसरों और फारमर्ज को ऐजुकेट करने के लिए सेमीनार कर रही है । पब्लिक ग्रिवेन्सिज को खत्म करने को

हमारी पूरी कोशिश है । स्पीकर साहब, सड्कों के बारे में भी बहुत से मैम्बरान ने जिक्र किया । सड़कों का काम करने की हमने काफी कोशिश की हैलेकिन सड़कों का काम बहुत मंहगा है । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने काफी काम किया है । नवम्बर, 1986 में केवल 5100 किलोमीटर सड़कें थीं और आज के दिन 19888 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं इसलिए यह कोई कम काम नहीं है । आप दूसरी स्टेट्स का मुकाबला करिए । इनमें नैशनल हाइंवे भी शामिल है जो 655 कि० मी ० है और 3100 किलोमीटर स्टेट हाई–बे है । मैं मैम्बरान की सूचना के लिए यह बताना चाहूंगा कि आठवें फाईनैन्स कमीशन ने राज्यों की सड्कों की मैंटीनैस के लिए जो स्टैन्डर्ड प्रैसक्राईब किया है उसके अनुसार 24 हजार रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च आता है लेकिन हरियाणा सरकार मैन्टिमैसं पर छः हजार रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च कर रही हैं । देहातों में जो सड़कें बहुत खराब ऐं उनकी रिपेयर करवाई जाएगी । उन्हें प्रायरिटी केसिज पर रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे । स्पीकर साहब, अगर हरियाणा सरकार काम नहीं करती तो ये 98 प्रतिशत हरियाणा के एरिया कैसे सड़कों से कनैक्ट होते? स्कूलों, हस्पतालों और वैट्रनरी डिस्पैन्सरीज के लिए भी गांव में लिंक रोड की बात कही गई हए । स्पीकर साहब, आने वाले साल में निश्चित रूप से सड़कें बनायी जायेंगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा । जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि शहरों की सड़कें जो म्यूनिस्पिल कमेटी के एरिया में हउ और

जिनकी हालत ठीक नहीं हैं उन्हें पी० डब्लयू ० डी० द्वारा मुरम्मत करवाने के बारे में सोच रहे हैं ।

श्रीमती बसन्ती देवी : स्पीकर साहब, ये स्पीड ब्रेकर बनाये जाते हैं लेकिन कुछ दिनों के वाद फिर तोड़ दिए जाते हैं । इसका क्या कारण है? '

श्री सागर राम गुप्ता : लाकर साहब, मैं एक दो बातें रैवेन्यू डिपार्टमैंट कें बारे में भी कहना चाहता हूं । यहां पर यह एलिनेशन लगाया है कि स्माल सेविंग का पैसा अफसर साहेबान जबरदस्ती इकट्ठा करते हैं । मैं उनकी इस बात हूंको रिफ्यूट करता हूं । यह गलत बात है । हम कानून के हिसाब से स्माल सेविंग का पैसा लेते है किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते । रैडक्रास के लिए जो लोग चन्दा देते है वह गरीबों के काम– आता है । कोई भी तहसीलदार रजिस्ट्री का पैसा नहीं लेता है? । अगर रजिस्ट्री के टाईम पर कोई आदमी दान दे दे तो कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई आदमी बीस–तीस हजार रुपये की रजिस्ट्री करवा रहा है, और वह थोड़ा बहुत दान दे दे तो कोई बुरी बात नहीं है । उसके लिए बाकायदा टिकट दिए जाते हैं । यह कहना कि तहसीलदार बीस–तीस रुपये लेकर जेब में डाल लेते हैं, यह गलत बात है। बाकायदा टिकट दिए जाते हैं । यहां पर म्यूटेशन की भी बात कही गई । मेरी समझ में नहीं आता कि इन्हें गैर–जिम्मेदाराना बात कहने की आदत क्यों पड़ गई है । अगर म्यूटेशन या गिरदावरी में गड़बड़ी की कोई स्पैसिफिक कम्पलेन्ट

नोटिस में लायेंगें तो सरकार जरूर कार्यवाही करेगी । इन शब्दों के साथ मैं हाउस से कहूंगा कि इन डिमान्डज की पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : अब मैं वेरियस डिमान्डज को वोटिंग के लिए रखता हूं ।

Question is—

That a sum not exceeding Rs. 7,62,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray Charges that will come in the course of payment for the year. 1935-36 in respect of charges. under Deal and No. 4-Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 31,30,80,000 for revenue expenditure and Rs. 38,44,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1985-86 in respect of charges under Demand No. 8 Buildings and Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Questions is—

That a sum not exceeding Rs. 74,94,49,00) for revenue expenditure and Rs. 1,37,82,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1985-86 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 43,33,26,000 for revenue expenditure and Rs. 4,00,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1985-86 in respect of charges wider Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Its. 13,46,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1935-86 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Its. 34,89,37,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1985-86 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 5,93,84,000 for revenue expenditure and Rs. 5,52,52,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

1935-83 in respect of charges under Demand No. 22 Cooperation.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है ।

13.37 बजे

(तत्पश्चात सदन बुधवार, दिनांक 27– 3– 1985 को प्रातः 9– 30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)